नौकरशाही
औचित्य पर सवाल

उत्तर प्रदेश
ब्राह्मण वोट की मांग

लोक जनशक्ति पार्टी
चिराग के घर में आग

इंडिया टुडे
30 जून, 2021
40 रुपए

कोविड का लंबा साया

डॉक्टरों की चेतावनीः संक्रमण दूर होने के बाद उसके असर
यानी लांग कोविड से सेहत को कई तरह का जोखिम

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22
www.indiatodayhindi.in
OC

VISIT…

LANZAROTE

Caliente.COM

Only Books Magazine

देश का नं. 1
हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

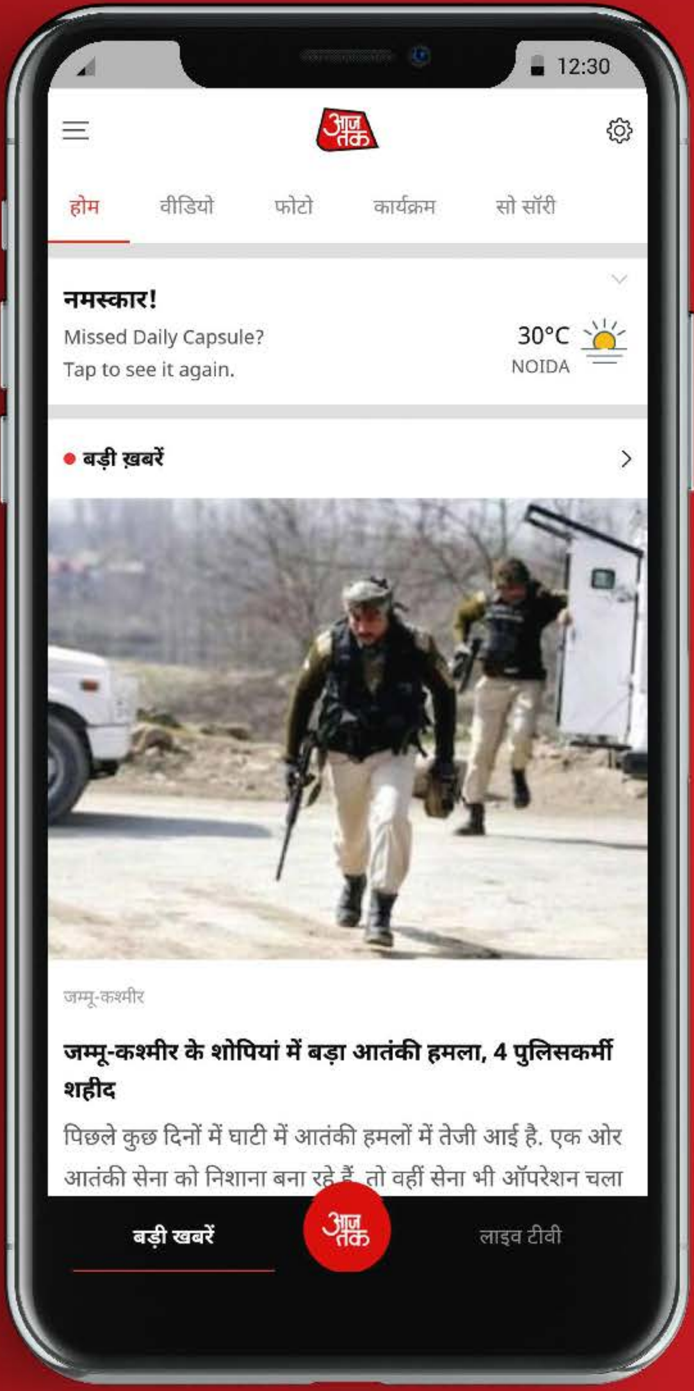
12:30
होम
वीडियो
फोटो
कार्यक्रम
सो सॉरी
नमस्कार!
Missed Daily Capsule?
Tap to see it again.
30°C
NOIDA
बड़ी ख़बरें
जम्मू-कश्मीर
बड़ी खबरें
लाइव टीवी

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बड़ा आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मी शहीद

पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी हमलों में तेजी आई है. एक ओर आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सेना भी ऑपरेशन चला

IndiaContent

SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE

Only Books Magazine

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41

INDIA TODAY

LIVE

TOP NEWS VIDEOS PROGRAMMES

TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

Only Books Magazine

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

प्रधान संपादक की कलम से

इस साल दिल को सुकून देने वाले ऐसे ग्राफ देखने को कम ही मिले हैं, जितना कि वह एक ग्राफ जो भारत में कोविड-19 के मामलों में तेज गिरावट को दिखा रहा था. मई में एक समय ऐसा था जब संक्रमण के रोज 4,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे. अब उनकी दैनिक संख्या 1,00,000 से कम पर आ गई है. 15 जून को दर्ज मामलों की गिनती 60,471 थी, जो कि बीते 75 दिनों में दैनिक मामलों के हिसाब से सबसे कम थी. 7 मई को सबसे ज्यादा सामने आए 4,06,901 मामलों के संक्रमितों की तादाद में पूरे 85 फीसद की कमी आई है.

भारत में महामारी की शुरुआत से अब तक 2.9 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2.8 करोड़ तो ठीक हो चुके हैं. फिर भी, जैसा कि पहली लहर ने पाठ पढ़ाया है, कोविड-19 को लेकर हमें अपनी सतर्कता में जरा भी कमी नहीं आनी देनी चाहिए. खास तौर पर इसलिए भी कि हम इस वायरस की वजह से नई किस्म की परेशानियां पैदा होते देख रहे हैं.

Only Books Magazine

इंडिया टुडे
कोविड विजेता

24 जून, 2020 का आवरण

इंडिया टुडे
कब थमेगा कहर?

26 मई, 2021 का आवरण

पहले तो हर किसी ने कोविड-19 को एक सामान्य किस्म का बुखार मानकर खारिज कर दिया था. एक ऐसा बुखार जिससे हम बगैर किन्हीं साइड इफेक्ट के उबर सकते हैं. पर अब हम अच्छी तरह जान गए हैं कि यह सच से बिल्कुल परे है.

आखिर इसके सही-सही लक्षण क्या हैं? इसके अनुमान न तो विशेषज्ञ लगा पा रहे हैं और न ही मरीज. दोनों को इसने हैरानी में डाला हुआ है. मगर बीते डेढ़ साल के दौरान शोधकर्ताओं ने इसका पर्याप्त डेटा जुटाया है जो इस बात की तस्दीक करता है कि बहुत सारे संक्रमित लोग 14 दिन (शरीर को इस वायरस के असर से उबरने में अमूमन लगने वाला समय) बाद भी इसके लक्षण अनुभव करते रहते हैं. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के मई 2021 के एक अध्ययन के मुताबिक, मध्यम या तीव्र कोविड संक्रमण वाले 70 फीसद मरीजों को ठीक होने के महीनों बाद तक किस्म-किस्म के लक्षण अनुभव होते रहे.

इसे लांग कोविड के नाम से जाना जाता है. इसके लक्षणों में बदन दर्द, बुखार, थकान, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट, आवाज में बदलाव और यहां तक कि याददाश्त में चूक भी शामिल है. एक डॉक्टर ने हमें बताया कि किस तरह उनके 80 से 90 फीसद के बीच मरीज ठीक होने के बाद भी सूखी खांसी, कमजोरी और बार-बार पानी की कमी होने की प्रवृत्ति से ग्रस्त रहे. डॉक्टरों के मुताबिक, दूसरी और ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि वायरस शरीर के हर प्रमुख अंग पर हमला कर रहा है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वायरस एसीई2 (एंजियोटेंसिन- कन्वर्टिंग एंजाइम) रिसेप्टर से चिपक जाता है, जो फेफड़ों, दिल, रक्त वाहिकाओं, किडनी, लीवर और पाचन तंत्र सहित शरीर के तकरीबन सभी अंगों में मौजूद है. एसीई2 एक एंजाइम है जो ज्यादा बड़े एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन के टुकड़े करके छोटे-छोटे प्रोटीन उत्पन्न करता है, जो फिर कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करते हैं. वायरस इन्हीं एसीई2 रिसेप्टरों का दरवाजों की तरह इस्तेमाल करता है और शरीर में दाखिल होकर उसे संक्रमित कर देता है.

हृदय और फेफड़ों के बाद मस्तिष्क और किडनी जोखिम से घिरे दो सबसे अहम अंग हैं. कोविड मरीजों के पोस्टमॉर्टम से पता चला कि इन दोनों ही अंगों में खून के थक्के चले गए थे.

इनफ्लेमेशन और थ्रोंबोसिस दो अन्य 'खामोश हत्यारे' हैं जो ऊपरी तौर पर कोविड से उबर चुके मरीजों पर हमला बोल सकते हैं. ये वायरस के खिलाफ शरीर के स्वाभाविक रक्षाकवच हैं, लेकिन इन्हें संक्रमण के बाद भी शरीर में टिके रहने दिया जाए तो ये कहर बरपा सकते हैं.

लांग कोविड को औपचारिक तौर पर पोस्ट-कोविड सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है. इसके बारे में राष्ट्रीय डेटा या इसके लक्षणों और इसकी संभावना बढ़ाने वाले जोखिम के कारकों की जानकारी मौजूद नहीं है. ऐसे में देश भर के कोविड वार्डों के डॉक्टर डरावनी तस्वीर पेश करते हैं. एसोसिएट एडिटर सोनाली आचार्जी ने देश भर के कई ऐसे डॉक्टरों से बात की और हमारी आवरण कथा 'कोविड का लंबा साया' का ताना-बाना बुना.

लांग कोविड फिर इस बात की तस्दीक करता है कि यह वायरस किस कदर जानलेवा है और यह भी कि तीव्र संक्रमण के खिलाफ एकमात्र कवच वैक्सीन ही हैं. इसलिए जरूरत इस बात की है कि सरकार इस साल के अंत तक भारत के 90 करोड़ वयस्क लोगों को टीके लगाने के अपने फोकस में जरा भी कमी न आने दे.

लांग कोविड के मामलों के कहीं ज्यादा गहरे अध्ययन और बेहतर समझ की जरूरत है. ढीठ प्रेत की तरह कोविड-19 उन्हीं लोगों के पीछे पड़ता है जो मानते हैं कि वे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं. डॉक्टरों को भी इसके बारे में संवेदनशील बनाना होगा. इसके लिए लगातार इलाज की जरूरत होती है. मसलन, दिल्ली में कोविड से ठीक हो चुके मरीजों के इलाज के लिए एक समर्पित अस्पताल है. खुशकिस्मती से लांग कोविड को स्वस्थ खान-पान और नियमित मेडिकल जांच से परास्त किया जा सकता है. इस वायरस से निबटने के मामले में आत्मसंतोष का विकल्प बिल्कुल है ही नहीं. अब जैसा कि हमें पता चल रहा है, यह इसके बाद के नतीजों पर भी इतना ही लागू होता है. जाहिर है, यह उसी वक्त खत्म नहीं हो जाता जब आपको लगता है कि अब तो यह गया, खत्म हुआ. सौ की सीधी बात, अगर आपको कोरोना हुआ था, तो अब भी जरा सावधान ही रहिएगा.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादकः अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सनः कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः मनोज शर्मा
एडिटरः अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटरः मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरोः आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनरः असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशरः अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजरः जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजरः इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजरः सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजरः पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्षः 35; अंकः 31; 24-30 जून, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजेंः** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवाः** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोनः दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्सः (0120) 4078080. ई-मेलः wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालयः** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-66063355 फैक्सः 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालयः एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**

संपादकः राज चेंगप्पा

भीतर

सुर्खियां

पश्चिम बंगालः खामोश! खेल जारी है
पेज 5

अर्थात्ः साबुत बचा न कोय
पेज 19

फुरसत

सोशल मीडियाः कविता का समां
पेज 56

सवाल-जवाब/छन्नूलाल मिश्रः शेष आकांक्षा गुरुकुल की
पेज 58

22

आवरण कथा

लांग कोविड का लंबा साया

डॉक्टर अब लंबे खिंचते पोस्ट कोविड सिंड्रोम को लेकर सावधान कर रहे हैं जो एक मरीज को वायरस से निजात पाने के अर्से बाद भी खतरे में डाल सकता है

फोटोः बंदीप सिंह; डिजिटल इमेजिंगः अमरजीत सिंह नागी

नौकरशाही

38 **औचित्य का सवाल**

आचरण संहिताओं से प्रतिबद्ध रहकर ही नेताओं के नजले से बचाव मुमकिन

विपक्ष

8 **नए मोर्चे का तिलिस्म**

ममता बनर्जी और शरद पवार मिलकर एक नए गठजोड़ की तैयारी में!

खास रपट

32 **ब्राह्मण वोटों पर नजर**

यूपी में सियासी दल ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए बेताब

यदाद्रि मंदिर

50 **आस्था का नया स्थान**

तेलंगाना में 1,800 करोड़ रु. में तिरुमला को टक्कर देता मंदिर तैयार

इंडिया टुडे
इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 **पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.**
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरणः **नीलांजन दास**

पाठकों के लिए सूचनाः कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

Only Books Magazine

विपक्षः नए मोर्चे
का तिलिस्म
पेज 8

दलित वोटरः
पंजाब में सभी डालें डोरा
पेज 10

सुर्खियां

सीएएः
अल्पसंख्यक रिपोर्ट
पेज 18

आओ इधर
11 जून को टीएमसी में मुकुल रॉय का स्वागत करते अभिषेक बनर्जी

देवज्योति चक्रवर्ती

पश्चिम बंगाल

Only Books Magazine

खामोश! खेल जारी है

रोमिता दत्ता

भाजपा नेता पिछले हफ्ते खुश थे कि कांग्रेस के जितिन प्रसाद उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उन्हें इसका गुमान नहीं था कि यही कुछ पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी के साथ भी हो रहा था. उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में लौट आए. रॉय के 11 जून को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक से मिलने के कुछ घंटे पहले इसकी जानकारी पाकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इस पार्टी बदल को रोकने की व्यर्थ कोशिश की, जिसने एक महीने पहले ही राज्य में अपमानजनक चुनावी हार के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया.

रॉय नवंबर 2017 में भाजपा में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कभी भाजपा में घर जैसा अपनापन महसूस नहीं किया. लगता नहीं है कि पार्टी में उनकी बढ़ती बेचैनी पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा. उन पर प्रतिद्वंद्वी सहयोगियों की तिरक्षी नजर थी और ममता के साथ दशकों पुराने जुड़ाव के कारण वे संदिग्ध नजरें दूर करने में असमर्थ थे. एक समय वे दीदी के सबसे भरोसेमंद और टीएमसी के दूसरे शीर्ष नेता थे, जब तक पार्टी में अभिषेक के उदय पर भारी मतभेद सामने नहीं आए.

भाजपा में रॉय को बहुत देर से मान्यता मिली. 2019 के आम चुनाव (42 में से 18 लोकसभा सीटें और 40 प्रतिशत वोट शेयर) में रॉय की मदद से शानदार प्रदर्शन के बावजूद

देबज्योति चक्रवर्ती

ताकत का प्रदर्शन
14 जून को शुभेंदु अधिकारी की अगुआई में भाजपा के 50 विधायकों ने चुनाव बाद हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ज्ञापन सौंपा

पार्टी को उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से पुरस्कृत करने में एक साल से अधिक समय लगा. वह भी तब जब रॉय ने नई दिल्ली में अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के होर्डिंग्स को हटाकर अपना विरोध दर्ज कराया था. भाजपा में अपनी संक्षिप्त पारी के अधिकांश समय वे चुनाव प्रबंधक ही बने रहे, ऐसे नेता, जिन्हें शाह के शब्दों में, ‘‘ममता को उखाड़ फेंकने’’ के लिए लाया गया था. भाजपा में रॉय के एक करीबी कहते हैं, ‘‘दादा (रॉय) को भाजपा में कभी घर जैसा महसूस नहीं हुआ. पार्टी के राज्य मुख्यालय (कोलकाता) में, उनके पास समर्थकों से मिलने के लिए उचित कमरा भी नहीं था. जब दादा निजी बैठकें करते थे, तो वे सीढ़ियों पर बैठकर उनका इंतजार करते थे.’’

शुरुआती संकेत

सारदा और नारद घोटालों में केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी थीं, इसलिए भाजपा ने शायद यह मान लिया था कि रॉय कभी भी पार्टी बदल नहीं कर पाएंगे. भाजपा संकेतों को पढ़ने में साफ नाकाम रही. जैसे, 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की 125वीं जयंती समारोह के दौरान रॉय और ममता के बीच चाय के दौरान मुलाकात हुई थी. ममता ने रॉय की सेहत का हालचाल पूछा, जबकि महज महीने भर पहले भाजपा में गए शुभेंदु अधिकारी की ओर देखा तक नहीं.

भाजपा की विधानसभा चुनाव की रणनीति से दूर रहे रॉय को शाह का वह निर्देश भी नहीं भाया था कि वे कृष्णनगर उत्तर सीट से चुनाव लड़ें. तीन दशकों के राजनैतिक करियर में वे दो बार राज्यसभा सदस्य थे और 2012-13 (यूपीए-2) में केंद्रीय रेल मंत्री थे. रॉय 2001 में केवल एक बार चुनाव लड़े थे और हार गए थे. इस बार भी उन्होंने मधुमेह के कारण अपनी खराब सेहत का हवाला देकर चुनाव न लड़ने की दलील रखी लेकिन शाह नहीं माने. रॉय नाराज हो गए, उन्होंने ज्यादा प्रचार नहीं किया, मगर अपनी सीट जीत गए.

सियासी जानकारों का कहना है कि रॉय भाजपा में पूरी तरह हाशिए पर चले गए थे. चुनाव प्रचार में उनकी शिरकत न के बराबर थी और उनकी साख प्रभावित हुई. पार्टी में उनके खास राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी चुनाव परिणामों के बाद रॉय से दूरी बनाना शुरू कर दिया था. कोलकाता के रबींद्र भारती विश्वविद्यालय में अध्यापन करने वाले राजनैतिक टिप्पणीकार विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, ‘‘मुकुल रॉय भाजपा में बाहरी व्यक्ति बने रहे. उन पर संदेह किया जाता रहा. वे भाजपा की संस्कृति के साथ तालमेल नहीं बिठा सके. अब वे बाहर हो गए हैं, तो वे भी सहज होंगे और भाजपा भी. ‘‘

> **मुकुल रॉय को भाजपा में कभी अपना जैसा नहीं लगा. उन्हें ममता बनर्जी के साथ दशकों पुराने संबंधों के कारण हमेशा संदेह की नजर से देखा जाता रहा. पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वी अक्सर कटाक्ष किया करते थे.**

टीएमसी की शानदार जीत (292 में से 213 सीटें) से रॉय को भाजपा छोड़ने के बारे में दो बार नहीं सोचना पड़ा. ममता और अभिषेक के साथ मेल-मिलाप का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने संबंधों को बेहतर करना शुरू कर दिया. स्पष्ट संकेत तो यही था कि 6 मई को विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ लेने के दौरान राय ने अपने पुराने दोस्त और टीएमसी अध्यक्ष सुब्रत बख्शी के साथ चाय पर बातचीत की मगर भाजपा के राज्य प्रमुख दिलीप घोष की पार्टी के नए विधायकों के साथ बैठक में शामिल नहीं हुए.

मुश्किल में भाजपा

आधिकारिक तौर पर तो भाजपा ने रॉय के पाला बदल पर यही रुख अपनाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता. घोष ने उत्तर 24 परगना के बनगांव में 11 जून को पार्टी की बैठक के दौरान कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि भाजपा ने कुछ भी खोया है; मुझे जर्रा भर यकीन नहीं है कि उनके भजपा में आने के बाद पार्टी को उनसे कसी तरह का लाभ हुआ. ‘कट मनी’ और सिंडिकेट राज जैसी पार्टी से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए भाजपा में रहना मुश्किल है.’’ स्थानीय भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर और विधायक विश्वजीत दास, अशोक कीर्तनिया और सुब्रत ठाकुर ने इस बैठक का बहिष्कार किया था.

घोष के इस बहादुराना रवैए के बावजूद, राज्य भाजपा के लिए 74 विधायकों की अपनी मौजूदा ताकत (पार्टी ने 77 सीटें जीती थीं, रॉय के बाहर होने के अलावा, दो विधायकों ने अपनी सीटें खाली कर दी थीं) को बचाए रखना चुनौती होगी, खासकर टीएमसी अगर उन्हें विभिन्न बोर्डों और निगमों में पद देने का लालच देती है. दास और कीर्तनिया जैसे रॉय के वफादारों सहित कम से कम 10 विधायक कथित तौर पर टीएमसी में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं.

इसके अलावा, दो दर्जन से अधिक मुस्लिम नेता, जो ममता की हार की आशंका में टीएमसी से भाजपा में आए थे, अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं. इनमें भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कासिम अली; कबीरुल इस्लाम, पूर्व विधायक शेख परवेज रहमान और आलमगीर मोल्ला शामिल हैं. अली कहते हैं, ‘‘भाजपा का हिंदुत्व पर खासा जोर आंख खोलने वाला रहा है. मुकुल रॉय ने हमें साथ ले चलने की बात की थी,

Only Books Magazine

लेकिन अब वे चले गए हैं, तो पार्टी में हमारा भविष्य खत्म हो गया है.'' कुछ मुस्लिम नेता, जिन्होंने अधिकारी के साथ दलबदल किया था, चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाली टिप्पणियों से बेहद चिंतित और चकित थे.

इस बीच, राज्य भाजपा में एक ट्विटर युद्ध छिड़ गया है, जिसमें स्वपन दासगुप्ता ने वरिष्ठ नेता तथागत रॉय के मुकुल रॉय को ''ट्रोजन हॉर्स'' कहने पर आपत्ति जताई और दिलीप घोष ने उन लोगों को अस्वास्थ्यकर बताकर बदनाम किया, जो टीएमसी से भाजपा में आए थे. ऐसी बयानबाजी से तो भाजपा को नुक्सान ही हो सकता है.

भाजपा की बंगाल इकाई के साथ और भी समस्याएं हैं. चुनाव प्रचार की दिशा तय करने में केंद्रीय नेतृत्व के भारी भूमिका को लेकर पार्टी में काफी नाराजगी है. जैसा कि घोष ने स्वीकार किया, ''हमारी कुछ चुनाव अभियान नीतियां वास्तव में गलत थीं. वे केंद्रीय नेतृत्व ने तय की थीं और उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है.'' पार्टी में कई अन्य लोग चुनावी रणनीति तैयार करने में 'ऊपर से नीचे' फरमान पर सवाल उठा रहे हैं, जिसने जमीनी स्तर के अनुभव वाले राज्य के दिग्गजों को हाशिये पर धकेल दिया. जो लोग हमेशा से यह मानते रहे हैं कि आक्रामक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण सांस्कृतिक रूप से बंगाली जीवन के विपरीत था, वे अब चेतावनी दे रहे हैं कि एक ही रणनीति का पालन करने से आम तौर पर बंगाली और खासकर राज्य की आबादी में 30 फीसद हिस्सा रखने वाले मुसलमान समुदाय पार्टी से दूर चला गया.

भाजपा को न केवल बंगाल में अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है, बल्कि उसे एकजुट चेहरा भी पेश करना होगा. चुनाव अभियान के सतही सौहार्द ने पार्टी के पुराने लोगों और दलबदलू नए लोगों के बीच शत्रुता बढ़ाने में ही मदद की है. फिलहाल राज्य इकाई में दो शक्ति केंद्र हैं: एक का नेतृत्व घोष कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व अधिकारी करते हैं, जो अब राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बना दिए गए हैं.

ममता का नया असलहा?

हालांकि ममता के पास पार्टी में शामिल होने के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है, लेकिन वे चुनेंगी कि किसको पार्टी में आने दिया जाए. जो लोग चुनाव लड़ने के लिए भागे थे और टीएमसी की आलोचना की थी, उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है. रॉय के बारे में दीदी का कहना है कि उन्होंने प्रचार के दौरान अपनी पूर्व पार्टी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं बोला. हालांकि, रॉय ने भाजपा में शामिल होने के समय ममता और अभिषेक के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी, उन पर ''निजी कंपनी'' की तरह पार्टी चलाने जैसे बेहद तीखे आरोप लगाए थे.

फिर भी ममता कहती हैं, ''मुकुल हमारे अपने में से एक है. वह घर का लड़का है. उसे केंद्रीय जांच एजेंसियों से बहुत उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ा. भाजपा में उसकी तबीयत बिगड़ रही थी. उसे यहां (टीएमसी में) मानसिक शांति मिलेगी.''

कथित तौर पर रॉय को ममता ने आश्वासन दिया है कि पार्टी सारदा और नारद घोटाले की जांच में उनका समर्थन करेगी. टीएमसी का मानना है कि नारद जांच में अधिकारी जैसे भाजपा के अपने नेता को फंसाए बिना रॉय को नहीं पकड़ा जा सकता है. रॉय के बेटे शुभ्रांशु को शायद कृष्णानगर उत्तर उप-चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाकर टीएमसी में पुनर्वास किया जाएगा.

अच्छा स्वास्थ्य नहीं होने और औपचारिक पद नहीं सौंपे जाने के बावजूद रॉय हालांकि पार्टी में फिर से शामिल होकर उत्साहित हैं. टीएमसी के नए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक चाहते हैं कि रॉय पार्टी के महत्वाकांक्षी विस्तार अभियान में भूमिका निभाएं. रॉय पूर्वोत्तर-मुख्य रूप से त्रिपुरा और मणिपुर से इसकी शुरुआत करेंगे, जहां पार्टी की पैठ है. त्रिपुरा में, सत्तारूढ़ भाजपा में अंतर्कलह है, कद्दावर नेता सुदीप रॉय बर्मन को मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दरकिनार कर दिया है. माना जा रहा है कि राज्य के 36 में से 25 भाजपा विधायक देब से नाखुश हैं.

बहरहाल, रॉय जब भाजपा में थे तो वे अक्सर दावा किया करते थे कि ममता को छोड़ने के लिए तैयार तृणमूल के 70-100 विधायक उनके संपर्क में थे. जाहिर है, टीएमसी में अपनी योग्यता साबित करने के लिए, उनसे अब भगवा खेमे से इसी तरह के दलबदल की उम्मीद की जाएगी. इसलिए भाजपा काफी सतर्क और चौकन्ना है. इसके संकेत जो मिलने लगे हैं. 14 जून को पार्टी ने लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को तोड़ते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ के पास चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए 50 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा. ममता पर दबाव बनाए रखने के प्रयास के अलावा, यह दौरा राजनैतिक दलबदल के मौसम में भी ताकत का प्रदर्शन था. ■

पाला बदल...

34

2021 विधानसभा चुनाव के पहले 34 टीएमसी विधायक भाजपा में चले गए, 13 को चुनाव का टिकट मिला

142

(292 में) या 49 फीसद भाजपा उम्मीदवार 2021 में टीएमसी के दलबदलू थे

नवंबर 2017

मुकुल रॉय टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए

2019

लोकसभा चुनावों के दौरान दो सांसद (सौमित्र खान और अनुपम हाजरा), एक विधायक और दर्जन भर दूसरे नेता टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए

2020

2021 विधानसभा चुनावों के पहले 3 सांसद, 34 विधायक, एक पूर्व सांसद और 150 दूसरे नेता टीएमसी छोड़कर भाजपा के पाले में गए. उनमें शुभेंदु तथा शिशिर अधिकारी (शुभेंदु के पिता), दिनेश त्रिवेदी, सुनील मंडल और राजीब बनर्जी प्रमुख हैं

...और घर वापसी

11 जून

मुकुल रॉय बेटे शुभ्रांशु के साथ टीएमसी में लौटे. अटकलें हैं कि कई नेता लौटने के इंतजार में है, घर वापसी की 10 अर्जियां (कम से कम दो भाजपा विधायकों के भी) पड़ी हैं. इसके अलावा दूसरे कई (3 सांसदों और 10-15 विधायकों सहित) सकारात्मक संकेतों के इंतजार में बताए जाते हैं

विपक्ष

नए मोर्चे का तिलिस्म

सुजीत ठाकुर

मरा हुआ हाथी भी सवा लाख का होता है. देश की सियासत में इस कहावत के बड़े मायने हैं. खासकर जब बात तीसरा मोर्चा बनाने की हो, जिसकी कवायद एक बार फिर शुरू हो गई है. सियासतदानों को इसकी दस्तक बीते 11 जून को सुनाई दी. उस दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार और पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच तीन घंटे की बातचीत हुई. इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की बात हुई. तीसरे मोर्चे का तिलिस्म यहीं से शुरू होता है. सियासत का यह मायाजाल इतना जटिल है कि इसकी हर कड़ी बहुत सारे अगर-मगर से गुजरते हुए सुलझती हैं. बहरहाल दो सियासी महारथी शरद पवार और ममता बनर्जी तथा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उस लंबे और दुरूह रास्ते पर चल पड़े हैं जिसकी मंजिल 2024 का लोकसभा चुनाव है.

यह शुरुआत अनायास नहीं है. पश्चिम बंगाल के बीते विधानसभा चुनाव के दौरान, जब भाजपा पूरे आक्रमकता के साथ ममता के खिलाफ लड़ रही थी और 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी उसी वक्त ममता बनर्जी ने कहा था कि 'वह एक पैर से बंगाल जीतेंगी और दूसरे पैर से दिल्ली'. (एक पैर में चोट की वजह से ममता व्हीलचेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर रही थीं.) ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने राज्य में ऐतिहासक जीत हासिल की थी. इसी चुनाव में प्रशांत किशोर ने भी कहा था, ''भाजपा दहाई के आंकड़े में सिमट जाएगी''. प्रशांत किशोर का दावा तो सही हो गया और ममता का वह दावा भी सही हो गया कि वह एक पैर से बंगाल जीतेंगी. 'दूसरे पैर से दिल्ली' की जंग लड़ने के लिए साल 2024 तक इंतजार करना होगा. लेकिन, व्हीलचेयर से हटकर ममता जैसे ही अपने दोनों पैरों पर खड़ी हुई हैं, उन्होंने 2024 में भाजपा को हराने के लिए सियासी तानेबाने को बुनना शुरू कर दिया है और पवार के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात इसका सबूत है.

एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक कहते हैं, ''प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल के अपने अनुभवों को पवार से साझा किया. प्रशांत चाहते हैं कि विपक्षी दल, केंद्र में भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाएं. बंगाल चुनाव के दौरान पवार, ममता का समर्थन कर रहे थे और उनके बंगाल जाने

Only Books Magazine

साल 2024 पर नजर
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (बाएं) एनसीपी नेता शरद पवार के साथ

देबज्योति चक्रवर्ती

सोनू किशन

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एनसीपी नेता शरद पवार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने के दुरूह रास्ते पर चल पड़े हैं

का कार्यक्रम भी था लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे नहीं जा सके.'' लेकिन मोर्चा का स्वरूप क्या होगा? क्या यह संयुक्त मोर्चा (कांग्रेस) के साथ होगा? क्या तीसरा मोर्चा होगा (गैर भाजपा-गैर कांग्रेस)? और मोर्चे का चेहरा कौन होगा?

राजनैतिक टीकाकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं, ''संयुक्त मोर्चा बनने का विकल्प फिलहाल नहीं दिख रहा. कांग्रेस में खुद ही एकजुटता नहीं है और न ही अभी तक नेतृत्व का मसला सुलझा है.'' मणिकांत की बात में दम है. कांग्रेस अभी खुद ही अपने संकट से जूझ रही है. राजस्थान और पंजाब में गुटबाजी चरम पर है. पार्टी के दिग्गज नेता, जिन्हें जी-23 कहते हैं, भी पार्टी के कामकाज से असहज हैं. इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश जैसे सूबे जहां अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हैं, वहां पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी के साथ यह भी अभी तय नहीं हैं. प्रदेश के सभी दल, भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे यह तो तय है लेकिन सभी एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ लड़ें, इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है. ऐसे में संयुक्त मोर्चा बनना दिवास्वपन की तरह ही है.

टीएमसी नेता डेरेक ओ'ब्रायन कहते हैं, ''किसान नेता राकेश टिकैत, पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए वोट मांग रहे थे. चुनाव के बाद भी वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले. यूपी चुनाव में टिकैत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.'' इस बयान के साफ संकेत हैं कि टीएमसी, यूपी चुनाव में टिकैत की मदद करेगी या टिकैत भाजपा विरोधी जिस दल के साथ होंगे टीएमसी उनकी मदद कर सकती है. ऐसे में क्या पवार और ममता तीसरे मोर्चे (गैर भाजपा-गैर कांग्रेस) दलों को एकजुट करने यानी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? राजनैतिक टीकाकार एन. अशोकन कहते हैं, ''कांग्रेस के बिना, भाजपा विरोधी दलों का मोर्चा बनाना, असंभव नहीं तो कठिन जरूर है. खासकर तब जब गैर भाजपा-गैर कांग्रेस दलों में ऐसे प्रभावी दल भी हैं जो अमूमन सत्तापक्ष के साथ जाते हैं. मसल बीजद, वाइएसआर कांग्रेस, बसपा, टीआरएस आदि.''

अशोकन का कहना मुनासिब दिखता है. अपने सबसे खराब समय से गुजर रही कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर, भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव लड़ती है. 2019 में कांग्रेस सिर्फ 52 सीट जीत सकी थी लेकिन 197 पर दूसरे नंबर पर थी. इतना ही नहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, तेलंगाना, पंजाब और गोवा जैसे राज्यों की 150 से अधिक सीटों पर सीधे मुकाबले में रहती है. ऐसे में कांग्रेस के बिना किसी भी भाजपा विरोधी मोर्चे की संभावना बहुत कम है. खासकर तब, जब कई राज्यों में जो भी भाजपा विरोधी दल या एनडीए विरोधी दल हैं वहां कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों की सहयोगी है. चाहे महाराष्ट्र हो या बिहार या तमिलनाडु या फिर झारखंड.

ऐसे में क्या कांग्रेस के बिना, भाजपा विरोधी मोर्चे की कोई संभावना नहीं है? एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ''राजनीति में संभावनाओं का अकाल नहीं है. इसलिए एक ऐसा मोर्चा साकार होगा, जिसमें वैचारिक रूप से कांग्रेस शामिल तो रहेगी पर व्यावहारिक रूप से नहीं.'' यह नेता अपनी बात को स्पष्ट करते हैं, ''पश्चिम बंगाल में व्यावहारिक रूप से कांग्रेस, टीएमसी के खिलाफ थी लेकिन वैचारिक रूप से नहीं. यहां कांग्रेस की हार से पार्टी को नुक्सान जरूर हुआ लेकिन यूपीए के लिहाज से यदि देखा जाए तो, कांग्रेस के लिए यह बड़ी जीत है. प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भाजपा विरोधी दलों की जीत ही भावी नए मोर्चे का उद्देश्य है.''

इन सब के बीच एक अहम सवाल नेतृत्व का उठता है. भावी मोर्चे का नेता कौन होगा और जो नेता होगा क्या वही 2024 में मोदी के मुकाबले विपक्ष का पीएम उम्मीदवार होगा? शिवसेना सांसद संजय राउत कहते हैं, ''समय के साथ सब कुछ स्पष्ट होगा. वैसे भी भाजपा विरोधी दलों में ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप यह सुझाव देते रहे हैं कि शरद पावर को यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए.'' राउत इससे आगे कुछ नहीं कहते हैं. लेकिन क्या कांग्रेस यह स्वीकार करेगी कि यूपीए का नेतृत्व सोनिया गांधी की जगह दूसरे नेता करें? टीएमसी और एनसीपी के नेता अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि यहां किसी पार्टी का नेतृत्व दूसरी पार्टी के नेता करने जा रहे हैं, यह बात नहीं है. यहां बात भाजपा विरोधी गठबंधन को चलाने की है. ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि गठबंधन को चलाने की जिम्मेदारी घटक दल की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को ही दिया जाए. पहले भी हरकिशन सिंह सुरजीत, चंद्रबाबू नायडु, जॉर्ज फर्नांडीस जैसे नेता गठबंधन के संयोजक के तौर पर सफल भूमिका निभा चुके हैं. यह भी जरूरी नहीं है कि गठबंधन में शामिल सभी दल, राज्य स्तरीय चुनाव में एक दूसरे के लिए मददगार साबित हों लेकिन उनके लिए नुक्सानदेह साबित नहीं हों, यह संभव किया जा सकता है.

बहरहाल, नए मोर्चे में टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, द्रविड़ मुनत्र कड़गम (द्रमुक), झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पहले चरण में शामिल होंगे क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं हैं. बाद में अन्य दलों को इसमें शामिल किया जा सकता है. इसका मकसद भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक गठबंधन को खड़ा करना है और जाहिर है कि गठबंधन के नेता को ही मोदी के खिलाफ मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी. रही बात संख्या बल की तो कांग्रेस पहले भी संख्याबल में अधिक रहने के बाद भी चंद्रशेखर को बाहर से समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना चुकी है. पहला लक्ष्य भाजपा को रोकना है. इस साल सात और अगले सात नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें ज्यादातर में कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से ही है. अगर कांग्रेस अपना प्रदर्शन सुधार पाती है तो नए मोर्चे को कांग्रेस की छतरी तले आते देर नहीं लगेगी. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ तो नए मोर्चे को लेकर कांग्रेस अपनी दिक्कत बताने की स्थिति में नहीं होगी. ■

दलित वोटर

पंजाब में सभी डालें डोरा

अनिलेश एस. महाजन

करीब आठ महीने बाद, अगले साल फरवरी में पंजाब के विधानसभा चुनाव होंगे लेकिन राजनैतिक दलों, दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी पंडितों ने भी कयासों और अनुमानों का अपना पिटारा खोल दिया है. 12 जून को चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल ने घोषणा की कि उनकी पार्टी एक बार फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन करेगी. बादल ने वादा किया कि अगर अकाली दल सत्ता में आया तो एक दलित उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा. बादल को उम्मीद है कि इससे दलित वोट उनकी पार्टी की ओर मोड़ने में मदद मिलेगी और भाजपा के साथ उसके रिश्ते टूटने के कारण जो नुक्सान हुआ है, उसकी भरपाई भी होगी.

इस घोषणा से अकाली दल के कट्टरपंथी भी प्रसन्न हैं. केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर भाजपा से अलग होने के बाद, ग्रामीण किसानों और धार्मिक मतदाताओं के बीच अपने राजनैतिक नुक्सान को कम करने के उद्देश्य से, सुखबीर पार्टी के पुराने पंथिक एजेंडे की ओर लौटते दिख रहे हैं. हालांकि सवाल यह भी है कि आखिर बसपा की संकटग्रस्त पंजाब इकाई उनके लिए कितने काम की साबित हो पाएगी. पिछले 25 वर्षों से बसपा राज्य में कभी भी पांच प्रतिशत से अधिक वोट नहीं हासिल कर पाई है. दरअसल, यह बड़े दलों के लिए राजनैतिक शिकारगाह जैसी हो गई है जिसके नेताओं को बड़ी पार्टियां जब चाहें अपनी ओर मिला लेती हैं और बसपा नेता भी अपनी किस्मत तलाशने के लिए बेहिचक चले जाते हैं. यह चलन पंजाब में 2002 के विधानसभा चुनावों से पहले बसपा के तब के शीर्ष नेता सतनाम कैंथ और वर्तमान मंत्री चरणजीत चन्नी के कांग्रेस में शामिल होने के साथ शुरू हुआ. बाद में, सुखबीर ने पवन कुमार टीनू, अविनाश चंदर और देस राज धुग्गा सहित बसपा के कई नेताओं को अपने खेमे में शामिल किया. दोआबा जिलों में बहुत से दलित कार्यकर्ताओं को साथ मिलाकर भाजपा ने भी काफी फायदा उठाया है.

अकाली दल के अधिकांश नेता मानते हैं कि बसपा पंजाब में एक चूकी हुई ताकत है, और दलित समूहों में अब उसका बड़ा प्रभाव भी नहीं है. जानकारों का कहना है कि 12 जून को घोषित गठबंधन दिखावे का मामला ही था. पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले आशुतोष कुमार कहते हैं, ''बसपा का असर पंजाब के दोआबा क्षेत्र की कुछ सीटों तक सीमित है. सभी दलित समूहों में इसका काडर भी नहीं है और गैर-दलितों के बीच इसकी अपील सीमित है.'' मजहबी सिखों में भी पार्टी का असर लगभग नहीं है, जो पंजाब के दलितों का एक-तिहाई हिस्सा हैं.

पंजाब में सभी दल खुद को 'दलित-हितैषी' साबित करना चाहते हैं. कांग्रेस भी अब राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में एक दलित उम्मीदवार पर विचार कर रही है. राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एक सुलह समिति ने 12 जून को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी से इसकी सिफारिश की, जिसके बाकी सदस्य पंजाब मामलों के पार्टी प्रभारी हरीश रावत और जे.पी. अग्रवाल हैं. इसके लिए रामदासी दलित मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और वाल्मीकि नेता तथा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी राजकुमार वेरका के नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है.

पंजाब में किसान आंदोलन जारी है और इसके कारण दलितों और अन्य समुदायों के बीच जट सिखों के खिलाफ एक ध्रुवीकरण के भी संकेत हैं. राज्य में जट सिख मतदाताओं की संख्या सिर्फ 18 प्रतिशत है लेकिन राजनीति में उनका दबदबा सबसे ज्यादा है. 1972-77 में ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर राज्य के सभी मुख्यमंत्री जट समुदाय से ही हुए हैं. जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स के प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोधका कहते हैं, ''दलित जट सिखों को हटाकर सत्ता का केंद्र बनने की इच्छा नहीं रखते, फिलहाल वे सत्ता में थोड़ा बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं.''

अकाली दल के अलग होने के बाद भाजपा दो प्रमुख शहरी दलित समूहों, रविदास और वाल्मीकि समुदायों के बीच अपनी पैठ को मजबूत कर रही है. दोनों समूह मिलकर पंजाब में कुल दलित मतदाताओं का 37

एएनआइ

नई शुरुआत
12 जून को चंडीगढ़ में अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (दाएं) के साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीशचंद्र मिश्रा

प्रतिशत हैं और राज्य के कुल मतदाताओं में दोनों की 7-7 प्रतिशत हिस्सेदारी है. पंजाब के दोआबा क्षेत्र के जलंधर, कपूरथला, नवाशहर और होशियारपुर जिलों में उनका दबदबा है (इन जिलों में बसपा की भी मौजूदगी है). भाजपा के दो प्रमुख नेता—केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश और हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला—रविदास समुदाय से हैं और इसी क्षेत्र से आते हैं. इसी तरह, सूफी गायक से उत्तरी दिल्ली से सांसद बने हंसराज हंस जालंधर के वाल्मीकि समुदाय से हैं. पिछले छह महीनों में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के सदस्य अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने पंजाब के 12,500 गांवों में से करीब 7,000 में गए हैं. इनमें कई दलित समुदायों के संपर्क में रहे हैं.

बादल को मजहबी सिखों को लुभाने की कोशिश भी करनी पड़ सकती है, जो कांग्रेस और अकाली दल दोनों से नाखुश हैं. यह समुदाय राज्य के कुल मतदाताओं का 10 प्रतिशत से अधिक है, फिर भी इस समुदाय का कोई न तो राज्य में मंत्री है, न ही कोई सांसद. 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेहुरमती की घटनाओं के बाद एसजीपीसी और कुछ सिख धार्मिक नेताओं ने इस समुदाय के कुछ लोगों—जैसे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों—को कथित रूप से निशाना बनाया तो इसको लेकर मजहबी सिख अकाली दल से नाराज हैं. मजहबी सिख, व्यवसायिक ताकत के लिए बड़े दलित संघर्ष में भी उलझ गए हैं. पंजाब में, जट सिखों के पास 93 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि है, जबकि दलितों के पास केवल तीन प्रतिशत है. मजहबी सिख अक्सर पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी जिलों (बठिंडा, फरीदकोट, मनसा, मोगा, बरनाला, संगरूर, मलेरकोटला और पटियाला) में खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करते हैं. ये जिले किसान संघों के विरोध का गढ़ भी हैं.

रविदास और वाल्मीकि समुदाय के 7-7 फीसद वोटर हैं. मजहबी सिख वोटरों की तादाद 10 फीसद है. इन तीनों दलित समुदायों के वोट राज्य में 25 फीसद बैठते हैं. इसलिए अकाली और कांग्रेस दोनों डोरे डाल रहे हैं

पिछले दो दशकों में इन दोनों समुदायों के बीच खेती योग्य जमीन और दलितों की संपत्ति पर कब्जा करने के प्रयासों के खिलाफ संघर्ष देखा गया है. 2009 के बाद से जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति, ग्राम-स्तरीय समितियों के माध्यम से दलितों को पंचायत भूमि की जुताई करने के लिए लामबंद कर रही है. हजारों दलित परिवारों ने पूरे दक्षिणी पंजाब में भूमि अधिकार आंदोलनों में भाग लिया है, जिससे जट सिख किसानों और दलित मजदूरों के बीच समीकरण बिगड़ गए हैं. अब तक, जट सिख किसान दलितों के बहाने 'पंचायत की जमीन' पर खेती करते आ रहे थे. पिछले विधानसभा चुनाव में, समुदाय ने बड़े पैमाने पर या तो कांग्रेस या फिर आप को वोट दिया था.

दलित समुदाय राज्य के मतदाताओं का लगभग 31.8 प्रतिशत हिस्सा है. उसने एक नकली शराब मामले की जांच को लेकर अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें 120 से अधिक लोग मारे गए थे. वे अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों और पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन जिलों में दलित सिखों को धर्मांतरित करने वाले ईसाई समूहों को सरकार के 'मौन समर्थन' से भी नाखुश हैं. पंजाब कांग्रेस के एक शीर्ष नेता का कहना है कि कैप्टन की कैबिनेट के तीन दलित मंत्री उन समुदायों से हैं जिनकी आबादी एक प्रतिशत से भी कम है. वे कहते हैं, ''मंत्रिमंडल में तीन दलित कैबिनेट मंत्री हैं और आठ जट सिख समुदाय से हैं.''

बादल को कांग्रेस का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए, पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी इलाकों में आप के साथ भी कड़ी होड़ करनी होगी. फिर बसपा के साथ नए गठबंधन सहित कट्टरपंथी एजेंडे की ओर झुकाव उच्च जाति के हिंदू और उदार सिख मतदाताओं को अकाली दल से अलग कर सकती है. परंपरा से अकाली दल के साथ जट सिख रहे हैं और कभी-कभी दलित वोटों की कांग्रेस के साथ होड़ भी रही है. सो, बादल का बसपा के साथ गठजोड़ का पासा काम नहीं करता है तो उनका राजनैतिक गणित बिगड़ जाएगा. ■

प्रतापेश्वर
१८७२ से आयुर्वेद सेवा
बाहर जाएँ तो सिर्फ खुशियाँ लाएँ, बीमारियाँ नहीं.
करें स्वामला से शुरुआत.
स्वामला
हर मौसम में संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक
सुवर्ण से समृद्ध
च्यवनप्राश
स्वामला से शुरुआत
रोग प्रतिरोधशक्ति बढाए
पाचन सुधारे
शारीरिक क्षमता सुधारे
एकाग्रता और केन्द्रित होने में सुधार करे
यौवन अवस्था बरकरार रखे
स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना में सहायता करे
हर मौसम में संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक
वयस्कों के लिए
1 बड़ा चम्मच (15 ग्राम) दिन में दो बार
बच्चों के लिए (12+ वर्ष)
1 छोटा चम्मच (5 ग्राम) दिन में दो बार
www.sdlindia.com | स्वास्थ्य और व्यापार संबंधित
पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 22 9874 पर

जीवन और जीविका बचा

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में संक्रमण के मामले पीक पर पहुंचे थे और इसी दिन बीते दो हफ्ते से महामारी की चपेट में रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव आ गयी थी. लोगों की जान बचाने का मिशन लिए योगी आदित्यनाथ फौरन मैदान में उतर आए. अस्पतालों, गावों का निरीक्षण करने के साथ महामारी से बचाव की नई रणनीति तैयार की. प्रदेश स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की टीम-9 का गठन किया और इसी तर्ज पर हर जिले में भी टीम-9 बनाकर कोरोना के खिलाफ जंग को धार दिया. टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट की रणनीति ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़कर रख दी. योगी की कारगर रणनीति का ही नतीजा था कि कोरोना संक्रमण का पीक आने के 35 दिन के भीतर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.2 प्रतिशत पर पहुंच गई. प्रदेश वासियों का जीवन बचाने के साथ कोरोना काल में लोगों की जीविका बचाने पर भी योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर प्रयासरत हैं. कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के बाद योगी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देने के मिशन में जुट गए हैं ताकि संभावित तीसरी वेव पर समय रहते प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल निर्णयों से प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर तेजी से लगाम लगाई जा सकी है. योगी के अहर्निश प्रयासों से आज प्रदेश के सभी जनपदों में कोरोना के केस 600 के नीचे पहुंच गए हैं. जिसके चलते आज योगी के ''यूपी मॉडल'' की सफलता की चर्चा दूसरे प्रदेशों में भी हो रही है. प्रदेश में अप्रैल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी ने तेजी से सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन व दवाओं की आपूर्ति, बेडों का विस्तार, जांच व टीकाकरण पर जोर दिया जिसका ही परिणाम है कि आज महज डेढ़ माह में ही प्रदेश का रिकवरी रेट 98 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है. सीएम योगी की एग्रेसिव टेस्टिंग और कांटेक्ट ट्रेसिंग की रणनीति से यूपी मॉडल'' देश में सबसे आगे है. प्रदेश में वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के मानक से अधिक हर रोज 10 गुना ज्यादा जांच की जा रही है. डब्ल्यूएचओ ने प्रदेश में रोजाना 32 हजार टेस्ट का लक्ष्य दिया था, लेकिन प्रदेश में रोजाना औसतन तीन लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं. प्रदेश में डब्ल्यूएचओ के मानक से अधिक प्रति पाजिटिव केस पर 31 कांटेक्ट सैंपल टेस्ट किए गए हैं. डब्ल्यूएचओ ने कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में भी यूपी के माइक्रो मैनेजमेंट की प्रशंसा की है. सीएम योगी के निर्देश पर बनाए गए माइक्रो कन्टेनमेंट जोन ने संक्रमण की चेन को तोड़ा है. रैपिड रिस्पांस टीम और निगरानी समितियों ने गांव-गांव जाकर बड़ी संख्या में लोगों की जांच की है। प्रदेश में 31 मार्च के बाद से ही 70 फीसदी टेस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए हैं. देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और अब तक 5.50 करोड़ से अधिक सैंपल की जांच की गई है.

मिसाल बना योगी का ''मिशन जून'' अभियान

युवाओं को सबसे तेज और सबसे अधिक टीका लगाने वाला यूपी देश का पहला राज्य बन गया है. 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना सुरक्षा कवर देने के लिए सीएम योगी ने प्रदेश में मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था. ''मिशन जून'' के तहत शुरू हुए इस विशेष वैक्सीनेशन अभियान को प्रदेश भर में जबरदस्त सफलता मिल रही है. सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश होने के बावजूद सीएम योगी की अगुआई में अब तक 51 लाख से अधिक वैक्सीनेशन डोज इस वर्ग को दी जा चुकी है. वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए सीएम योगी ने प्रतिदिन 4 लाख वैक्सीनेशन को बढ़ाकर 5 से 6 लाख तक करने का निर्देश दिया है. जबकि जुलाई तक दैनिक खुराक क्षमता को बढ़ाकर 10 से 12 लाख करने का लक्ष्य दिया है. सीएम योगी ने 'मिशन जून' समाप्त होने के साथ ही अगले 3 महीनों में एक दिन में 10 लाख डोज के साथ 10 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

ने को मिशन मोड में योगी

> “जहां बीमार-वहां उपचार के सिद्धांत पर माइक्रोकंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार शहर और गांवों में घर-घर दवाएं वितरित कर रही है, यह बहुत अच्छी पहल है.’’
>
> *–नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

इलाज की निगरानी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लखनऊ के एसजीपीजीआई के विशेषज्ञ डॉक्टरों को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी. यह टीम ब्लैक फंगस के इलाज के तौर तरीकों की मानीटरिंग करके हर मरीज के हिसाब से ‘‘लाइन आफ ट्रीटमेंट’’ तय कर रही है. इन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने गहन अध्ययन कर सरकार के समक्ष ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सुझाव दिए. जिसमें एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन के अलावा दो अन्य दवाओं का जिक्र किया गया. जिसमें इसावुकोनाजोल और पोसकोनाजोल दवा से ब्लैक फंगस के इलाज की बात कही गई है. इन दोनों दवाओं की प्रदेश में उपलब्धता को सुनिश्चित करने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं. इसके साथ ही एम्फोटेरेसिन-बी इंजेक्शन की आपूर्ति सुचारू रूप से कराने के आदेश अधिकारियों को दिए गये हैं. कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा रीफिलर्स के पास पर्याप्त बैकअप के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध है. प्रदेश में क्रियाशील, निर्माणाधीन एवं अनुमन्य कुल ऑक्सीजन संयंत्रों की संख्या बढ़कर अब 427 हो गई है, इनमें से 78 ऑक्सीजन संयंत्र कार्यशील हैं.

इलाज में हर संभव इंतजाम करने में जुटी योगी सरकार

डोर टू डोर सर्विलांस

उत्तर प्रदेश में सक्रिय 79000 से अधिक निगरानी समितियों के जरिए डोर-टू-डोर सर्विलांस किया जा रहा है. इस सर्विलांस के माध्यम से प्रदेश की 24 करोड़ की जनसंख्या में से अब तक 18 करोड़ लोगों की कोरोना स्क्रीनिंग की गई है. सामने आए मरीजों का फौरन इलाज कराया गया.

सेनेटाइजेशन पर जोर

संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए साप्ताहिक बंदी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में फॉगिंग, सैनेटाइजेशन और साफ-सफाई का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में 86,700 और शहरी क्षेत्रों में 82,000 कर्मचारी लगाए गए हैं.

महिला टीकाकरण केंद्र

सात जून से प्रदेश के हर जिले में महिला स्पेशल टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं. जिला महिला चिकित्सालय एवं संयुक्त चिकित्सालयों में दो महिला स्पेशल टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं. ब्लॉक मुख्यालय पर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर भी महिलाओं के लिए दो अलग-अलग टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं

फीवर क्लीनिक

मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंडल और जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर फीवर क्लीनिक और फ्लू क्लीनिक अनिवार्य रूप से शुरू करने के आदेश दिए हैं. कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच कराकर उनका फौरन इलाज शुरू किया जाएगा.

मेडिसिन किट

योगी सरकार ने प्रदेश में सक्रिय 79000 निगरानी समितियों के माध्यम से 15 जून से बच्चों में वायरल बुखार आदि के लिए घर-घर मेडिसिन किट बांटने का अभियान शुरू किया है. इसके लिए समितियों को पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन किट उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार ने की है.

टेलीकंसल्टेशन सिस्टम

प्रदेश के जिला अस्पतालों एवं मेडिकल कालेजों में टेलीकंसल्टेशन सुविधा शुरू की गई है. इस पर सामान्य मरीजों को घर पर ही बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करायी जा रही है. ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है कि कोरोना काल में केवल गंभीर मरीज ही इलाज के लिए अस्पताल आएं.

आयुष किट

सीएम योगी के निर्देश पर कोरोना काल में आयुष विभाग करीब 23 लाख लोगों तक पहुंचा है. इसमें विभाग की ओर से 20 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क आयुष किट वितरित की जा चुकी है. इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म और आयुष कवच एप से तीन लाख से अधिक लोग जुड़कर टिप्स ले चुके हैं.

ड्राइ राशन

सीएम योगी के निर्देश पर कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं समेत कुल 1,47,99,150 लाभार्थियों के लिए 1,64,714 आंगनबाड़ी केंद्रों से ड्राइ राशन वितरित किया जा रहा है. सरकार की ओर से शुरू की गई ड्राइ राशन परियोजना से 6,30,000 महिलाओं को रोजगार भी मिला है.

इंसेफ्लाइटिस की तर्ज पर कोरोना से बचाए जाएंगे मासूम

विशेषज्ञ कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रति बच्चों को अधिक संवेदनशील बता रहे हैं. इन आशंकाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में बच्चों को ऐसी किसी संभावित लहर से बचाने के लिए पहले से ही युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू की गई हैं. दिमागी बुखार से बच्चों की अकाल मौत रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में यूपी की सत्ता संभालते ही युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए थे. पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) और सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) तक इंसेफ्लाइटिस को केंद्र में रखकर स्वास्थ्य सुविधाओं की बुनियादी संरचना को मजबूत किया गया. पूर्वांचल के तीन दर्जन से अधिक संवेदनशील जिलों में रोकथाम को लेकर सफाई और स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया उससे इंसेफ्लाइटिस तकरीबन खत्म होने के कगार पर है. अब इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन के ये अनुभव योगी सरकार कोराना से बच्चों को बचाने में उपयोग कर रही है.

इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण में बड़ी भूमिका निभाने वाले पीकू (पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट) प्रोजेक्ट को पूरे प्रदेश में कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए लागू किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में बच्चों के लिए 100 बेड का आईसीयू तैयार रखने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने हर मंडल मुख्यालय पर 100-100 बेड का और जिला अस्पतालों में 25-25 बिस्तरों की क्षमता वाला आईसीयू बनाने को कहा है. इसके साथ ही तय समय में जरूरी और दक्ष मानव संसाधन का बंदोबस्त करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है.

इंसेफ्लाइटिस से मासूमों को बचाने के करीब चार दशक लंबे अनुभव के मद्देनजर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिर्विसिटी के डॉक्टर पीकू के संचालन के लिए प्रदेश के अन्य चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे. मालूम हो कि प्रदेश के करीब तीन दर्जन जिलों खासकर गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी जिलों में पिछले चार दशक से मासूमों के लिए काल बनी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों में अब 95 फीसद से अधिक की गिरावट आ चुकी है.

आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का समेकित प्रयास

कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए समेकित प्रयास भी शुरू किए गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विशेषज्ञों से आयुर्वेद की पुरानी परम्पराओं से कोरोना संक्रामित लोगों के इलाज की बात कही थी. आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी) विभाग ने भी कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है. आयुष विभाग अपने सभी अस्पतालों में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक हेल्प डेस्क बनाने जा रहा है. साथ ही आयुष कवच एप पर बच्चों की सेहत से जुड़ा एक नया फीचर भी जोड़ने जा रहा है. इसमें बच्चों की सेहत का मौसम के हिसाब से कैसे ख्याल रखें, किस तरह से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाया जाए, कौन सी घरेलू औषधि के जरिए उनकी सेहत बेहतर बनाए, इसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी. इसके बाद से आयुष विभाग लगातार होमआइसोलेटेड मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं, काढ़ा आदि वितरित करा रहा है. कोरोना काल में आयुष कवच मोबाइल एप लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ है. तीन लाख से अधिक लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. प्रदेश में आयुष विभाग के करीब 2104 चिकित्सालय हैं. इनमें से लखनऊ, बनारस, पीलीभीत समेत अन्य जिलों में 8 बड़े अस्पताल हैं. इन सभी अस्पतालों में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक हेल्पडेस्क बनाई जाएगी. जहां पर आयुष डॉक्टर लोगों को बच्चों की सेहत और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए इसकी जानकारी देंगे. इसके अलावा यहां से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं का वितरण भी किया जाएगा.

कोरोना से अनाथ हुए बच्चे की देखभाल करेगी सरकार

कोविड काल (मार्च 2020 से) में अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के जीवन को संवारने के लिए तैयार 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही उसे धरातल पर उतारने में योगी सरकार मुस्तैदी से जुट गई है. इसके तहत

चिन्हित बच्चों की लिस्टिंग समेत पात्रता की शर्तों और जिलों में योजना को अमलीजामा पहनाने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गयी है. इस योजना का उद्देश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुंचाना और उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है. इस योजना के तहत अनाथ हुए बच्चों के भरण, पोषण, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया है. पात्र बच्चे के वैध संरक्षक का चिन्हांकन जनपद स्तरीय टास्क फोर्स करेगी और जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति भी इन बच्चों के समुचित विकास पर नजर रखेगी. उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने पर ही इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही एक परिवार के सभी (जैविक तथा कानूनी रूप से गोद लिए गए) बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा. 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' से जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना है, उनकी श्रेणी तय कर दी गई है. इस योजना में शून्य से 18 साल के ऐसे बच्चे शामिल किए जाएंगे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोविड काल में हो गयी हो या माता-पिता में से एक की मृत्यु एक मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और दूसरे की मृत्यु कोविड काल में हो गयी अथवा दोनों की मौत एक मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड काल में हो गयी. इसके अलावा शून्य से 18 साल के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड काल में हो गयी हो और वह परिवार का मुख्यकर्ता हो और वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय तीन लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो को भी योजना में शामिल किया गया है.

कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को तैयार हो रहे अस्पताल

कोविड केयर सेंटर

सभी जिलों में दूरदराज स्थित चार-चार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) को एल-1 कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है. इनमें बिस्तरों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 की जा रही है. सभी बेड पर आक्सीजन की सुविधा होगी. इनमें से 10 बेड पीडियाट्रिक्स के लिए आरक्षित रहेंगे.

ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर

एल-1 कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील होने वाले सीएचएसी के सभी बिस्तरों पर आक्सीजन की सप्लाई देने के लिए योगी सरकार 17000 आक्सीजन कंसेन्ट्रेटर खरीद रही है. स्वास्थ्य विभाग के जून महीने के अंत तक सभी अस्पतालों में आक्सीजन कंसन्ट्रेटर लगा दिए जाएंगे.

आक्सीजन प्लांट

यूपी की चीनी मिलें 40 जिलों में तथा 35 जिलों में डिस्टलरियों के माध्यम से अस्पतालों में आक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रही हैं. ग्रामीण इलाकों में बनने वाले 100 से अधिक एल-1 कोविड केयर सेंटर में ये प्लांट लगेंगे. इनसे एक साथ 100 मरीजों को 24 घंटे आक्सीजन दी जा सकेगी.

डाक्टरों की तैनाती

ग्रामीण इलाकों में तैयार होने वाले हर कोविड केयर सेंटर में कम से कम सात डाक्टरों की तैनाती रहेगी. इनमें दो इमरजेंसी मेडिकल आफीसर, एक चिकित्सा अधीक्षक तथा चार अलग-अलग विधा के स्पेशियलिस्ट डाक्टर, छह नर्स, चार फार्मासिस्ट समेत 12 मेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे.

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश के नर्सिंग कालेजों की प्रशिक्षु नर्सों को कोविड टीकाकरण का प्रशिक्षण देने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिया है. पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट के संचालन में डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को पारंगत करने के लिए तीन दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है.

चिकित्सकों की नियुक्ति

योगी सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (पीएमएस) में 3620 डाक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी है. सबसे ज्यादा 600 बाल रोग विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी. इसके बाद 590 पद जनरल फिजीशियन और इतने ही पद जनरल सर्जन एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों के हैं.

आपदा विशेषज्ञ

योगी सरकार ने प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए 62 जिलों में संविदा के आधार पर आपदा विशेषज्ञ रखने का फैसला किया है. इन्हें हर माह 50 हजार रुपए मानदेय मिलेगा. पहले से 13 जिलों में काम कर रहे विशेषज्ञों को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है.

प्रोजेक्ट एल्डरलाइन

यूपी में अपनों से बिछड़े और सड़क व फुटपाथ पर जीवन बिताने को मजबूर बुजुर्गों के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल काफी मददगार साबित हो रही है. प्रोजेक्ट एल्डरलाइन के तहत यूपी में शुरु की गई टोल फ्री हेल्पलाइन 14567 नम्बर पर जानकारी मिलने पर ऐसे अनेक लोगों की रोज मदद की जा रही है.

23 लाख
इंडियन बैंक
Indian Bank
Bapubhawan Branch, (6174)
MUNNA LAL
One Thousand Only
50260212358
₹ 1,000/-
UP Building and other construction workers welfare board

कोरोना महामारी में हर जरूरतमंद का सहारा बने सीएम योगी

वैश्विक महामारी कोरोना की मार से समाज का हर तबका प्रभावित रहा. चूंकि दूसरी लहर पहले की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक थी, लिहाजा इसका असर भी उसी अनुसार रहा. समाज का सबसे वंचित तबका जिसके परिवार का गुजारा उसकी मुखिया की रोज की कमाई पर निर्भर करता है, वह इस अभूतपूर्व और अप्रत्याशित महामारी से सर्वाधिक प्रभावित रहा. इसमें सड़क के किनारे रेहड़ी, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा और ठेला चालक, नाई, धोबी, दर्जी, मोची, फल और सब्जी विक्रेता आदि शामिल हैं. इसके अलावा एक बड़ा वर्ग उन श्रमिकों का है जो निर्माण कार्य से जुड़े हैं. कोरोना के पहले संक्रमण के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे आकर समाज के इस सबसे वंचित वर्ग की हर संभव मदद की थी. दूसरे चरण में भी यह सिलसिला जारी है. कोविड महामारी के बीच जीवन और जीविका की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयासों के क्रम में शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को 1,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया गया है. आपदाकाल में यह उनके लिए बड़ा संबल है. इससे लगभग 91 लाख गरीबों को राहत मिली है. कोरोना महामारी के पहले चरण में करीब 11 लाख पटरी व्यवसायियों को भरण पोषण भत्ते के रूप में एक हजार रुपए मिले थे. अगले चरण में इसी सुविधा से करीब 80 लाख पंजीकृत और गैर पंजीकृत श्रमिकों को भी संतृप्त किया गया है. उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों आदि को भरण-पोषण भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया था. बाद में कई राज्य सरकारों ने इसे अपने राज्यों में भी लागू किया. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दो बार तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक बार भरण-पोषण भत्ता दिया गया.

गरीबों के लिए अनाज का प्रबंध कर रही सरकार

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को 03 माह के लिए प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है. इस प्रकार, प्रति यूनिट 05 किलो निःशुल्क खाद्यान्न जरूरतमन्दों को दिया जा रहा है. इससे प्रदेश की लगभग 14.71 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित हो रही है. यह राशन केंद्र सरकार द्वारा घोषित निःशुल्क राशन के अतिरिक्त है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन के रूप में मिलने वाली मदद को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं. इसका सर्वाधिक लाभ उत्तरप्रदेश को ही मिलेगा. उत्तर प्रदेश में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब 15 करोड़ है. विगत वर्ष कोविड काल में सरकार ने रिक्शा चालकों, पटरी व्यवसायियों, निर्माण श्रमिकों, अंत्योदय श्रेणी के लोगों व अन्य गरीब परिवारों को भरण-पोषण भत्ता व परिवार के प्रत्येक सदस्य को राशन प्रदान किया था. वहीं, इसके साथ ही, राशन कार्ड बाध्यता समाप्त कर माह में दो बार, एक बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा दूसरी बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया गया. मालूम हो कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से लेकर अब तक गरीबों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने बहुत शुरू में ही घोषणा की थी कि श्रमिक जहां काम करेंगे वहीं के अटल आवासीय विद्यालय में ही उनके बच्चे पढ़ेंगे. गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज की सरकारी खरीद में भी यूपी ने रिकार्ड कायम किया है. फसल की खरीद में योगी सरकार हर वर्ष नए रिकार्ड कायम कर रही है. यूपी में रिकार्ड 54 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है. पूरे प्रदेश में 12 लाख से अधिक किसानों के खातों में गेहूं खरीद का 10401.54 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. गेहूं खरीद अभी जारी है.

गरीबों को राहत दे रहा कम्युनिटी किचन माडल

उत्तर प्रदेश कोरोना काल में लाखों लोगों

वाराणसी की रहने वाली गौरी शंकर को पीएम आवास योजना (अरबन) के तहत मिला आवास

को रोजाना निशुल्क भरपेट भोजन कराने वाला राज्य बन गया है. श्रमिक, ठेला, रेहड़ी व्यवसायी, दिहाड़ी मजदूरों को भोजन की समस्या न हो और प्रदेश में कोई भूखा न रहे. इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी के प्रत्येक जनपद में कम्युनिटी किचन की सकारात्मक पहल जरूरतमंदों का बड़ा सहारा बनी है. सरकार ने 75 जिलों में 416 कम्युनिटी किचन की स्थापना की है. इन सरकारी कम्युनिटी किचन के माध्यम से फूड पैकेट लोगों तक मुफ्त पहुंचाए जा रहे हैं. इस पहल में सरकार का साथ स्वैच्छिक व निजी संस्थाएं भी दे रही हैं. उनकी ओर से प्रदेश में 158 कम्युनिटी किचन संचालित किये गये हैं. प्रदेश में 416 सरकारी कम्युनिटी किचन से आज तक 6116 क्षेत्रों व मोहल्लों में 513730 लोगों को फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है. जरूरतमंदों, गरीबों को निशुल्क भोजन कराने के लिये गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं की ओर से भी लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. प्रदेश में संस्थाओं की ओर से 158 कम्युनिटी किचन संचालित हैं. इनके माध्यम से अभी तक कुल 604463 लोगों को फूड पैकेटों का वितरण किया गया है. 3145 मोहल्लों में 604990 लोगों को भोजन के पैकेट दिये गये. देश में किसी अन्य राज्य के मुकाबले कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में कम्युनिटी किचन संचालित करके लाखों लोगों को भोजन कराने में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर बना हुआ है. सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयास से लोगों ने राहत की सांस ली है. कोरोना कर्फ्यू के दौरान उनको भोजन की कमी नहीं आने दी गई है. सरकार की ओर से कोविड अस्पतालों में भी मरीजों के तीमादारों के लिये भी कम्युनिटी किचन बनवाए गए हैं जिससे इलाज कराने के दौरान उनके परिजनों को भरपेट भोजन मिल सके. सरकार की पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों ने सामुदायिक रसोई की शुरुआत की है. इसके माध्यम से शहर में बस्तियों और जरूरतमंदों को रोजाना भोजन कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी के आह्वान पर महापौर, पार्षद और नगर निगम कर्मचारी इस काम में तेजी से जुटे हुए हैं.

कोरोना काल में भी तेजी से दौड़ रहा विकास का पहिया

निवेशकों का भरोसा

कोरोना काल खंड में भी निवेशकों का यूपी पर भरोसा बरकरार रहा. इस आपदा काल में भी सूबे को 66000 करोड़ रुपए के 96 निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनमें से 18 निवेशकों की 16000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित करने की कार्यवाही पूरी हो गई है.

डेडीकेटेड हेल्प डेस्क

मुख्यमंत्री के निर्देश पर निवेशकों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हुए उन्हें नीति के अनुसार हर संभव सुविधा और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है. निवेशकों की सुविधा के लिए पिछले साल स्थापित की गई ‘‘डेडीकेटेड हेल्प डेस्क’’ को पूरी सक्रियता के साथ संचालित किया जा रहा है.

दोगुना ऋण वितरण

एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) वित्त पोषण योजना के तहत सामान्य वर्ष की तुलना में दो गुना अधिक ऋण वितरित किए गए. इस दौरान हस्तशिल्पियों और उद्यमियों को करीब 380 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही 94.60 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी भी उपलब्ध कराई गई.

शतप्रतिशत प्रगति

लॉकडाउन के दौरान भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराते हुए ओडीओपी प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में 16 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत हस्तशिल्पियों एवं कारीगरों को 10 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण और निशुल्क टूल किट्स उपलब्ध कराई गई.

आक्सीजन नीति

सूबे को मेडिकल और इंडस्ट्रियल आक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने ‘‘उत्तर प्रदेश आक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021’’ लागू की है. इसके आकर्षक प्रावधानों के कारण आक्सीजन उत्पादन से जुड़ी अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रदेश में संयत्र स्थापना में रुचि दिखाई है.

कोविड हेल्प डेस्क

औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थानों में 1 लाख, 14 हजार से अधिक कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं. 2,719 कोविड केयर सेंटर में 6,700 से अधिक बेड भी स्थापित है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्थापित कोविड हेल्प डेस्क तथा कोविड केयर सेण्टर निरन्तर संचालित रहने चाहिए.

मनरेगा रोजगार

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार में बढ़ोतरी हुई है. 10 मई को 17,980 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत केवल 2,49,428 श्रमिक काम कर रहे थे. वहीं छह जून को श्रमिकों की संख्या 14,08,615 हो गई है. 10 मई से 6 जून तक 448 करोड़ रुपये मजदूरी का भुगतान किया गया है.

मेरा गांव-स्वच्छ गांव

योगी सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में 9 जून से 10 दिन का ‘‘मेरा गांव-स्वच्छ गांव’’ अभियान शुरू किया है. इसके अंतर्गत प्रत्येक राजस्व गांव में ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए कंपोस्ट पिट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सोख्ता का निर्माण कराया जाना है.

देश की तलाश
पाकिस्तान से आकर अहमदाबाद में रह रहे हिंदू शरणार्थी अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हुए (दिसंबर, 2019)

एपी फोटो

सीएए

अल्पसंख्यक रिपोर्ट

रोहित परिहार

मई की 28 तारीख को केंद्र ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में कलेक्टरों और पंजाब तथा हरियाणा के गृह सचिवों को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों में से किसी के भी अप्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया गया है. इससे भारत में कानूनन रह रहे कम से कम 30,000 गैर-मुस्लिम अप्रवासियों को लाभ हो सकता है.

अधिसूचना कहती है, ''नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 के 57) की धारा 16 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि धारा 5 के तहत भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए या नागरिकता अधिनियम 1955, की धारा 6 के तहत देश में निवास के लिए प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अपनी शक्तियां, उल्लेखित जिलों और राज्यों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अर्थात् हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, समुदाय से ताल्लुक रखने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जा सकती है...'' 13 जिलों में राजस्थान के जालौर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर और सिरोही; गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा; छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलौदाबाजार; हरियाणा में फरीदाबाद; और पंजाब में जालंधर शामिल हैं. राजनैतिक पर्यवेक्षकों ने इस अधिसूचना को विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए), 2019 को 'पिछले दरवाजे से लागू करने' का प्रयास बताते हुए इस आधार पर आपत्ति की है कि सीएए के नियम और प्रावधान गृह मंत्रालय की ओर से अभी तैयार किए जाने बाकी हैं. 28 मई की अधिसूचना के तुरंत बाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, ''छल. सीएए-2019 के नियम अभी बने नहीं हैं फिर भी केंद्र ने इसे लागू करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी अभी सुनवाई होनी है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर तुरंत संज्ञान लेगा और इसे पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिशों को रोकेगा.'' 1 जून को, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) ने सुप्रीम कोर्ट में इस अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती दी कि नागरिकता अधिनियम 1955, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है. अधिनियम की धारा 5 (1) के अनुसार, केंद्र एक आवेदक को भारत के नागरिक के रूप में तब तक पंजीकृत कर सकता है जब तक कि वह अवैध अप्रवासी न हो. ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जो श्रेणियां निर्धारित हैं, उनमें धर्म का कोई उल्लेख नहीं है. आइयूएमएल ने आगे तर्क दिया कि केंद्र दिसंबर 2019 में अदालत की ओर से पार्टी को दिए गए आश्वासन (जब आइयूएमएल ने सीएए की वैधता को चुनौती दी थी) की अनदेखी कर रहा है. अदालत ने तब कहा था कि फिलहाल सीएए पर रोक लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि नए कानून के नियम अभी बने नहीं हैं.

गैर-मुस्लिम शरणार्थियों से नागरिकता आवेदन मांगने की केंद्र की अधिसूचना को आइयूएमएल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है

गृह मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में याद दिलाया कि नागरिकता एक केंद्रीय विषय है और मंत्रालय समय-समय पर नागरिकता कानून, 1955 की धारा 16 के तहत राज्यों को पात्र लोगों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार देता है. केंद्र ने आइयूएमएल की याचिका के जवाब में 14 जून को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें उसने कहा कि अधिसूचना का सीएए से सरोकार नहीं है और केंद्र ने अपनी निहित शक्तियों के प्रयोग का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को दिया है.

2016 में, केंद्र सरकार ने इसी तरह के एक कदम में, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से नागरिकता के लिए आवेदन मांगे थे. 2018 में, अधिसूचना को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया था. अब नवीनतम अधिसूचना नौ राज्यों के कुल 29 जिलों को कवर करती है.

गृह मंत्रालय का कहना है कि नवीनतम अधिसूचना से केवल कानूनी आप्रवासियों को ही फायदा होगा जो भारत में सात साल के प्रवास के बाद नागरिकता के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं. दूसरी ओर सीएए, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को पांच साल के प्रवास के बाद ऐसे आवेदनों की अनुमति देगा, लेकिन विवादास्पद रूप से, केवल छह नामित धार्मिक समुदाय ही इसके तहत आवेदन करने के पात्र होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को कहा कि वह केंद्र की 28 मई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. ■

अर्थात्

साबुत बचा न कोय

अंशुमान तिवारी

कोई सरकार किसी देश के लोगों के लिए कितनी अच्छी साबित हुई है, इसे मापने का सबसे आसान तरीका क्या है?

पहला—उस देश के लोग आय और खर्च के अनुपात में कितना टैक्स (इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, राज्यों के टैक्स) चुकाते हैं?

दूसरा—बीते कुछ दशकों में उनकी आय ज्यादा बढ़ी या टैक्स?

तीसरा—टैक्स के बदले उन्हें सरकार से क्या मिलता है?

भारत में यह हिसाब लगाते ही आपको महसूस होगा कि अगर सरकार कोई कंपनी होती तो आप उस पर पैसा लेकर सेवा न देने का मुकदमा कर देते.

क्या आपको पता है कि बीते एक दशक में भारत के आम परिवारों पर कितना टैक्स बढ़ा है?

आम लोगों के मुकाबले कंपनियों पर टैक्स का क्या हाल है?

महामारी और मंदी के दौरान भारतीय ही दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब क्यों हुए?

इन तीनों के सवालों के जवाब हमारे भविष्य के लिए अनिवार्य हैं लेकिन इससे पहले टैक्स को लेकर दिमागों के जाले साफ करना जरूरी है. अक्सर टैक्स जीडीपी अनुपात (भारत 11.22 फीसद—2018) में विकसित देशों का ऊंचा औसत दिखाकर हमें शर्मिंदा किया जाता है. यह अनुपात दरअसल आर्थिक उत्पादन पर सरकार के राजस्व का हिसाब-किताब है.

इनकम टैक्स देने वाले मुट्ठी भर लोग शेष आबादी को देश पर बोझ बताते हैं लेकिन टैक्स को प्रति व्यक्ति आय की रोशनी में देखना चाहिए. भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 122वें नंबर वाला देश है. उसमें भी 80 फीसद आबादी की कमाई 20,000 रुपए मासिक (आइसीई 360 सर्वे) से कम है तो इनकम टैक्स देने वाले अरबों की संख्या में नहीं होंगे.

टैक्स आय की जगह खर्च पर लगे, यह कहकर जॉन लॉक्स और थॉमस हॉब्स ने 17वीं सदी में टैक्स बहसों को आंदोलित कर दिया था. भारत में सरकार को पता है कि अधिकांश आबादी की कमाई टैक्स के लायक नहीं है इसलिए उसकी खपत निचोड़ी जाती है.

2019 में केंद्र और राज्यों के कुल राजस्व का 65 फीसद हिस्सा खपत पर लगने वाले टैक्स से आया. वह टैक्स जो हर व्यक्ति चुकाता है जिसके दायरे में सब कुछ आता है. केंद्र की कमाई में इनकम टैक्स का हिस्सा 17 फीसद था.

किस पर बोझ

बीते एक दशक (2010 से 2020) के बीच भारतीय परिवारों पर टैक्स का बोझ 60 से बढ़कर 75 फीसद हो गया. इंडिया रेटिंग्स के इस हिसाब से व्यक्तिगत आयकर और जीएसटी शामिल हैं. मसलन, बीते सात साल में पेट्रोल-डीजल से टैक्स संग्रह 700 फीसद बढ़ा है. यह बोझ जीएसटी के आने के बाद बढ़ता रहा है जिसे लाने के साथ टैक्स कम होने वादा किया गया था.

इस गणना में राज्यों के टैक्स और सरकारी सेवाओं पर लगने वाली फीस शामिल नहीं है. वे भी लगातार बढ़ रहे हैं

किसे राहत

उत्पादन या बिक्री पर लगने वाला टैक्स (जीएसटी) आम लोग चुकाते हैं. कंपनियां इसे कीमत में जोड़कर हमसे वसूल लेती हैं. इसलिए कंपनियों पर टैक्स की गणना उनकी कमाई पर लगने वाले कर (कॉर्पोरेशन टैक्स) से होती है. इंड-रा का अध्ययन बताता है कि 2010 में केंद्र सरकार के प्रति सौ रुपए के राजस्व में कंपनियों से 40 रुपए और आम लोगों से 60 रुपए आते थे. 2020 में कंपनियां केवल 25 रुपए दे रही हैं और आम लोग दे रहे हैं 75 रुपए. याद रहे कि 2018 में कॉर्पोरेट टैक्स में 1.45 लाख करोड़ रुपए की रियायत दी गई है.

दुनिया के मुकाबले

कोविड वाली मंदी के दौरान (2020) दुनिया के प्रमुख देशों की तुलना में भारत के लोग सबसे ज्यादा गरीब हुए. ताजा आंकड़े (एमओएसएल ईकोस्कोप मई 2021) बताते हैं, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने अर्थव्यवस्था के नुक्सान को खुद उठाया और तरह-तरह की मदद के जरिए परिवारों (रोजगार देने वाली कंपनियों की भी) की कमाई में कमी नहीं होने दी. सरकारी मदद से दक्षिण अफ्रीका में भी आम परिवारों की आय सुरक्षित रही. यूरोप में भी 60 से 80 फीसद नुक्सान सरकारों ने उठाया.

भारतीय अर्थव्यवस्था की आय में कमी का 80 फीसद नुक्सान परिवारों और निजी कंपनियों के खाते में गया. जब अन्य देशों ने लोगों से वसूला गया टैक्स उनकी मदद में लगा दिया तो भारत में मंदी और बेकारी के बीच सरकार ने आम लोगों को ही निचोड़ लिया है.

भारतीय अर्थव्यवस्था उपभोक्ताओं पर केंद्रित है. भ्रष्ट सरकारी तंत्र के जरिए खर्च कारगर नहीं है. मंदी से उबरने के लिए आम लोगों पर टैक्स का बोझ घटाकर खपत बढ़ाना जरूरी है.

अगर हम जनकल्याण के लिए कंपनियों से ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं तो वह कल्याण है कहां? कोविड के दौरान ऑक्सीजन-दवा तलाशते हुए लोग मर गए, सड़कों पर भटके और बेकार होकर गरीबी में धंस गए.

सरकारों से टैक्स का हिसाब मांगना सबसे बड़ी देशभक्ति है क्योंकि बीते एक दशक में भारत के अधिकांश परिवार ऐसे आदमी में बदल चुके हैं जो बाल्टी में बैठकर उसे हैंडल से उठाने की कोशिश कर रहा है.

@anshuman1tiwari

भारत में आम लोग ज्यादा टैक्स चुकाते हैं या कंपनियां?

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

तीरथ ने कोविड काल के लिए स्वास्थ्य सुविध

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दस्तक से उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिस तरह इससे मुकाबला करने का हौंसला स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों को दिया, उसकी तुलना करना कठिन है। मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों को देखने और उनका हाल चाल लेने स्वयं पीपीई किट पहनकर कोविड अस्पतालों में पहुंच, कदाचित वे देश के ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य के कोविड मरीजों का हाल लेने अस्पताल में मरीजों से रूबरू होने में भी पीछे नहीं रहे। जिससे इस महामारी से जूझ रहे मरीजों को यह भरोसा दिलाने में वे कामयाब हुए, कि सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यही नहीं गांव घरों में होम आइसोलेट हुए कोरोना संक्रमितों से भी मुख्यमंत्री ने जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर मोबाइल के माध्यम से बात कर उनका हाल चाल भी जाना। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कोविड मरीजों की सेवा की सराहना कर उनका मनोबल बढाने को मुख्यमंत्री तीरथ कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कोविडकाल में पीपीई किट धारण कर कोविड अस्पतालो की जहां खैर-खबर लेकर कोविड से लड़ने की तैयारी को परखा, वहीं उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिदिन पीपीई किट पहन कर कोविड मरीजों की सेवा करने के लिए उनकी यह कहकर सराहना की कि उनको यह किट बीस मिनट के लिए मरीजों का हाल चाल जानने के लिए पहनने में इतनी परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन वे उन स्वास्थ्य कर्मियों को सैल्यूट करते है,जो कि प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक इसको पहनकर कोविड मरीजों की लगातार सेवा कर रहे हैं ।

जब प्रदेश में पिछले साल इस वैश्विक महामारी ने दस्तक देनी शुरू की थी तो इस महामारी से निपटने के लिए इंतजामों की अत्यधिक कमी थी। लेकिन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया जिसकी तस्दीक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जुटाया गया इन्फ्रास्ट्रक्चर खुद कर देता है। जब 15 मार्च 2020 में वैश्विक महामारी ने राज्य में पहली बार कदम रखा तो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड 673, आईसीयू बेड 216, वेंटिलेटर 116, ऑक्सीजन सिलेंडर 1193 थे। आज उत्तराखंड में कोविड मरीजों के लिए कुल आइसोलेशन बेड बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के 25,147, ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की संख्या 7,040, आईसीयू बेड 1,754 तथा वेंटिलेटर 1,092 कोविड मरीजों के लिए मौजूद हैं। राज्य में कुल 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं। जबकि 103 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर 389 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर राज्य में कोविड मरीजों को समर्पित किए गए हैं। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार ने इस बीमारी को हराने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए ।

15 जून तक उत्तराखंड में कुल 3,37,449 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 3,21,064 मरीज स्वस्थ हो गए इस प्रकार राज्य का रिकवरी प्रतिशत 95.14 प्रतिशत हो गया। 15 जून को कुल सक्रिय मामले केवल 3,642 थे। राज्य के दूरस्थ क्षेत्र के गांवों में कोरोना की जांच के लिए 278 मोबाइल सैंपल कलेक्शन टीमें दूर दराज के गांव –गांव जाकर कोविड टेस्ट कर रही हैं। मोबाइल टीमें लोगों के आरटी पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट गांव गांव जाकर कर रही हैं। वर्तमान में राज्य और केन्द्र सरकार की कुल दस प्रयोगशालाओं में कोरोना आरटी पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा 26 निजी लैब्स में ये जांच की जा रही हैं। 64 ट्रूनेट मशीनों से भी कोरोना जांच की जा रही हैं। प्रतिदिन राज्य में 35 हजार तक टेस्ट हो रहे हैं।

इनके अलावा होम आइसोलेशन में रखे गए

कोरोना से प्रभावित बच्चों की सामाजिक सुरक्षा के लिए तीरथ सरकार की वात्सल्य योना

उत्तराखंड में कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं उसके लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में बच्चों को सरकार 21 साल की आयु तक 3 हज़ार रुपये महीना देगी। साथ ही बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य इलाज की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि कोविड के कारण इन बच्चों को सरकार का आसरा देकर उनके जीवन को संवारा जायेगा। इस योजना को साल 2020 से साल 2022 तक लागू किया जायेगा।

> **“पिछले दो माह में हमने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया है। अब राज्य में कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त उपलब्धता है। कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की दृढ़ता के साथ किये गये कार्यो का ही नतीजा है कि कोरोना मामलों में बहुत कमी हुई है। हमारी सरकार संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर अभी और भी अधिक तैयारियां कर रही है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है जिससे स्वास्थ्य संसाधन बेहतर करने में मदद मिल रही है। कोविड के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं उन बच्चों के जीवन को वात्सल्य योजना के अर्न्तगत संवारने का संकल्प भी हमने लिया है। ”**
>
> *– तीरथ सिंह रावत, मुख्यमंत्री उत्तराखंड*

में उत्तराखंड की बेहतरी ओं को बनाया मजबूत

अस्पताल में पीपीई किट पहन कर कोरोना मरीज का हाल पूछते मुख्यमंत्री तीरथ

मरीजों की निगरानी एसडीआरएफ नियंत्रण कक्ष समेत जिला नियंत्रण कक्ष से भी फोन के माध्यम से भी की जा रही है। अगर किसी मरीज को लेकर किसी भी तरह का कोई खतरा दिखता है तो उसे तुरंत कोविड सेवा के लिए समर्पित एम्बुलेंस सेवा के जरिये अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। आइसोलेटेड मरीजों की देखभाल करने के लिए एक हजार स्वास्थ्य देखभाल कर्ताओं को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर आइसोलेट हुए मरीजों को होम आइसोलेशन दवा किट उपलब्ध करवा रहे हैं ।

उत्तराखंड राज्य द्वारा कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले को व्यापक तैयारी करली है। उत्तराखंड सरकार ने इसके मुकाबले के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में सबसे मुकम्मल इंतजाम किए हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं इसके लिए कुल 4,975 ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर तथा 12,349 ऑक्सीजन सिलेंडर राज्य में उपलब्ध कराए गए हैं जिनकी संख्या और बढाई जा रही है। राज्य के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाए जा रहे हैं। ग्यारह ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए जबकि आठ की मंजूरी और दी गई है। राज्य के सभी दस बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखने, दस से अधिक बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे जाने की अनिवार्यता कर दी गई है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 5 ऑक्सीजन सिलेंडर अनिवार्य रूप से रखने होंगे।

◆

कोविड के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए सरकार ने राज्य के गांव में गांव स्तरीय कोविड निगरानी समितियों का भी गठन कर कोविड लक्षणों की पहचान, लोगों में लक्षण देख होम आइसोलेशन करने, होम आइसोलेशन में रखे गए लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी रखने का काम इन समितियों को दिया। तब से ये समितियां रात दिन काम में जुटी हैं।

सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। 2 जून को मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में 500 बेड के कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस कोविड केयर सेंटर में 375 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। ब्लैक फंगस (म्यूकरमायोसिस) के मरीजो के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत बेस अस्पताल में 500×2 एलपीएम एवं अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 216 एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया। कुमाऊं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले ये पहले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं। मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय में मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं एवं भोजन आदि की गुणवत्ता को भी परख रहे हैं।

17 मई 2021 को अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित संयुक्त सिविल मिलिट्री कोविड केयर अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया। रानीखेत में 50 बेड क्षमता वाले संयुक्त अस्पताल में 10 बेड ऑक्सीजन युक्त बनाए गए हैं। यह अस्पताल कुमाऊं रेजीमेंट सेंटर एवं जिला प्रशासन अल्मोड़ा के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत से पहले ही हम सीएचसी, पीएचसी स्तर के अस्पतालों को मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए लिण्डे इण्डिया के लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति रिकार्ड समय में अंडरग्राउंड केबलिंग पूर्ण कर उपलब्ध करा केन्द्र सरकार का भी दिल जीत लिया।

केंद्र द्वारा की जा रही मदद के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते मुख्यमंत्री, तीरथ सिंह रावत

कोरोना टीकाकरण मुफ्त किए जाने पर तीरथ ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने देश में 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले समस्त भारतीयों का कोरोना टीकाकरण मुफ्त किए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा इस संकटकाल में देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए भी सीएम तीरथ ने पीएम मोदी जी का आभार व्यक्त किया।

सीएम ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने हेतु राज्य को भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की सहायता मिली है। प्रधानमंत्री जी के सद्प्रयासों से डी.आर.डी.ओ. ने रिकॉर्ड समय में ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में पांच-पांच सौ बेड के अस्पताल बनाए हैं, जिसका राज्य की जनता को लाभ मिल रहा है।

सीएम ने पीएम से राज्य में मानसून व आपदा के दौरान सड़कें बंद होने की स्थिति में ग्रामीण इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटे का आवंटन करने की भी मांग की।

लांग कोविड का लंबा साया

डॉक्टरों ने कोविड से ठीक होने के बाद भी कायम लक्षणों को लेकर चेताया. ये वायरस के शरीर से चले जाने के लंबे वक्त बाद भी मरीज को खतरे में डाल सकते हैं

सोनाली आचार्जी

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

बेंगलूरू के बनासवाड़ी मोहल्ले में रहने वाले भाटिया परिवार में अप्रैल की शुरुआत में कोविड वायरस ने दस्तक दी. दूसरी लहर अभी उतनी बर्बर नहीं हुई थी. पांच सदस्यों के इस परिवार के ज्यादातर सदस्यों को सर्दी-जुकाम और बुखार हुआ. इनमें 18 और 17 बरस के दो किशोर भी थे. सबने पांच दिनों तक ऐंटीबायोटिक और विटामिन लिए और ठीक हो गए. केवल 70 बरस की दादी को अंदरूनी सूजन खत्म करने के लिए स्टेरॉयड देने पड़े. उन्होंने राहत की सांस ली कि उन्हें बदतरीन नहीं झेलना पड़ा. लक्षण खत्म होते ही वे सामान्य कामकाज में जुट गए. मगर दो हफ्तों के भीतर वह बुरा सपना फिर लौट आया. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म में मैनेजर 45 वर्षीय अभिषेक भाटिया कहते हैं, ''पता चला कि मेरी मां को पार्किंसन हो गया है. खून का एक थक्का शायद उनके दिमाग में चला गया था. इलाज के दौरान उन्हें थक्के बनने से रोकने वाली दवाइयां नहीं दी गईं.'' शरीर में दर्द और बहुत थकान के कारण उनकी पत्नी रसोई के काम नहीं कर पा रही थीं. बच्चों ने 'ब्रेन फॉग' (दिमागी धुंध) की शिकायत की. वे न ध्यान केंद्रित कर पा रहे थे और न साफ सोच पा रहे थे. खुद भाटिया को भी टेस्ट नेगेटिव आने के छह दिन बाद हल्का बुखार हो गया, जो अंदरूनी शोथ या सूजन का संकेत था. बाद में उनके एक हाथ में खून के थक्के मिले. वे कहते हैं, ''टेस्ट नेगेटिव आए दो महीने हो चुके हैं पर अभी भी हममें से किसी में इतनी ताकत नहीं है कि पहले की तरह रह पाएं.''

कोविड के लक्षणों की चाल-ढाल अब भी इतनी अनजान है कि विशेषज्ञ और मरीज दोनों हैरान हैं. इनमें आमतौर पर शरीर या मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिरदर्द, गंध या स्वाद का जाना और सांस उखड़ना शामिल हैं. बीते डेढ़ साल के दौरान हासिल जानकारियों से तस्दीक हुई कि कोविड से उबरे बहुतायत लोगों को 14 दिन (वायरस से

शरीर के लड़ने और जीतने का औसत समय) बाद भी इनमें से एक या अधिक लक्षण महसूस होते हैं. स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन ने मई 2021 में दुनिया भर के 9,751 मरीजों का अध्ययन किया और पाया कि मध्यम या गंभीर संक्रमण से गुजर चुके 70 फीसद लोगों में ठीक होने के महीने भर बाद 84 अलग-अलग लक्षण देखे गए.

हल्के लक्षणों वाले मरीजों की स्थिति भी बेहतर नहीं है. जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन या जेएएमए ने मई 2021 में स्वीडन में अध्ययन किया. इसमें पाया गया कि हल्के कोविड संक्रमण से गुजरे 10 लोगों में से एक ठीक होने के आठ महीने बाद भी अपना सामान्य कामकाज पूरी तरह नहीं कर पा रहा था. औसतन कम से कम तीन हफ्ते मरीजों को लक्षण महसूस होते रहे. फोर्टिस अस्पताल हीरानंदानी, मुंबई की आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. फरह इंगले कहती हैं, ''कोविड के बाद के असर केवल अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीज ही महसूस नहीं करते. मेरे यहां घर पर ही बुखार और खांसी का इलाज करवाने वाले ऐसे मरीज हैं जिन्हें शुरुआती लक्षण खत्म होने के आठ महीने बाद भी जोड़ों में गंभीर दर्द है. मेरे यहां ऐसे मरीज भी थे जिन्हें पहले दो हफ्ते कोई लक्षण नहीं थे और बाद में तीव्र थकान और पेट की परेशानियों जैसे लक्षण विकसित हो गए. चूंकि वे महज दो हफ्ते पहले ही पॉजिटिव हुए थे इसलिए अनुमान ही लगा सकते हैं कि ये लक्षण वायरस की वजह से हैं.'' महामारी की शुरुआत से ही कोविड वार्ड में काम कर रहीं डॉ. इंगले कहती हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद इलाज के लिए लौट रहे मरीजों की तादाद अप्रैल 2021 में दूसरी लहर आने के बाद अच्छी-खासी बढ़ी है.

लांग कोविड क्या है?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या आइसीएमआर की नेशनल कोविड टास्क फोर्स के अनुसंधान कार्य समूह के प्रमुख एन.के. अरोड़ा कहते हैं, ''हम शरीर पर वायरस के छोटे या लंबे वक्त प्रभावों के बारे में अब पूरी तरह नहीं जानते. मगर इतना जानते हैं कि ठीक होने के छह महीने या एक साल बाद भी मरीजों में नए लक्षण प्रकट हो सकते हैं. इसे लांग कोविड (लंबा कोविड) कहा जाता है.'' आइसीएमआर के मुताबिक, किसी शख्स को कोविड का टेस्ट नेगेटिव आने के चार या 12 हफ्तों बाद लक्षण होते हैं तो इसे पोस्ट-कोविड सिंड्रोम या पीसीएस मानकर इलाज किया जाना चाहिए. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ''अगर लक्षण 12 हफ्तों बाद भी जारी रहते या दोबारा दिखाई देते हैं तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए. अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस व्यक्ति को फिर से कोविड संक्रमित माना जाएगा. लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो इसे लांग कोविड मानकर इलाज किया जाना चाहिए.'' ज्यादातर डॉक्टरों का कहना है कि दूसरे दौर के ज्यादातर लक्षण पहले लक्षणों के प्रकट होने के चार हफ्ते बाद शुरू होते हैं. सभी लक्षण गंभीर स्थिति का संकेत नहीं हैं, लेकिन अगर डायग्नोसिस और इलाज न किया जाए तो इनसे छोटे या लंबे वक्त में

''कोविड ठीक होने के छह महीने से साल भर के दौरान मरीजों में नए लक्षण उभरते हैं तो इसे लांग कोविड कहा जाता है''

एन. के. अरोड़ा

प्रमुख, अनुसंधान कार्य समूह, नेशनल कोविड टास्क फोर्स, आइसीएमआर

मलाइका अरोड़ा
47 वर्ष
अभिनेत्री

एएफपी/गेट्टी इमेजेज

कोरोना की मेरी कहानी

“मुझे अपने योग दिनचर्या में वापस आने में 32 हफ्ते लग गए”

जब मैं सितंबर 2020 में जांच में पॉजिटिव पाई गई, तो मुझे लगा कि मेरा मामला भी बहुत सारे उन लोगों जैसा ही होगा जिनमें लक्षण नहीं था. बहरहाल, मुझे जांच में नेगेटिव आने में 22 दिन लग गए. वे मुश्किल इम्तिहान के दिन थे. वायरस और दवाओं की वजह से मैं खुद की हालत खराब होते देख रही थी. मुझमें इतनी ऊर्जा भी नहीं थी कि मैं सांसों की कसरत कर सकूं. मैं पांच तक गिनती थी और कहती थी, 'हे भगवान, बस और नहीं.' मैं बस खाती और सोती थी.

आखिरकार, जब मैं जांच में नेगेटिव आ गई, तो मैंने ईमानदारी से सोचा कि मैं ठीक हो गई. मैं दौड़ने के लिए निकली और तब जाकर मुझे इसकी चोट का पता चला—रिकवरी रातोरात नहीं हासिल की जा सकती थी. मेरे जोड़ों में तेज दर्द हो रहा था और मैं सांस लेने के लिए हांफ रही थी. पचीसवें दिन, मैं *इंडियाज बेस्ट डांसर* (सोनी का एक शो) की शूटिंग पर लौटी. वह बेहद थकाऊ था. मेरे पास इतनी ऊर्जा भी नहीं थी कि मैं फिनाले में परफॉर्म कर पाऊं, लेकिन मैं डटी रही. रिहर्सल लंबे समय तक चली और मैं एक बार में सिर्फ 30-45 मिनट ही प्रैक्टिस कर पा रही थी.

मैंने शूटिंग खत्म करने के बाद योग शुरू कर दिया और सर्वेश (शशि, इंस्ट्रक्टर और योग ऐप सर्व के संस्थापक) बड़े लगन से मेरे साथ काम करते रहे, वे भी देख पा रहे थे कि मैं संघर्ष कर रही थी.

दिसंबर तक, मैं बमुश्किल ही कोई काम कर पा रही थी. बाल गिरने लगे, जोड़ों में दर्द, सांस फूलने और नींद में भी समस्या आई. मेरी न्यूट्रिनशनिस्ट डॉ. विशाखा शिवदासानी ने मुझे कहा कि मैं अकेली नहीं हूं और बहुत सारे लोग इस दौर से गुजर रहे हैं. जब हाल में मैंने इंस्टाग्राम पर यह शेयर किया कि मुझे कोविड-पूर्व दिनचर्या में लौटने में 32 हफ्ते लगे तो कई लोगों ने कहा कि उनका तजुर्बा भी ऐसा ही रहा. मैं ठीक से वर्कआउट जनवरी में ही करना शुरू कर पाई. कोविड बाद का संघर्ष सचाई है. इसको नजरअंदाज मत कीजिए.

—सुहानी सिंह से बातचीत पर आधारित

बीमारियां हो सकती हैं.

पीसीएस या उसकी संभावना बढ़ाने वाले लक्षणों और जोखिम के कारकों से जुड़ा राष्ट्रीय डेटा मौजूद नहीं है और ऐसे में देश के अनेक कोविड वार्डों के डॉक्टरों की बातों पर ही भरोसा करना होगा. वे मायूसी की तस्वीर ही पेश करते हैं. दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉ. विवेक नांगिया कहते हैं, ''हमने बहुत सारे मरीजों में कोविड के बाद के लक्षण देखे हैं. उनमें से ज्यादातर लगातार शरीर दर्द, थकान, सांस उखड़ने, बेचैनी, आवाज में बदलाव और यहां तक कि याददाश्त में चूक की शिकायतें करते हैं.'' दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. बी.एल. शेरवाल कहते हैं कि ठीक होने के बाद भी उनके 80–90 फीसद मरीजों को सूखी खांसी, कमजोरी और तेजी से पानी की कमी होने लगी. ''उनमें से कई तो घर में एक से दूसरे कमरे में जाने सरीखे रोजमर्रा के आसान काम नहीं कर पाते.''

दूसरी लहर में वायरस के नए डेल्टा रूपों के बी.1.617.1 और बी.1.617.2 वंशजों ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया. इसके चलते डॉक्टरों ने पीसीएस से जुड़े लक्षणों में भी बदलाव देखे. हालांकि इनमें सीधा संबंध होने की वैज्ञानिक अभी तस्दीक नहीं हुई है. डॉ. शेरवाल कहते हैं, ''ब्रेन फॉग इस बार ज्यादा आम है.'' कोविड से ठीक हुए दूसरे मरीज लगातार हल्का बुखार बने रहने की शिकायत करते हैं.

पीसीएस को बेहतर समझने के लिए विशेषज्ञ मरीजों को दो वर्गों में बांटने की सलाह देते हैं. एक वे जिन्हें हल्के से मध्यम कोविड हुआ (जो इलाज से या उसके बगैर घर पर ही ठीक हो गए) और दूसरे वे जिन्हें गंभीर संक्रमण हुआ (अस्पताल में, आइसीयू में भर्ती किया गया, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, और/या स्टेरॉयड देने पड़े). वे दोनों समूहों में पीसीएस का जोखिम अलग-अलग बताते हैं. डॉ. शेरवाल कहते हैं, ''हल्के संक्रमण वाले मरीजों में लक्षण जिंदगी के लिए खतरा नहीं हैं. लेकिन गंभीर मामलों में थ्रोंबोसिस और इनफ्लेमेशन जानलेवा हो सकता है.''

> **“कोविड में दिल की मांसपेशियों में सूजन के कारण प्लेक फूट सकते हैं जिससे थ्रोंबसिस की आशंका बढ़ जाती है. खून के थक्के धमनी पूरी तरह बाधित हो जाती है और दिल का दौरा पड़ सकता है ”**
>
> **डॉ. राजीव राठी**
>
> *कॉर्डियोलॉजिस्ट, मैक्स अस्पताल, साकेत, दिल्ली*

खामोश हत्यारे?

इनफ्लेमेशन (सूजन) और थ्रोंबोसिस (खून के थक्के जमना) कोविड के दो बेहद अहम रोगजनक तरीके हैं. सूजन स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे शरीर नुक्सानदायक संक्रमण या चोट से लड़ता है. जब रोग प्रतिरोधक प्रणाली को शरीर में किसी कोशिका को नुक्सान पहुंचने का एहसास होता है तो वह आक्रमण रोकने के लिए रसायन छोड़ती है. इन रसायनों का स्राव होते रहने से वह घटना घटित होती है जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं और ऐसे में

इनफ्लेमेशन दूसरे स्वस्थ ऊतकों और अंगों को नुक्सान पहुंचा सकता है. ऐसा सबसे ज्यादा बुखार में होता है, पर खून में सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) के स्तर से भी इनफ्लेमेशन का फैलाव जाना जा सकता है. डॉ. नांगिया कहते हैं, ''कोविड-19 से पैदा इनफ्लेमेशन का असर कई अंगों पर पड़ सकता है, इनफ्लेमेशन से फेफड़ों में निमोनिया या किडनी और लिवर को हुए नुक्सान का संकेत मिल सकता है.'' इनफ्लेमेशन से जुड़ी परेशानियां आमतौर पर उन लोगों में देखी गई हैं जिन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं और उन बुजुर्गों में भी जिनकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली पहले की बीमारियों या दवाइयों की वजह से तहस-नहस हो गई है.

दूसरी तरफ, थ्रोंबोसिस का मतलब है बाहरी तत्व की मौजूदगी में खून में थक्के जमने की प्रवृत्ति. ये थक्के शिराओं या धमनियों में बनते हैं और वक्त पर दवाइयों से खत्म न किए जाएं तो पल्मोनरी थ्रोंबोसिस, दिल की परेशानियां, लकवा या किडनी को नुक्सान पहुंचा सकते हैं. डॉ. नांगिया कहते हैं, ''हमने ऐसे मरीज देखे हैं जिन्हें हाथों और पैरों में थक्के जम गए.'' थ्रोंबोसिस की आशंका उनमें ज्यादा होती है जो बीमारी के कारण लंबे समय से बिस्तर पर हैं, बुजुर्ग हैं, कैंसर से ग्रस्त हैं या जिनका थ्रोंबोसिस या थ्रोंबोफीलिया का पुराना इतिहास रहा है.

इनफ्लेमेशन या थ्रोंबोसिस को जो बात सचमुच खतरनाक बना देती है, वह है इनका शरीर में खामोश विस्फोट. इनकी निगरानी और इलाज न किया जाए तो ये कोविड से ठीक हो चुके उन मरीजों के अंगों को भी नुक्सान पहुंचा सकते हैं जिन्हें ऑक्सीजन का स्तर स्थिर रहने से अस्पताल में दाखिल नहीं करना पड़ा और घर पर ही इलाज से ठीक हो गए.

डॉक्टरों का कहना है कि यह तो पता है कि थक्के जमने से अंगों को नुक्सान पहुंच सकता है, लेकिन यह बता पाना मुश्किल है कि कोविड के बाद होने वाले थ्रोंबोसिस से मौत हो सकती है या नहीं. मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अतुल इंगले कहते हैं, ''थ्योरी में तो यह दर्ज है लेकिन इस पर हमें ज्यादा व्यावहारिक अध्ययनों की जरूरत है.''

> **“कोविड प्रभावित फेफड़ों की सूजन से फाइब्रोसिस की आशंका रहती है. ऊतकों में हवा की आवाजाही न होने से सांस उखड़ने लगती है ”**
>
> **डॉ. विवेक नांगिया**
>
> *पल्मोनोलॉजिस्ट, मैक्स अस्पताल, साकेत*

दिल और फेफड़ों को खतरा

पुणे के ट्रैवल एजेंट 39 वर्षीय मानिक बिश्वास की 2 मई को अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. उनके परिवार को सहसा यकीन नहीं हुआ. मौत से 24 दिन पहले बिश्वास और उनकी पत्नी कृतिका कोविड से उबरे थे. उन्हें रोज सुबह एक साथ साइकिल चलाना अच्छा लगता था. कोविड के लक्षण खत्म होने के एक हफ्ते बाद उन्होंने ''सामान्य'' कामकाज शुरू कर दिया. कृतिका कहती हैं, ''हमें ठीक लग रहा था और हमने शरीर पर नजर रखने की बात सोची तक नहीं.'' दोनों का घर पर ही इलाज हुआ था, लेकिन स्टेरॉयड देने और कोविड से पैदा अंदरूनी सूजन के कारण मानिक कोविड के बाद की पेचीदगियों के भारी जोखिम से घिर गए. कृतिका कहती हैं, ''संक्रमण के दौरान तीव्र सूजन के कारण उनकी धमनी की कोई परत 'खुल गई', जिससे खून का थक्का जमा और फिर दिल का दौरा पड़ गया.''

कोविड से ठीक हो चुके युवाओं की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु की कई घटनाएं हुई हैं. हालांकि उनकी तादाद बता पाना मुश्किल है. उम्र बढ़ने के साथ हम सभी की धमनियों में किसी न किसी हद तक ब्लॉकेज होता है, लेकिन जब तक ये 50-70 फीसद से ज्यादा नहीं होता, हमें कोई लक्षण महसूस नहीं होते और इसलिए हम जोखिम से अनजान होते हैं. मगर रिसर्च से पता चला कि कोविड के कारण दिल की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है. जेएएमए कार्डियोलॉजी के जुलाई 2020 के अंक में प्रकाशित दो जर्मन अध्ययनों में 57 कोविड-19 मरीजों में से 78 फीसद में हार्ट इमेजिंग के नतीजे असामान्य पाए गए. उनमें से ज्यादातर में ठीक होने के बाद भी कार्डिएक इनफ्लेमेशन मौजूद था. दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में ट्रांस-रेडियल इंटरवेंशनल प्रोग्राम के डायरेक्टर और हृदय विशेषज्ञ डॉ. राजीव राठी बताते हैं: ''शरीर में दाखिल होते ही यह वायरस तकरीबन सभी अंगों में इनफ्लेमेटरी प्रतिक्रिया शुरू कर देता है. दिल में भी एसीई2 रिसेप्टर होता है, ये वही प्रोटीन है जिसे वायरस अपने कांटों से पकड़कर शरीर में दाखिल होता है और इसलिए मरीजों के दिल की मांसपेशियों में इनफ्लेमेशन की आशंका होती है.''

दिल पर वायरस संक्रमणों का बुरा असर पड़ने के प्रमाण पहले से मौजूद हैं. 2019-20 के फ्लू के सीजन में हुए जेएएमए कार्डियोलॉजी के एक अध्ययन से पता चला कि इसमें शामिल 94 फीसद मरीजों के दिल की सेहत पर वायरस का असर पड़ा था. दिल को जो सबसे आम परेशानियां होती देखी गईं, उनमें थीं लो इजेक्शन फ्रैक्शन (जब दिल पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता, जो अक्सर दिल के नाकाम होने का संकेत होता है) और धमनियों में रुकावट जिससे अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है. डॉ. राठी विस्तार से बताते हैं, ''कोविड से संक्रमित मरीजों में दिल की तकलीफ की घटनाएं बढ़ी हैं. वायरल संक्रमण की वजह से कोरोनरी ट्री अस्थिर हो जाता है. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनके दिल में पहले से कितना ब्लॉकेज है क्योंकि कुछ प्लैक तो स्वाभाविक रूप से बनता है और जब तक गंभीर न हो लोगों पर असर नहीं डालता. लेकिन कोविड का हमला होने पर दिल की मांसपेशियों में सूजन की वजह से ये प्लैक फूट सकते हैं. यह फूटन लूमन (धमनी के भीतरी भाग) के भीतर होती है, जिससे थ्रोंबोसिस की आशंका बढ़ जाती है. थक्के बनने पर फूटी हुई धमनी शत प्रतिशत ब्लॉक हो सकती है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है.'' खून का डी-डायमर टेस्ट इनफ्लेमेशन और थ्रोंबोसिस की आशंका पर नजर रखने में मदद कर सकता है. डॉ. राठी बताते हैं, ''डी-डाइमर वह मानदंड है जो मरीज में खून के थक्के जमने की बहुत ज्यादा संभावना या ज्यादा जोखिम के बारे में बताता है. कोविड के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, स्टेरॉयड दिए गए और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल होना पड़ा, उनमें खून के थक्के जमने के आसार पर नजर रखने की जरूरत है.''

अलबत्ता यह अब भी पता नहीं है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों को कितने लंबे वक्त तक दिल की परेशानियां होने का खतरा रहता है. डॉ. राठी कहते हैं, ''कोविड से ठीक होने के बाद लंबे समय की कार्डिएक हेल्थ के बारे में हमें अब भी नहीं पता. अस्थिर प्लैक एक या दो महीने के दौरान अलग-अलग ढंग से पेश आ सकते हैं. जरूरी नहीं कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही दिल का दौरा पड़े. अगर प्लैक अस्थिर रहता है और मरीज कोविड के बाद जल्द भारी शारीरिक काम शुरू कर देता है तो जोखिम बढ़ जाता है.'' हृदय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि कोविड से

अंगों पर खतरा

कोविड ठीक हो जाने के बावजूद शरीर के कुछ अंग लंबे समय तक प्रभावित रह सकते हैं

फेफड़े
अस्थायी फाइब्रोसिस या फेफड़े के ऊतकों पर संभावित निशान कोविड के बाद सांस फूलने की वजह है

लिवर
दिल को चोट, थ्रोंबोसिस या आंतरिक सूजन के फलस्वरूप भी लिवर फंक्शन टेस्ट असामान्य हो सकता है

मांसपेशियां
कोविड के चलते आई सूजन की वजह से जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द रहता है क्योंकि शरीर को उबरने में समय लगता है

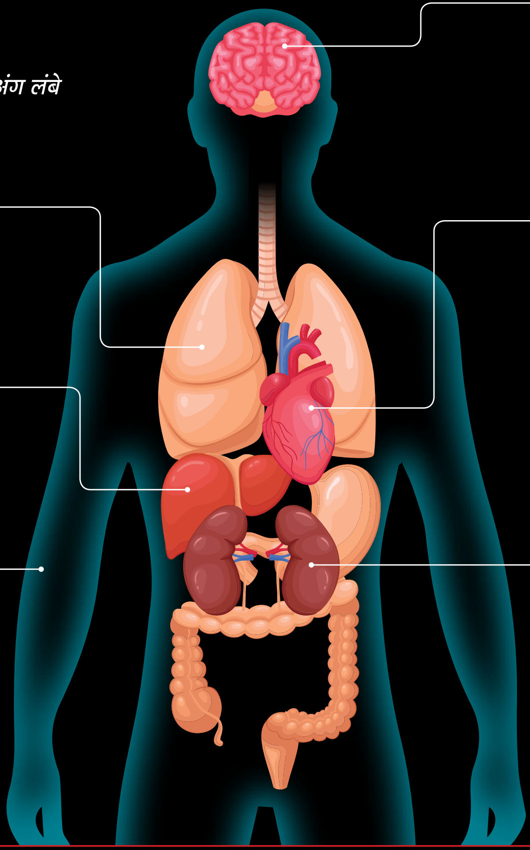

मस्तिष्क
थक्कों के मस्तिष्क में पहुंचने से स्ट्रोक, मस्तिष्क के विकार हो सकते हैं; कोविड के मामूली लक्षण वाले मरीजों में ब्रेन फॉग और गंध व स्वाद न आने की दिक्कत हो सकती है

हृदय
हृदय की मांसपेशियों में इनफ्लेमेशन की वजह से आर्टीरियल प्लैक अस्थिर हो जाती हैं, इससे लंबे वक्त में हृदय को खासा नुक्सान पहुंचता है और उसके काम करने की गति कम हो जाती है या अचानक हार्ट अटैक होता है; दिल की ओर जाते थक्के धमनियां जाम करते हैं जिससे दिल काम करना बंद कर देता है

किडनी
किडनी के ऊतकों में कोविड का पाया जाना अपने आप में इसके किडनी की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने का सूचक हो सकता है; कोविड के दौरान कम तरल पदार्थ लेने से भी किडनी को बहुत नुक्सान पहुंचता है

कब कराएं जांच

कोविड की तीव्रता के मुताबिक ये टेस्ट साप्ताहिक या मासिक कराए जा सकते हैं; बुनियादी पैरामीटर की निगरानी से स्वास्थ्य चिंताओं का पता लगाया जा सकता है. इन जांचों को समझने के लिए डॉक्टर से परामर्श महत्वपूर्ण है

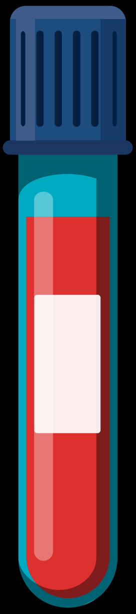

सी-रिएक्टिव प्रोटीन ब्लड टेस्ट
इससे शरीर में गंभीर अंदरूनी इनफ्लेमेशन का पता चलता है

डी-डायमर ब्लड टेस्ट
यह ब्लड थ्रोंबोसिस या थक्के जमने की संभावनाओं का सूचक है

कंप्लीट ब्लड काउंट
इससे किसी दूसरे संक्रमण या थ्रोंबोसिस का पता लगाने में मदद मिलती है

लिवर और किडनी की सेहत
खून की जांच से ही इन दोनों अंगों में जख्म का पता लग सकता है

ग्राफिक्स : तन्मय चक्रवर्ती

उबरने के लिए खुराक

कोविड के बाद अपना आहार प्रबंधन कैसे करें

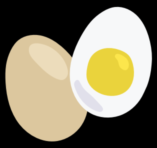

प्रोटीन लांग कोविड से पैदा हुई कमजोरी को पर्याप्त प्रोटीन लेकर दूर किया जा सकता है. इसके लिए सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है; प्राकृतिक तौर पर एनिमल या प्लांट प्रोटीन जैसे दालें, पनीर, टोफू आदि किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत को पूरा कर सकते हैं. शरीर के वजन के मुताबिक प्रति किलो एक ग्राम प्रोटीन की सिफारिश की जाती है. ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर बोझ पड़ता है.

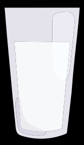

कैल्शियम
जोड़ों का दर्द और कमजोरी दूर करने में मददगार. दूध के अलावा दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद, 1 चम्मच तिल के दाने रातभर पानी में भिगोकर खाने से भी कैल्शियम का स्तर बढ़ता है

आयरन इससे हीमोग्लोबिन का स्तर ऊंचा रखने में मदद मिलती है. मरीज के आहार का पांचवां हिस्सा मौसमी फल होना चाहिए. एक हिस्सा 50 से 70 ग्राम फल का होता है.

ड्राइ फ्रूट

कोविड से उबर चुके मरीज अपनी मीठा खाने की इच्छा को ड्राइ फ्रूट्स से शांत कर सकते हैं. चीनी और प्रोसेस्ड फूड को ज्यादा लेने से बचना चाहिए

पर्याप्त तरल पदार्थ लें सूप, ताजा जूस और पर्याप्त पानी से शरीर में तरल की मात्रा बनी रहती है

–इनपुट डॉ. मेघा जेनिना-, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, मैक्स अस्पताल

उबरे लोगों को काफी समय आराम करना चाहिए, फिर बीमारी की तीव्रता चाहे जितनी रही हो. दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. राजीव पासी कहते हैं, ''कोई कभी जान नहीं सकता कि आपके दिल के भीतर क्या चल रहा है. इसलिए बेजा परिश्रम न करना ही बेहतर है. कुछ महीने आराम कीजिए और फिर धीरे-धीरे गतिविधियों का स्तर बढ़ाइए. लांग कोविड कई बार दिल के लक्षणों पर खामोश असर डाल सकता है, आप इसे हल्के में लेते हैं तो यह जानलेवा भी हो सकता है.''

फेफड़ों पर कोविड के प्रभाव बीमारी के पहले और बाद में भिन्न हो सकते हैं. कोविड के दौरान मरीजों को न्यूमोनिया और हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होने का जोखिम होता है. कोविड के बाद मरीजों को फेफड़ों के स्थायी फाइब्रोसिस (ऊतकों का मोटा या चोटिल होना), पल्मोनरी एंबोलिज्म (फेफड़े के ऊतकों में थक्के जमना) और लंबे वक्त तक सांस उखड़ने की परेशानियां हो सकती हैं. यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल में छपे मई 2021 के एक अध्ययन से पता चला कि इसमें शामिल 14 फीसद मरीजों को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही पल्मोनरी एंबोलिज्म का खतरा था. डॉ. नांगिया कहते हैं, ''ठीक होने के बाद खून के थक्के जमना बड़ी चिंता की बात है. यह सभी अहम अंगों के लिए खतरा पैदा करता है.'' वे यह भी कहते हैं कि फेफड़ों के संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, कुछ धीरे ठीक होते हैं और कुछ फिर बीमार पड़ सकते हैं. वे कहते हैं, ''ऐसे भी मामले हैं जिनमें फेफड़ों का संक्रमण फिर लौटकर इनफ्लेमेशन पैदा कर सकता है (जिसे ग्राउंड ग्लासिंग इफेक्ट भी कहते हैं). ऐसे लोगों में फाइब्रोसिस की आशंका हो सकती है. इसमें फेफड़े दागदार या चोटिल हो जाते हैं, जिससे फेफड़ों की सामान्य सांस लेने की जगह मृत ऊतक में बदल जाती है. उस ऊतक में फिर हवा नहीं आती-जाती, जिससे लोगों के फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और सांस उखड़ने लगती है.''

60 साल से ऊपर के लोगों, धूम्रपान और मदिरापान करने वालों और लंबे समय तक अस्पताल, आइसीयू या वेंटिलेटर पर रहने वाले लोगों में फेफड़ों का फाइब्रोसिस होने के आसार ज्यादा होते हैं. ऐसे मरीजों को ठीक होने के महीनों बाद भी अक्सर ऑक्सीजन के सहारे की जरूरत पड़ती है. कोलकाता के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. अभ्युदय दासगुप्ता कहते हैं, ''मेरे यहां ऐसे मरीज हैं जिन्हें घर पर 2-3 महीनों तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी. कुछ तो ठीक होने के छह महीने बाद भी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते या 10 मिनट से ज्यादा पैदल नहीं चल सकते.''

फेफड़ों का फाइब्रोसिस कोविड से उबरे कई मरीजों के लिए हमेशा की परेशानी बन सकता है. दिल्ली के अपोलो अस्पताल में फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉ. राजेश चावला इसके दो प्रकार बताते हैं. वे कहते हैं, ''एक कोविड के फौरन बाद होने वाला फाइब्रोसिस है, जो सामान्यत: अपने आप ठीक हो जाता है. मगर कुछ लोगों को स्थायी और हमेशा बना रहने वाला फाइब्रोसिस हो सकता है. हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है क्योंकि कोविड को डेढ़ साल ही हुआ है.'' जहां तक फेफड़ों में कोविड का गंभीर संक्रमण झेल चुके लोगों की बात है, विशेषज्ञों के मुताबिक यह समय ही बताएगा कि उनका लांग कोविड कितने वक्त बाद जाएगा.

अन्य अंगों पर असर

दिल और फेफड़ों के अलावा मस्तिष्क और गुर्दे, दो अन्य महत्वपूर्ण अंग हैं जो लांग कोविड के कारण जोखिम में रहते हैं. पोस्टमॉर्टम में इन दोनों अंगों की ओर जाने वाले रक्त में थक्के पाए गए हैं. डॉ. इंगले कहते हैं, ''मरीजों को किसी भी लक्षण से बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी अनदेखी भी नहीं करनी चाहिए. कोई भी लक्षण जैसे बुखार, थकान, शरीर में दर्द, सांस फूलना, या कोई अन्य ऐसी बात है जिसके कारण आपको लगता है कि आपका शरीर अब पहले की तरह काम नहीं कर रहा है या ऐसी कोई चीज जो आपके रोजमर्रा के काम या चलने-फिरने में परेशानी की वजह बन रही है तो इसे डॉक्टर को जरूर बताएं. उसकी जांच और जरूरत पड़ने पर इलाज होना चाहिए.'' स्ट्रोक (दौरे) और ब्रेन फॉग को लांग कोविड से जोड़ा जा रहा है. हालांकि डॉक्टर ब्रेन फॉग, जिसमें लोग लंबे समय तक ठीक से सोच पाने में मुश्किल अनुभव करते हैं, को अस्थायी मानते हैं.

''गंभीर किडनी रोग से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है. कोविड उन लोगों में जोखिम बढ़ा देता है जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है''

डॉ. अतुल इंगले
नेफ्रोलॉजिस्ट, फोर्टिस, मुंबई

कोरोना की मेरी कहानी

''ऐसा लगा जैसे कि कोविड ने मेरी सारी ताकत छीन ली हो''

भूमि पेडनेकर
31 वर्ष
अभिनेत्री

कोविड का मेरा सफर आसान नहीं था. पहले नौ दिन भयावह थे. मेरा बुखार बना रहा, मैं बहुत थकी हुई थी और मेरे शरीर में दर्द हो रहा था—मेरी त्वचा, नाखून, यहां तक कि पलकों तक में पीड़ा थी. मेरी मां के फेफड़ों में फाइब्रोसिस हो गया था और उन्हें 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह बहुत ही परेशानी भरा दौर था और मैं बहुत अलग-थलग और असहाय महसूस कर रही थी. मुझे पता था कि इस बार मुझे सिर्फ पैसे दान करने के अलावा कुछ और भी करना है. इसलिए, मैंने अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल लोगों को चिकित्सा संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए शुरू किया. लेकिन जांच में नेगेटिव आने के ठीक बाद यह काम शुरू करने का मतलब था कि मुझ पर थकान लगातार तारी रहता था और मैं लंबी बातचीत में शामिल नहीं हो सकती थी.

मेरे चेहरे से मेरे शरीर पर पड़ रहे गहन शारीरिक दबाव की झलक दिखती थी. यह दिल तोड़ने वाला था.

I·L·L
BE
THERE
FOR
YOU

आप अपनी तंदरुस्ती के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. मैंने दोबारा काम सिर्फ दो हफ्ते पहले शुरू किया है—टेस्ट में नेगेटिव आने के एक महीने बाद—और मेरे हृदय की शक्ति (कार्डियो स्टेमिना) अब पहले जैसी नहीं रह गई है. मुझे महसूस होता है कि कोविड ने मेरी सारी ताकत खींच ली है. मुझे डॉक्टर और मेरे ट्रेनर ने बताया कि कोविड से बाहर आना एक 'प्रक्रिया' है और मुझे इसे सहज भाव से लेना होगा.

मुझे उम्मीद है कि मैं जुलाई तक पटरी पर आ जाऊंगी. बेशक मैं काम पर दोबारा जाने को लेकर बेचैन हो उठती हूं, खासकर मैंने अभी वैक्सीन नहीं ली है, लेकिन आपको इसका सामना तो करना ही होगा और अधिकतम कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा क्योंकि आखिकार, रोजी तो सबको कमानी ही होगी. कोविड की वजह से मैं अपने तीन निकट परिवारवालों को खो चुकी हूं और अपनी आंटी को खतरनाक रूप से इससे जूझते भी देखा. अब मैं यह जानती हूं कि मैं सिर्फ काम के लिए ही बाहर निकलूंगी.

*—**सुहानी सिंह** से बातचीत पर आधारित*

ऐसे मामले दुर्लभ हैं जिसमें लोगों में पार्किंसंस रोग या तंत्रिका संबंधी अन्य विकारों के पूर्व लक्षण थे और कोविड उन विकारों की शुरुआत का कारण बना.

गंभीर किडनी रोग या सीकेडी के रोगियों के लिए भी लांग कोविड खतरनाक है. उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों में सीकेडी होने का खतरा अधिक होता है इसलिए इस बात की पूरी आशंका रहती है कि कोविड के मामले में उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ जाए. मुंबई के फोर्टिस अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अतुल इंगले कहते हैं, ''सीकेडी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है. उन लोगों के लिए जोखिम और भी अधिक है जिनका गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है.''

कोविड से गुर्दे को गंभीर क्षति भी हो सकती है और इसके लिए वायरल लक्षणों के कम होने के बाद लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है. डॉ. अतुल इंगले बताते हैं, ''कोविड रोगियों में डिहाइड्रेशन (शरीर में जल की कमी) प्री-रीनल इंजरी (ऐसी क्षति जिससे गुर्दा काम करना बंद कर सकता है) का कारण बनता है लेकिन अगर शरीर में पानी की कमी दूर कर दी जाए तो वे तेजी से ठीक भी हो जाते हैं. कोविड-19 सेप्सिस जैसे साइटोकाइन स्टॉर्म को भी शुरू करता है. अगर स्टॉर्म शुरू हो जाए तो उस दौरान, पीड़ित को ट्यूबलर नेक्रोसिस या गुर्दे को गंभीर नुक्सान हो सकता है. ऐसी स्थिति में रिकवरी कितनी होगी इसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता. सौ प्रतिशत रिकवरी नहीं हो सकती और इसमें दो सप्ताह से तीन महीने तक का समय लग सकता है. फिर एक तीसरी श्रेणी है जिसमें कोविड के उपचार के लिए दी जाने वाली कुछ दवाओं के परिणामस्वरूप रोगियों में ट्यूबलोइंटरस्टीशियल नेफ्राइटिस (गुर्दे की नलिकाओं में सूजन) हो जाता है. अगर समय रहते दवाओं को बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाता है.'' कोरोना वायरस स्वयं भी नेफ्रॉन-ग्लोमेरुलोपैथीज (गुर्दे में रक्त वाहिकाओं की क्षति) का कारण बनता है. डॉ. अतुल इंगले बताते हैं, ''चीन में, पोस्टमॉर्टम में गुर्दे के ऊतकों में वायरस पाया गया था. हम नहीं जानते कि यह मौत का कारण बना था या नहीं, लेकिन गुर्दे के ऊतकों में वायरस का पाया जाना संकेत है कि इससे ग्लोमेरुलोपैथी भी हो रही है.''

कोविड की घातक दूसरी लहर से लाखों लोग उबर चुके हैं, कोविड के बाद के लक्षणों का राष्ट्रीय डेटाबेस और साथ ही पोस्टमॉर्टम के ज्यादा मामलों के गहन अध्ययन, डॉक्टरों को लांग कोविड के जोखिम कारकों और लक्षणों का बेहतर अनुमान लगाने में मदद कर सकता है. गुलेरिया कहते हैं, ''कोविड के बाद देखभाल के लिए हमें अनुसंधान समर्थित बहु-विषयक (मल्टी डिसिप्लिनरी) दृष्टिकोण की जरूरत है. वायरस किसी अंग को नहीं बख्शता.''

बंदीप सिंह

रीना सिंह 45 वर्ष
फैशन डिजाइनर और संस्थापक, इका कोर

कोरोना की मेरी कहानी

“कोविड मेरे शरीर पर प्रसव से ज्यादा भारी पड़ा”

अप्रैल के मध्य में मुझे, मेरे पति और दोनों बच्चों को कोविड हो गया. मेरा वायरल लोड बहुत अधिक था, शायद इसलिए कि मुझे संक्रमण कई जगहों से हुआ. टीकाकरण के तीसरे दिन से मुझमें लक्षण उभरने लगे थे. असल में, वैक्सीन को लेकर पहले दो दिन में शरीर की प्रतिक्रिया मेरे पूरे कोविड संक्रमण की अवधि की तुलना में अधिक बुरी थी. तीसरे दिन मैं काम पर गई, लेकिन आधे घंटे में वापस लौटना पड़ा क्योंकि खबर मिली कि मेरे बेटे की सेहत ठीक नहीं है.

जांच में पॉजिटिव आने के बाद मुझे ऐंटीबायोटिक्स और स्टेरॉयड का भारी कॉकटेल की दवा दी गई. घर पर ऑक्सीमीटर में एसपीओ2 स्तर में कोई खास कमी नहीं दिख रही थी. मुझे दिनभर घबराहट होती थी. मुझे लगता था कि शायद ऐंटीबायोटिक्स और स्टेरॉयड ने फायदे से अधिक नुक्सान पहुंचा दिया. हालांकि मेरे सभी पैरामीटर सही हो गए थे. दस दिनों के बाद जाकर मुझमें इतनी ताकत आ पाई कि मैं टहल सकूं. मैं रोज छत पर 5 से 10 मिनट टहलती थी, लेकिन धीमे से चलने के बावजूद मेरी धड़कनें तेज हो जाती थीं. 14 दिनों के बाद मैं घर से बाहर निकली और 200-300 मीटर चलने के काबिल हो गई लेकिन उसके बाद धड़कनें फिर तेज हो जाती थीं. ऐसा अगले 10 दिनों तक रहा. पूरी जिंदगी में धाविका रही हूं, मैं कठोर व्यायाम करती थी और अपने खान-पान को लेकर भी मैं काफी सजग रहती हूं.

लेकिन अभी भी, करीब दो महीनों के बाद, मुझे एक साथ कई काम करने में दिक्कत होती है. अब मैं एक घंटे तक टहल सकती हूं लेकिन मैं भागना तब तक शुरू नहीं करूंगी जब तक मैं सौ फीसद सही महसूस न करने लगूं. मेरा हाजमा भी कतई दुरुस्त नहीं है. मेरा मासिक चक्र गड़बड़ हो चुका है और सोने का पैटर्न भी अनियमित हो गया है. यह मेरे शरीर पर प्रसव से भी ज्यादा मुश्किल रहा है.

*—**चुमकी भारद्वाज** से बातचीत पर आधारित*

कोविड के बाद, सेहत का ख्याल

पिछले साल अगस्त में, राजीव गांधी सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल देश का पहला अस्पताल था जिसने विशेष रूप से उन रोगियों के लिए ओपीडी खोली जो कोविड से ठीक हुए थे. ओपीडी सेवाएं इस साल दूसरी लहर के दौरान भी जारी रहीं. कैब ड्राइवर 48 वर्षीय फारूक मोहम्मद कोविड-19 के बाद इलाज कराने यहां लखनऊ से आए थे. वे बताते हैं, ''इस साल मार्च के अंत में मैं कोविड से उबर चुका था. पूरे अप्रैल, मुझे बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी रही. कई रातों को तो मेरे जोड़ों में ऐसा महसूस हुआ जैसे वे टूट जाएंगे. लेकिन जो लोग कोविड-पॉजिटिव नहीं थे उनके लिए बहुत कम ओपीडी सेवाएं उपलब्ध थीं. मुझे दवाओं की नहीं, मुझे फिजियोथेरेपी की जरूरत थी. शरीर के दर्द के लिए फिजियोथेरेपी लेने के दौरान मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में ठहरा था.''

डॉ. शेरवाल कहते हैं, ''जब रोगियों को ठीक होने के बाद समस्या होती है तो यह महत्वपूर्ण समय होता है जब उन्हें चिकित्सा देखभाल की जरूरत होती है. भले ही इससे जीवन के लिए कोई सीधा खतरा न पैदा होता हो, फिर भी लांग कोविड किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को कम कर सकता है.'' रक्त की जांच और व्यक्तिगत परामर्श के अलावा, फेफड़े के फाइब्रोसिस वाले रोगियों के लिए अस्पताल में फिजियोथेरेपी की बहुत मांग है. डॉ. शेरवाल कहते हैं, ''जिन मरीजों में केवल 10 फीसद फाइब्रोसिस था, उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई है. हम विभिन्न ब्रीदिंग एक्सरसाइज से उनके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करते हैं.''

ठीक होने वाले रोगियों में दूसरे संक्रमण भी आम हैं और ये मृत्यु दर की आशंका बढ़ाते हैं. आइसीएमआर का नवीनतम अध्ययन दर्शाता है कि उन लोगों में मृत्यु दर 56.7 प्रतिशत अधिक है जिनमें कोविड के बाद दूसरे संक्रमण हुए. रक्त और श्वसन अंगों में ऐसे संक्रमण सबसे आम हैं. चेन्नै के अपोलो अस्पताल में प्रीवेंटिव हेल्थ के सीईओ डॉ. श्रीराम सत्या कहते हैं, ''कोविड उन बीमारियों में से है जो सबसे अधिक तेजी से परिवर्तित होती हैं; यह कहना मुश्किल है कि किसी व्यक्ति पर इसका कैसा असर होगा. इसलिए, 14 दिनों के बाद कोविड से उबरे व्यक्ति को कितनी आंतरिक क्षति हुई है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है.''

विशेषज्ञों के अनुसार, कोविड से बचे लोगों की तीन श्रेणियां हैं और जब तक आप परीक्षण नहीं करवाते, तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप किसमें आते हैं. पहली श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो कोविड के तुरंत बाद बेहतर महसूस करते हैं जो कमजोरी तो महसूस करते हैं लेकिन उनके लक्षण कम हो गए हैं और वे रोजमर्रा के कार्यों में लौट सकते हैं. दूसरी श्रेणी में ऐसे मरीज हैं जिनके लंबे समय तक लक्षण बने रहते हैं और उन्हें उचित गति से चलने-फिरने में भी मुश्किल होती है; वे ब्रेन फॉग, दर्द और अधिक तीव्र थकान का भी अनुभव कर सकते हैं. तीसरी श्रेणी में वे हैं जो रक्तचाप में वृद्धि, अनियंत्रित शर्करा का स्तर या सूजन जैसी शारीरिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं लेकिन उन्हें इसका अनुभव भी नहीं होता.

पहली श्रेणी के रोगियों के लिए, डॉक्टर सामान्य एहतियात के तौर पर रक्त की नियमित रूप से निगरानी की सलाह देते हैं. डॉ. सत्या कहते हैं, ''हमने कुछ जांच की एक सूची बनाई है जिसे घर से ही किया जा सकता है, क्योंकि कई मरीज कोविड से उबरने के बाद भी अस्पताल नहीं आना चाहते हैं. इनके आधार पर, डॉक्टर सलाह दे सकते हैं कि क्या आगे के परीक्षणों की आवश्यकता है.'' खून की जांच में लीवर, किडनी, हृदय के साथ बुनियादी मेटाबोलिक बीमारियों और रक्त प्रोफाइल की जांच को शामिल किया जाना चाहिए. ये जांच क्वारंटीन समाप्त होने के चार से आठ सप्ताह बाद होनी चाहिए. दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट (क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट) डॉ. मेघा जेनिना का कहना है कि कोविड ठीक होने के बाद, पोषण बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. वे बताती हैं, ''कोविड इतना कहर बरपाता है कि आप पहले उसके लक्षणों को शांत होने देना चाहते हैं, उसके बाद ही शरीर को हुई दीर्घकालिक क्षति की जांच की सोचते हैं. पहली बार, मुझे ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनकी वजन घटाने में दिलचस्पी नहीं है. अब लोग जानना चाहते हैं कि भोजन कैसे उनकी सेहत को तेजी से सुधार सकता है और लांग कोविड के लक्षणों को कम कर सकता है.''

दूसरी और तीसरी श्रेणी के लोगों को उबरने में अधिक समय लग सकता है और उन्हें व्यवस्थित देखभाल की जरूरत होती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से चिकित्सकों से परामर्श जारी रखें और महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी करते रहें. चेन्नै के अपोलो अस्पताल में ऐसे मरीजों के लिए पैकेज है और पिछले दो महीनों में इसके लिए 1,000 अनुरोध प्राप्त हुए हैं. हालांकि सफलता दर बताना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन डॉ. श्रीराम कहते हैं, ''हमें कुछ लक्षणों में कमी और नियंत्रण पक्के तौर पर दिख रहा है.''

अधिकांश डॉक्टरों के अनुसार, पूरी तरह ठीक होने की प्रक्रिया में तीन से छह महीने का समय लग सकता है, लेकिन यह काफी हद तक रोगी की मेडिकल हिस्ट्री (पूर्व की बीमारियों के इतिहास) और जीवन शैली के साथ-साथ कोविड के लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है. डॉ. सत्या कहते हैं, ''लंबे समय तक बने रहने वाले लक्षणों को नियंत्रित करने और कोविड से उबरने के कुछ हफ्तों के बाद विकसित होने वाले किसी भी अतिरिक्त जोखिम की भविष्यवाणी करने के लिए, कोविड के बाद सेहत की स्थिति सभी रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है.'' जिन रोगियों में फेफड़े के फाइब्रोसिस विकसित हुए हों, उन्हें उस व्यायाम को घर पर नहीं दोहराना चाहिए जो उन्होंने किसी पल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी में किए हैं. अन्य लोगों को योग और प्राणायाम से थकान के लक्षणों में सुधार और अपने शरीर को दैनिक दिनचर्या में वापस लौटने में मदद मिल सकती है.

डॉ. फरह इंगले कहती हैं, ''आपको जीवन फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत होगी और ऐसा करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि आपको कोविड हुआ था.'' उन्होंने यह सलाह पिछले डेढ़ साल में हजारों रोगियों को दी है. धैर्य, सुनियोजित गतिविधि, एक स्वस्थ आहार, आराम, नियमित चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के निरंतर प्रयास ही, कोविड पर सही मायने में जीत हासिल करने का एकमात्र तरीका है. सच तो यह है कि लांग कोविड के इलाज का कोई शॉर्टकट नहीं है. ■

> **“वायरस किसी अंग को नहीं बख्शता. कोविड बाद की देखभाल के लिए हमें अनुसंधान समर्थित बहु-विषयक दृष्टिकोण की जरूरत है”**
>
> **डॉ. रणदीप गुलेरिया**
>
> *डायरेक्टर, एम्स, दिल्ली*

रतीय जनत
ARATIYA JANAT

नया अंगरखा
9 जून को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ जितिन प्रसाद (बाएं)

चंद्रदीप कुमार

खास रपट

हर कोई चाहे ब्राह्मण वोटर

राजनैतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों जाति-बिरादरियों का समर्थन जुटाने के लिए बेतरह कोशिश में जुटीं

आशीष मिश्र

कानपुर में पिछले साल जुलाई में माफिया सरगना विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत से पूरे देश में सुर्खियां हैरानी से चीख उठी थीं. यह उस दौरान हुआ था जब उत्तर प्रदेश पुलिस उसे मध्य प्रदेश से ला रही थी. उसके सात दिन पहले 2 जुलाई को उसने जिले के बिकरू गांव में सात पुलिसवालों को मार गिराया था. इसी दौरन पुलिस ने विकास दुबे के छह साथियों को भी एनकाउंटर में मार गिराया था. इन साथियों में ज्यादातर ब्राह्मण जाति से थे. जब वह भगोड़ा बना हुआ था, तब सोशल मीडिया पर उसे 'ब्राह्मण रक्षक' बताए जाने वाले पोस्ट की भरमार लग गई थी.

लेकिन उसकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक ब्राह्मण समुदाय पर फोकस बढ़ गया. विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में योगी अदित्यनाथ की सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया था. अगस्त, 2020 में तत्कालीन वरिष्ठ कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने अपने संरक्षण में बने संगठन 'ब्राह्मण चेतना परिषद' के जरिए ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान शुरू किया था. कोरोना संक्रमण के दौरान जितिन ब्राह्मण परिवारों से ऑनलाइन संवाद कर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को ब्राह्मण विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे थे. जितिन ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर परशुराम जयंती का अवकाश बहाल करने की भी मांग की थी, जिसे 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद खत्म कर दिया गया था.

भाजपा ब्राह्मणों की नारजगी से काफी डरी हुई है और उसकी काट के लिए वह दूसरी पार्टियों से ब्राह्मण नेताओं को अपनी पार्टी में लाने में जुटी है. लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या इससे नाराजगी दूर हो पाएगी

अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को ब्राह्मणों के छिटकने का डर सताने लगा तो पार्टी ने जितिन प्रसाद के लिए अपने दरवाजे खोल दिए. नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को भाजपा की सदस्यता दिलाई. उसके फौरन बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया "जितिन के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी."

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री का दांव खेलने वाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 'श्री कल्की धाम, संभल' के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं, "भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति में ब्राह्मणों का मुख्य स्थान है. उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और उसकी उपजातियों को मिलाकर उनकी आबादी 11 फीसद के करीब है. योगी सरकार से ब्राह्मण बेहद नाराज हैं. इस वजह से भाजपा को 2022 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व कार्ड खेलने में कठिनाई होगी. इसी के डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ब्राह्मण नेताओं को शामिल कर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा."

हालांकि राजनैतिक जानकार चुनावों में ब्राह्मणों के वोट करने के तौर-तरीकों को एक नए नजरिए से देख रहे हैं. लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.के. द्विवेदी कहते हैं, "ब्राह्मण मतदाता असल में 'फ्लोटिंग वोटर' है जो मुख्यत: सुरक्षा, रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट करता है. ब्राह्मण और सामाजिक रूप से प्रभावी दूसरी अगड़ी जातियों को अपने साथ जोड़कर राजनैतिक पार्टियां अपने लिए महौल बनाती हैं. यह महज संयोग नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जब भी जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतीं, उसके पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक रहे हैं." 2007 में प्रदेश में पूरे बहुमत से सरकार बनाने वाली बसपा के पास उस वक्त सबसे अधिक 41 ब्राह्मण विधायक थे तो पांच वर्ष बाद 2012 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी (सपा) के पास सबसे ज्यादा 21 ब्राह्मण विधायक थे. 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक जीते थे. इनमें 46 भाजपा के टिकट पर जीते थे. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां एक बार फिर ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गई हैं.

ब्राह्मण समाज के हितों के लिए काम कर रही संस्था "ब्राह्मण संसद" के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र बताते हैं, "2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने भाजपा को एकतरफा समर्थन दिया था. पिछ्ले चार वर्षों के दौरान ब्राह्मणों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा देने में भाजपा सरकार असफल साबित हुई है. भाजपा सरकार के कार्यकाल में बड़ी संख्या में ब्राह्मण प्रताड़ित हुए हैं. कई निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हुई है. कई निर्दोष ब्राह्मणों पर झूठे केस दर्ज कराए गए हैं. इन वजहों से ब्राह्मण प्रदेश की भाजपा सरकार से नाराज हैं." हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला इन आरोपों को खारिज करते हैं. मनीष शुक्ला कहते हैं, "ब्राह्मण समाज को जितना सम्मान भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकार में मिला है, उतना पहले कभी नहीं मिला है. ब्राह्मण समाज का भाजपा को पूरा समर्थन है."

2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अगस्त, 2016 में बसपा के तत्कालीन वरिष्ठ ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक और दो महीने बाद अक्तूबर, 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी को शामिल कर ब्राह्मण राजनीति में भगवा खेमे की धमक दिखाई थी. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दूसरी पार्टियों के प्रमुख ब्राह्मण नेताओं को शामिल कर एक बार फिर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. हाथरस के सादाबाद से विधायक तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के ब्राह्मण चेहरा रामवीर उपाध्याय की पत्नी, पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय 15 मई को भाजपा में शामिल हो गईं. चुनाव के पहले रामवीर उपाध्याय के भी भाजपा में शामिल होने की पूरी संभावना है. जितिन प्रसाद के शामिल होने के बाद पूर्वांचल में कांग्रेस के कई और युवा ब्राह्मण नेता भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक कहते हैं, "भाजपा की सबका साथ-सबका विकास की नीति से प्रभावित होकर सभी जातियों के लोग पार्टी में शामिल होना चाहते हैं. ब्राह्मण भी उनमें हैं."

उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी सपा परशुराम की मूर्ति के जरिए बाह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है. 5 अगस्त, 2020 अयोध्या में राम मंदिर के भूमिपूजन के दो दिन ही बीते थे कि सपा के राष्ट्रीय सचिव तथा पूर्ववर्ती अखिलेश यादव

परशुराम पहल
बलिया में परशुराम की प्रतिमा के साथ सपा नेता अभिषेक मिश्र और अन्य

मनीष अग्निहोत्री

जीत का गणित

पिछले तीन दशकों में उत्तर प्रदेश विधानसभा में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व

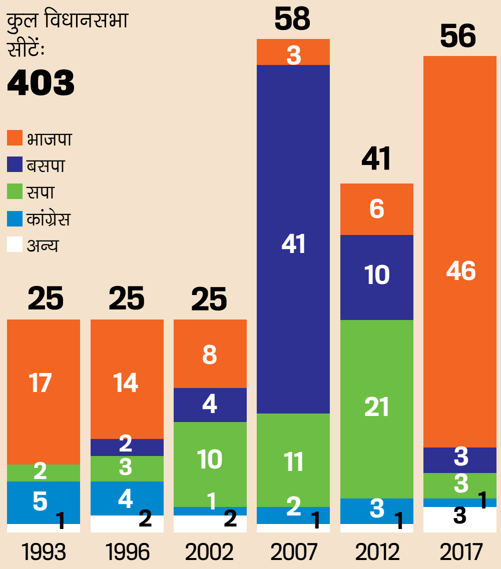

नोटः ये आंकड़े चुनाव आयोग की सूची से निकाले गए हैं

सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अभिषेक मिश्र ने राजधानी लखनऊ में 108 फुट ऊंची परशुराम की प्रतिमा लगाने के साथ सभी जिलों में मूर्ति स्थापना की घोषणा की थी. फिलहाल जालौन, उरई, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा समेत दस जिलों में परशुराम मूर्ति की स्थापना हो चुकी है. अभिषेक मिश्र बताते हैं, ''सभी जिलों में सपा नेताओं की छह सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो मूर्ति स्थापना के लिए जगह की तलाश और सभी जरूरी प्रबंध करती है. मूर्ति स्थापना के लिए चंदा लेकर धन जुटाया जा रहा है. लखनऊ में लगने वाली 108 फुट ऊंची परशुराम की प्रतिमा के लिए जगह की तलाश की जा रही है.''

बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी ऐलान किया है कि अगर प्रदेश उनकी सरकार बनती है तो परशुराम की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी. ब्राह्मणों का समर्थन पाने के लिए मायावती ने 2005 की तर्ज पर भाईचारा कमेटियों का गठन करना शुरू किया है. विधानसभा स्तर पर दलित, ब्राह्मण और ओबीसी कमेटियों का गठन कर बसपा उसी सोशल इंजीनियरिंग को दोहराने के प्रयास में है, जिसके जरिए पार्टी ने 2007 में प्रदेश में सरकार बनाई थी. बसपा ने ब्राह्मण नेता अमरचंद्र दुबे को गोरखपुर-बस्ती मंडल की ब्राह्मण भाईचारा कमेटी का सेक्टर संयोजक बनाया है. अमरचंद्र दुबे बताते हैं, ''हर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण भाईचारा कमेटियों के जरिए लगातार बैठकें करके ब्राह्मण समाज के युवा और अनुभवी लोगों को बसपा से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकार की उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण बड़ी संख्या में बसपा से जुड़ रहे हैं.''

वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया था. बाद में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और प्रदेश के इतिहास में अब तक सबसे कम 7 सीटें ही जीत पाई. कभी ब्राह्मणों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के पास इस वक्त विधानसभा में केवल एक ही ब्राह्मण विधायक है. 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में महज एक सीट जीतने वाली कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी तथा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने संगठन को सक्रिय करने के लिए कुछ ब्राह्मण नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी हैं. प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट से लगातार दो बार विधायक तथा कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा को प्रियंका ने योगी सरकार की गड़बड़ियों को सदन के भीतर पुरजोर ढंग से उठाने की जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा प्रियंका ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ललितेशपति त्रिपाठी को कांग्रेस के शाखा संगठनों के प्रदेश प्रभारी का जिम्मा सौंपा है.

2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठन को नया रूप देने की तैयारी शुरू की है. सोशल मीडिया पर कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रियंका ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मोहित पांडेय को 'यूपी कांग्रेस सोशल मीडिया सेल' का चेयरमैन बनाया है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कोर टीम के सदस्य रह चुके हैं. कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में पार्टी के संगठन को चार क्षेत्रों पूर्वी, पश्चिमी, अवध और बुंदेलखंड में बांटकर उनमें क्षेत्रीय अध्यक्षों की तैनाती पर विचार कर रहा है. सभी चारों क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का सहयोग करेंगे. कार्यकारी अध्यक्ष का नाम तय करने में पार्टी जातिगत समीकरणों पर भी ध्यान देगी. इन चारों क्षेत्रीय अध्यक्ष में से कम से कम एक ब्राह्मण जाति से होगा. इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी वाराणसी से पूर्व सांसद राजेश मिश्र, लखनऊ से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आचार्य कृष्णम कहते हैं, ''उत्तर प्रदेश में 1989 में कांग्रेस सरकार में एन.डी. तिवारी आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे. तीन दशक में एक बार भी किसी पार्टी ने ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया. ब्राह्मण अपना मुख्यमंत्री देखना चाहता है. अगर कांग्रेस ने किसी ब्राह्मण नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया तो पार्टी को अधिसंख्य ब्राह्मणों का समर्थन मिल सकता है.'' इतना तो तय है कि ब्राह्मण अब सबके एजेंडे में हैं. तो, क्या 'परशुराम लहर' का जादू इस बार भी चलेगा? ■

साउथ ब्लॉक के भीतर तोप पर जंग

भारतीय सेना की तरफ से तोपों की तत्काल मांग ने सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति पर दबाव और बढ़ा दिया है

संदीप उन्नीथन

भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय के बीच पिछले कुछ महीनों से 4,000 करोड़ रु. में 400 तोप खरीदने को लेकर माथापच्ची चल रही है. इज्राएल से 400 होवित्जर तोप खरीदने के सेना के प्रस्ताव पर सितंबर 2019 में महानिदेशक (खरीद) से मंजूरी के आखिरी चरण में था, लेकिन स्वदेशी तोप निर्माण कार्यक्रम में तेजी दिखने पर वह प्रस्ताव धरा रह गया. इस साल के शुरू में पूर्वी लद्दाख में चीन से नौ महीने का टकराव कुछ हद तक खत्म हुआ तो सेना ने तोप आयात के प्रस्ताव को फिर जिंदा किया. आयात को जायज ठहराने के लिए उत्तरी सीमाओं पर 'फौरी अभियान जरूरत' का हवाला दिया गया. सेना की फौरी जरूरत को इस तथ्य से भी हवा मिली थी कि स्वीडिश एफएच-77बी बोफोर्स तोप के स्वदेश निर्मित संस्करण 'धनुष' की आपूर्ति धीमी हो गई है. एक बार महानिदेशक (खरीद) के स्तर से तोप आयात प्रस्ताव आगे बढ़ने पर इसे आखिरी मंजूरी के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) के पास भेजा जा सकता है.

हालांकि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी सेना के तोप आयात के प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहते हैं. उनकी दलील है कि इस मौके पर तोप के ऑफ द शेल्फ आयात से स्वदेशी तोप विकास कार्यक्रम को गंभीर झटका लगेगा. रक्षा मंत्रालय का रक्षा उत्पादन विभाग (डीओडीपी) रक्षा शोध और विकास संगठन (डीआरडीओ) की ओर से डिजाइन अत्याधुनिक तोप सिस्टम (एटीएजीएस) को शह दे रहा है, जिसके उत्पादन में स्वदेश में उसके निजी क्षेत्र के उद्योग सहयोगी भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड जुड़े हुए हैं. डीओडीपी का मानाना है कि यह तोप कार्यक्रम रक्षा उत्पादन में सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के लिए परीक्षा की तरह है. उसकी दलील है कि देश के उद्योग जगत और ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड (ओएफबी) से बड़ी संख्या में एटीएजीएस की खरीद होनी चाहिए.

गतिरोध बना हुआ है जबकि होवित्जर तोप आयात को बंद करने की आखिर तारीख 31 दिसंबर, 2021 नजदीक आ रही है. अगस्त 2020 में जारी रक्षा मंत्रालय की 101 सामान की 'नकारात्मक सूची' में 155/52 कैलिबर की होवित्जर तोपें भी हैं. अब इसे 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' का नाम दिया गया, जिसका मकसद उन श्रेणियों में आयात रोकना है जिनमें उद्योग आत्मनिर्भर हैं. साल 2007 में जब ऐसा कोई घरेलू कार्यक्रम नहीं था तब रक्षा मंत्रालय ने सेना के 12,640 करोड़ रुपए में 1,580 होवित्जर खरीदने और एसेंबल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसके तहत 400 होवित्जर ऑफ द शेल्फ आयात होनी थीं और बाकी 1,180 तकनीक हस्तांतरण के जरिए देश में ही बनाई जानी थीं. तब से तीन स्वदेशी तोप कार्यक्रमों ने धीरे-धीरे सेना को तोपों की आपूर्ति शुरू की—धनुष, एटीएजीएस और ओएफबी की वह किट जो मौजूदा सोवियत निर्मित 130 एमएम गन को 155 एमएम शारंग होवित्जर में बदल रही है—इसमें शामिल है.

भारतीय उद्योग से जुड़े लोगों को डर है कि 400 होवित्जर तोपों के आयात से घरेलू उद्योग दम तोड़ देगा. नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक डेवलपर कहते हैं, "जब भारतीय तोपें निर्माण के आखिरी चरण में हैं, ऐसे ऑर्डर, उस अवस्था में जब भारतीय तोपें परिपक्व हो रही हैं, विदेशी निर्माता को हमारे दरवाजे पर ला खड़ा करेगा. इससे भविष्य में विदेशी के भारत में उत्पादन को बल मिलेगा और स्वदेशी उद्योग और को नष्ट कर देगा."

इस साल के शुरू में दोनों निजी डेवलपर के एक-एक, दो एटीएजीएस होवित्जर सिक्किम में जाड़े के परीक्षण में कामयाब रहे हैं. और इससे इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ी हैं. इन दोनों का राजस्थान में गर्मियों का परीक्षण इस महीने होने वाला है. इन परीक्षणों के कामयाब रहने पर 3,365 करोड़ रु. में 150 एटीएजीएस की खरीद का रास्ता साफ हो जाएगा. ऑर्डर दोनों निजी डेवलपरों में बांटा जाएगा. पिछले साल मई में अचानक पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की मोटर डिविजन आगे बढ़ आई थी, इससे सेना की मारक क्षमता

अत्याधुनिक तोप (एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम या एटीएजीएस)

155/12 होवित्जर

डिजाइन: डीआरडीओ

निर्माता: टाटा पावर एसईडी और भारत फोर्ज

स्थिति: सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ हाइ आल्टीट्यूड पीएसक्यूआर ट्रायल सिक्किम में जनवरी और मार्च 2021 के बीच; 15 डिग्री सेल्सियस और शून्य से नीचे के भीषण तापमान और 13,000 फुट की ऊंचाई पर. मरुस्थल का ट्रायल जून 2021 में.

एटीएचओएस तोप

155/52 होवित्जर

निर्माता: एल्बित, इज्राएल

स्थिति: एल्बित ने भारतीय सेना के 2019 के तोपों के ठेके में सबसे कम कीमत की बोली लगाई. खरीद का मामला अभी रक्षा मंत्रालय और महानिदेशक (खरीद) के स्तर पर लंबित है. सेना तत्काल संचालन की जरूरतों का हवाला दे कर 400 तोपें जल्द खरीदना चाहती है. लेकिन रक्षा मंत्रालय ने मना कर दिया है.

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी तरह के ऑफ द शेल्फ तोप आयात का स्वदेशी तोप के विकास पर गंभीर असर पड़ेगा

तत्काल बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई. एटीएजीएस अभी भी विकास की परीक्षण अवस्था में है और ओएफबी को अभी धनुष होवित्जर की पहली पूरी रेजिमेंट डिलिवर करना है. सीमा पर टकराव की बहुत वास्तविक आशंकाओं की वजह से सेना को उत्तरी सीमा पर कुमुक बढ़ानी पड़ी–जिसे सेना 'पुनर्संतुलन' करना कहती है. इसके तहत पश्चिम में पाकिस्तानी सीमा से कुमुक हटाकर चीन से लगी विवादास्पद उत्तरी सीमा की ओर ले जाई गई.

होवित्जर इस पुनर्संतुलन का हिस्सा हैं. उनसे छह किलो विस्फोटक को 30 किलो से अधिक स्टील कवर में 155 मिलीमीटर के गोले दागे जा सकते हैं. इनके फटने से लक्ष्य पर सुपरसोनिक रफ्तार से स्टील के छर्रों की बरसात होती है, जो कंक्रीट और बख्तरबंद ढांचों को तार-तार कर सकते हैं. इस तरह तोप पर्वतीय युद्ध में अहम हैं. ये आक्रमण के अलावा जवानों और बखतरबंद गाड़ियों के आगे बढ़ने में भी कवच का काम करते हैं,

जिसे 'परोक्ष गोलाबारी' कहा जाता है. 1999 में करगिल युद्ध भारतीय तोपों की गोलाबारी से पाकिस्तानी फौज को काफी नुक्सान झेलना पड़ा था. इससे उनकी सप्लाइ लाइन और अभेद्य बंकर बर्बाद हो गए थे. फिलहाल दो सीमा पर मोर्चों पर तैनात रहने के मद्देनजर भारतीय सेना के पास दोनों मोर्चे के लिए तोपें काफी नहीं हैं. सेना के एक पूर्व कमांडर 3,448 किमी उत्तरी सीमा पर तैनात टुकड़ी के पास जमीनी और रॉकेट तोपों की भारी कमी का हवाला देते हैं. यही संभावित वजह है जिसके कारण सेना ने 2019 के होवित्जर आयात मामले को फिर उठाने का फैसला किया. (इस स्टोरी पर भारतीय सेना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.) माना जा रहा है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तोप आयात के सेना के प्रस्ताव का समर्थन किया है लेकिन ये शर्त भी लगाई है कि स्वदेशी होवित्जर कार्यक्रम के लिए भी सांस लेने की गुंजाइश रहनी चाहिए.

इस साल अप्रैल में सेना के उच्चाधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय को इज्राएल के 155 मिमी तोप 'एटीएचओएस' (ऑटोनॉमस टोव्ड होवित्जर ऑर्डनेंस सिस्टम) की कीमत, तैनाती और वक्त की बढ़त के बारे में बताया. जल्दी आपूर्ति के मद्देनजर इज्राएली निर्माता एल्बित ने सेना को आश्वस्त किया कि पहली 12 तोपें तो करार पर दस्तखत के 14 महीनों के भीतर मिल जाएंगी और सभी 400 तोपें कुल 54 महीने में मुहैया करा दी जाएंगी. 15 टन वजन की इज्राएली तोप 18 टन वजन की एटीएजीएस के मुकाबले खासकर पहाड़ी इलाकों में बढ़त दिला देती हैं, जहां सड़कें पूरी तरह सही-सलामत नहीं हैं. इसके अलावा एटीएचओएस की कीमत 9 करोड़ रुपए प्रति तोप है जबकि एटीएजीएस का मूल्य 22 करोड़ रुपए प्रति तोप है. करार को आकर्षक बनाने के लिए इज्राएली वेंडर ने कथित तौर पर यह भी वादा किया कि वह तोप के 70 फीसद कल-पुर्जे भारतीय उद्योगों से खरीदेगा और उन्हें उसके लिए टीओटी (तकनीक हस्तांतरण) मुहैया कराएगा. सेना ने रक्षा मंत्रालय को यह भी कहा कि एटीएसओएस तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए बस एक बार खरीदी जाएगी, जिससे स्वदेशी तोप कार्यक्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इस आयातित तोप की अपनी समस्याएं हैं. यह अभी इज्राएली सेना की तैनाती में भी नहीं है और कुछ साल पहले भारत में परीक्षण के इसके ढांचे में दिक्कतें पाई गई थीं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि एटीएजीएस को एकदम मुकम्मल करने में समय की जरूरत है और सेना को आयात पर जोर देने के बदले धनुष कार्यक्रम की समस्याएं दूर करने की आवश्यकता है

इज्राएली वेंडर के नए ऑफर्स से रक्षा मंत्रालय के लिए संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं, इसका मतलब है कि वे साल 2007 के मूल एक्सेपटेंस ऑफ नेसेसिटी और 2011 के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्रस्तावों में संशोधन हो सकता है. इन बदलावों के लिए या तो सीसीएस की नई मंजूरी की जरूरत होगी या फिर जैसे 2016 में एमएमआरसीए फाइटर डील के समय हुआ कि टेंडर रद्द कर सीधे सरकार से सरकार के जरिए खरीद हो जैसा कि 36 राफेल जेट के मामले में किया गया.

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने *इंडिया टुडे* को बताया कि अभी तक प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. सूत्रों का कहना है, ''रक्षा मंत्रालय इस मामले में सभी संबंधित से राय-मशविरा कर रहा है. उसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ सशस्त्र बलों को जरूरी अस्त्र-शस्त्र मुहैया कराने की जरूरत, दोनों का ध्यान है. हमें हथियार के आयात को कम करने के लिए हथियारों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और उत्पादन की दिशा में काम करना है और यह देश की सुरक्षा से समझौता किए बिना हासिल करना है.''

इस बीच डीआरडीओ की डिजाइन वाली एटीएजीएस सिक्कम में जनवरी से मार्च 2021 के बीच जाड़े के परीक्षण में कामयाब रही है और सितंबर 2020 की उस घटना को पीछे छोड़ चुकी है, जब फायरिंग ट्रायल के दौरान एक एटीएजीएस का बैरल फट गया था. ये तोपें शून्य से 15 डिग्री सेल्सियस कम तापमन पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर रात में कुल 500 किमी तक चलाई गईं और बिना नाकामी 160 चक्र गोले दागे. नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक डेवलपर कहते हैं, ''ये तोपें जाड़े का परीक्षण पास कर चुकी हैं और सेना चाहे तो फौरन उत्तरी सीमा पर तैनात की जा सकती हैं.''

डेवलपरों का कहना है कि ये स्वदेशी तोपें हर तरह संकरे और हल्के वजन वाले पुलों पर भी खरी उतरी हैं और उन आशंकाओं का समाधान कर चुकी हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में इनकी रफ्तार में दिक्कत आ सकती है. उनका कहना है कि एल्बित की तोप का 2017 में मैदानी परीक्षण कम दुर्गम क्षेत्र में ही किया गया, उसकी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रफ्तार का परीक्षण दिन में हुआ. इसे तिब्बत के पठार में उत्तरी सिक्कम के सबसे उत्तरी स्थान लूक्रेप ले जाया गया और कार्यकुशलता परखने के लिए बर्फ से ढंके मेनला और चांगू लेक में परीक्षण किया गया. डेवलपरों का कहना है कि कम वजनी पर्वतीय हवा में तोप की मारक दूरी 60 किमी तक हो जाती है, जिससे सेना को ब्रिगेड मुख्यालय, पुलों और ईंधन डिपो को निशाना बनाने रणनीति बढ़त शुरुआत से ही मिल सकती है.

हालांकि जानकारों का माना है कि एटीएजीएस को एकदम मुकम्मल होने में वक्त की जरूरत है और सेना को आयात पर जोर देने के बदले धनुष कार्यक्रम की समस्याएं दूर करने की आवश्यकता है. धनुष तोप को सेना के तोप निदेशालय ने करीब दशक भर पहले ओएफबी के जरिए बनाने पर जोर दिया था. उसका डिजाइन 1980 के दशक में बोफोर्स एबी के मुहैया कराए ब्लूप्रिंट से तैयार किया गया था. दोनों स्वदेशी तोपों के डिजाइन और विकास के साथ जुड़े रहे पूर्व तोपखाना महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पी. रविशंकर कहते हैं, ''मैं नहीं समझता कि एटजएजीएस फौरी अभियान जरूरतों का विकल्प है.'' उनका कहना है, ''आखिर परीक्षण में खरी तोप धनुष को अभी तैनात क्यों नहीं किया गया जबकि उत्पादन के ऑर्डर साल भर पहले दे दिए गए थे? कड़े फैसलों की जरूरत है. अगर धनुष में समस्या है तो उसे दूर करने की जरूरत है. जरूरत पड़े तो बोफोर्स के मूल डिजाइनरों को बुलाया जाना चाहिए.'' हालांकि ओएफबी के अधिकारी इससे इनकार करते हैं कि तोप को चलाने में कोई दिक्कत है. उनका कहना है कि पहली 12 तोपें सेना को 2019 में दी गई थीं. उनका मानना है कि 20 तोपों का ऑर्डर साल के अंत तक पूरा हो जाएगा. देखना है कि सरकार का 16 जून का ओएफबी को सात कंपनियों में बदलने का फैसला धनुष कार्यक्रम पर किस तरह असर डालता है. अल्प समय में धनुष की बाधाएं दूर करने से सेना की तोपों की जरूरत पूरी की जा सकती है. ■

अहम सवाल औचित्य का

नियम-प्रतिमानों और आचरण संहिता का दृढ़ता से पालन करके ही नौकरशाह सियासी प्रतिशोध से अपना बचाव कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं

कौशिक डेका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुआई वाली पश्चिम बंगाल सरकार के बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के एक अफसर को लेकर हाल ही में जो अप्रिय खींचतान हुई, वह केंद्र-राज्य संबंधों के इतिहास में इस तरह की पहली घटना नहीं है. सिविल सेवकों की तैनाती, उन्हें इनाम या सजा देने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ऐसे अनगिनत टकराव हो चुके हैं. बेशक सियासी इरादे इस आग को हवा देते हैं.

लोक प्रशासन के जानकारों की मानें तो पश्चिम बंगाल के अब रिटायर हो चुके मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को लेकर यह ताजातरीन टकराव देश में राजकाज के ढांचे को लेकर चिंताजनक रुझान सामने लाता है. यह 28 मई को प्रधानमंत्री की राज्य की यात्रा के दौरान एक घटना से शुरू हुआ. संविधान के संस्थापकों ने अफसरशाही की परिकल्पना गैर-राजनैतिक संस्था के रूप में की थी, लेकिन सिविल सेवक लगातार ऐसे राजनैतिक टकरावों में उलझते जा रहे हैं, जो अलग-अलग पार्टियों और सरकारों और यहां तक कि एक ही पार्टी और सरकार के नेताओं से भी जुड़े हैं.

राजनैतिक कार्यपालिका के आगे उनकी लाचारगी की वजह से उन्हें इन टकरावों में धकेल दिया जाता है. कई बार खुद उन पर भी अपने करियर को मनमाफिक और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राजनैतिक आकाओं को खुश करने की बेताबी सवार होती है. दोनों ही स्थितियों में सिविल सेवकों के बढ़ते राजनीतिकरण ने उन्हें खास विचारधारा या राजनैतिक मत के प्रति निष्ठा के आधार पर ऐन बीच से दोफाड़ कर दिया है. केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में सचिव रह चुके अजय दुआ कहते हैं, ''बेहतर या मालदार तैनाती हासिल करने की सिविल सेवकों की कमजोरी का इस्तेमाल नेता अक्सर उनकी रीढ़ तोड़ने के लिए करते हैं. युवा अफसरशाह देखेंगे कि इनाम किन्हें मिल रहा है—उन्हें जो नियमों का पालन कर रहे हैं या उन्हें जो राजनैतिक आकाओं के प्रति वफादारी दिखा रहे हैं?''

नतीजा यह है कि वह एकता जो कभी खुल्लमखुल्ला राजनैतिक दुरुपयोग के

दूसरा पक्ष नदारद
चक्रवात यास पर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की सीटें खाली हैं

एएनआइ

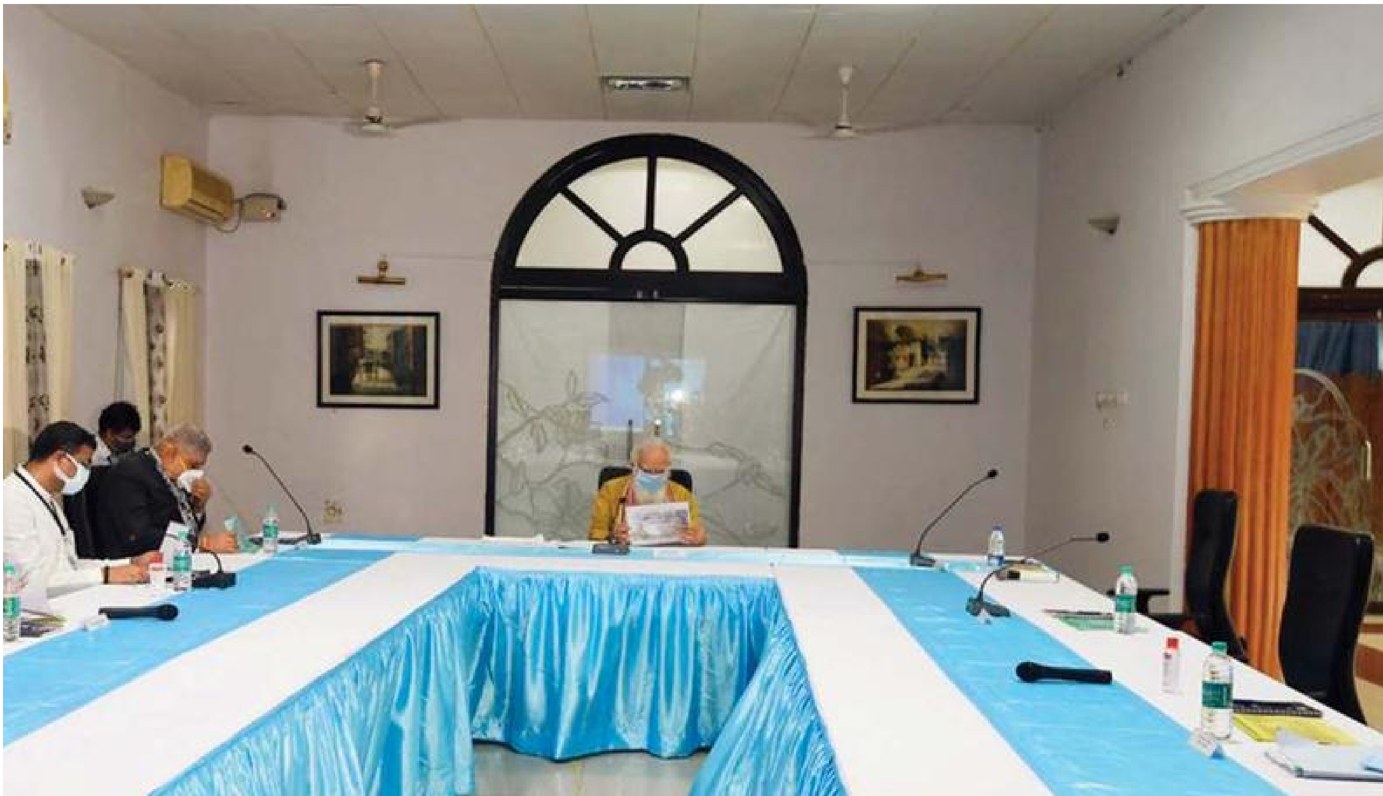

एएनआइ

एक झलक
पश्चिम बंगाल की मुख्यमत्र ममता बनर्जी राज्य के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय के साथ

खिलाफ मजबूत दीवार का काम करती थी, तार-तार हो चुकी है. यह गड़बड़ी राजनीतिकरण को और ज्यादा हवा देती है और फिर यह एक दुष्चक्र बन जाता है. पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जी.के. पिल्लै कहते हैं, ''एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह हुई है कि सीनियर अफसर अब जूनियर अफसरों का साथ नहीं देते. इससे अफसर की स्थिति और नाजुक हो जाती है और फिर वह मानने लगता है कि राजनैतिक फरमानों के आगे नतमस्तक हो जाना ही पेशेगत हिफाजत का एकमात्र तरीका है.''

कौन दोषी है?

अफसरशाहों का एक बड़ा तबका मानता है कि बंद्योपाध्याय के मामले में सामने आई अपनी इस हालत के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं. कई आइएएस अधिकारी जोर देकर कहते हैं कि दोनों तरफ के अफसरशाह इस गड़बड़झाले को टाल सकते थे. बंद्योपाध्याय के सामने उस मुख्यमंत्री की बात मानने के अलावा बेशक कोई चारा नहीं था जिन्हें वे रोज रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर सिविल सेवक सहमत हैं कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव प्रधानमंत्री के प्रति अपना फर्ज निभाने से चूक गए. पिछले साल असम के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त कुमार संजय कृष्ण कहते हैं, ''प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अचानक प्रकट नहीं होता. राज्य मशीनरी को पहले से बताया जाता है. बंद्योपाध्याय की जगह अगर मैं होता तो मुख्यमंत्री को राजी करता कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हिस्सा होना मुख्य सचिव के प्रोटोकॉल का दायित्व है. अगर मुख्य सचिव किन्हीं अपरिहार्य स्थितियों के कारण मौजूद नहीं रह सकते तो उन्हें दूसरे अफसर को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए. इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ. आइएएस अफसर के लिए यह अच्छी बात नहीं है.''

केंद्र सरकार के एक और अधिकारी ओडिशा की मिसाल देते हैं. पश्चिम बंगाल जाने से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री राज्य में यास चक्रवात के असर की समीक्षा के लिए भुवनेश्वर पहुंचे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके मुख्य सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर थे.

बंद्योपाध्याय ने तो इस मामले में चूक की ही, लेकिन उन्हें दिल्ली रिपोर्ट करने का फरमान जारी करने वाले अफसर ने भी नियम पुस्तिका की अनदेखी की. ज्यादातर पूर्व अफसरशाहों के मुताबिक, उन्हें इस फरमान की कानूनी खामियां सामने रखनी चाहिए थीं, जो शायद राजनैतिक मंशा से जारी किया गया था. बंद्योपाध्याय संयुक्त सचिव स्तर पर केंद्र सरकार में सेवा देने वाले अफसरों की सूची में कभी रखे ही नहीं गए. जो अधिकारी इस सूची में नहीं है, वह केवल निदेशक या अवर सचिव सरीखे ओहदों पर ही काम कर सकता है, जो बंद्योपाध्याय के पद से नीचे की श्रेणियां हैं. पिल्लै कहते हैं, ''यह नितांत मूर्खतापूर्ण निर्णय था. ऐसी कोई नजीर नहीं है. किसी न किसी को तो इनकार करना चाहिए था और इस फरमान की अवैधता बतानी चाहिए थी. सिविल सेवक हमेशा फाइलों में अपने नोट लिखते हैं. यह उनका अधिकार है. इन दिनों ऐसा नहीं किया जा रहा है और अफसरशाह आंख मूंदकर आदेशों का पालन कर रहे हैं.''

केंद्र सरकार में पूर्व सचिव और दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा स्वीकार करती हैं कि तथ्यों को कागज पर दर्ज करने की अनिच्छा बढ़ती जा रही है. वे यह भी मानती हैं कि राजनैतिक इच्छा के मुताबिक न चलें तो अफसरों को अपमान और 'सजा' भुगतने का अंदेशा हमेशा रहता है. लेकिन अपने कई साथियों की तरह यह पूर्व आइएएस अफसर भी जोर देकर कहती हैं कि नियमों का पालन करना ही राजनैतिक प्रतिशोध के खिलाफ एकमात्र सुरक्षा है. वे कहती हैं, ''किसी भी कदम की खामियां लिखित में सामने लानी चाहिए, फिर वह सलाह कितनी भी कठोर या अप्रिय क्यों न हो. तब कम से कम उस अफसर को पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं कहा जाएगा और न ही यह कि उसमें साहस तथा पेशेवर शुचिता की कमी है.''

असल आका कौन है?

मोदी और ममता के बीच शह और मात के खेल ने इस सदाबहार मांग को फिर जिंदा कर दिया है कि सिविल सेवकों को उनके राजनैतिक आकाओं की सनक और शौक से महफूज रखने के उपाय किए जाएं. कई पूर्व नौकरशाहों ने 2013 में एक पीआइएल दाखिल की थी, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अफसरों का एक न्यूनतम तयशुदा

''इधर एक बड़ा खराब किस्म का बदलाव देखने को मिला है, वह यह कि सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसरों का साथ नहीं देते. इससे किसी अफसर के लिए जोखिम बढ़ जाता है और तब उसे यह लगने लगता है कि पेशे में अपने बचाव के लिए अपने राजनैतिक आका के अनुरूप लाइन पकड़ लेने में ही भलाई है''

जीके पिल्लै
पूर्व गृह सचिव

''कुछ नए अफसरों में अब यह एक तरह की आदत-सी बनती जा रही है. वे किसी औचित्य या आचरण संहिता का पालन ही नहीं करते. भविष्य में इसके गंभीर नतीजे होने वाले हैं''

कुमार संजय कृष्ण
पूर्व मुख्य सचिव, असम

कार्यकाल हो, वे नेताओं के मौखिक आदेशों पर काम न करें, और तैनातियों, तबादलों तथा अनुशासन की कार्रवाइयों को नियम-कायदों के दायरे में लाने के लिए तीन महीने के भीतर केंद्र और राज्यों में सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) का गठन किया जाए. अदालत ने सरकार से इस विषय में एक समग्र कानून पारित करने को भी कहा था.

यूपीए सरकार ने 28 जनवरी 2014 को भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) संशोधन नियम अधिसूचित किए और स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अफसर एक काडर पद पर कम से कम दो साल तैनात रहेगा, बशर्ते इस बीच वह पदोन्नत या सेवानिवृत्त न हो गया हो या राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति या दो महीनों से ज्यादा के प्रशिक्षण पर न भेज दिया गया हो. राज्य सरकारों को मुख्य सचिव सरीखे शीर्ष कार्यकारी की अध्यक्षता में सीएसबी बनाने का आदेश भी दिया गया. न्यूनतम निर्दिष्ट अवधि से पहले काडर अधिकारी का तबादला सीएसबी की सिफारिश पर ही किया जा सकता है और इसके कारण लिखित में दर्ज होने चाहिए. 20 राज्यों ने सीएसबी गठित किए, पर ज्यादातर ठप पड़े हैं. उधर, आइएएस अफसर राजनैतिक तीन-तिकड़म के सुविधाजनक प्यादे बने हुए हैं.

कर्नाटक की मिसाल लीजिए. राज्य सरकार ने सीएसबी को स्थगित कर रखा था, जिसे केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (सीएटी) ने मार्च में बहाल किया. यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब आइएएस अधिकारी बी. शरत ने मैसूर के डिप्टी कमिशनर के पद से अपने समय-पूर्व तबादले को चुनौती देते हुए अर्जी दाखिल की. सीएटी ने मुख्यमंत्री से शरत के तबादले पर पुनर्विचार करने को भी कहा.

पूर्व आइएएस अफसरों का कहना है कि राजनैतिक कार्यपालिका और अफसरशाही के बीच खटपट का वास्ता राज्य या केंद्र के शीर्ष नेताओं की परिपक्वता से है. उनके मुताबिक पहले तपे-तपाए नेता अच्छा काम करने वाले निपुण अफसरों का इस्तेमाल अक्सर अच्छे नतीजों के लिए करते थे. इसके उलट मौजूदा माहौल राजनैतिक तबके और अफसरशाही के बीच अविश्वास का है. महाराष्ट्र काडर के एक आइएएस अफसर कहते हैं, ''महाराष्ट्र में एक मुख्यमंत्री थे जिन्हें नियमों में यहां-वहां कुछ हेरफेर से कोई ऐतराज न था, लेकिन उन्होंने अपने अफसरों से कह दिया था कि ऐसे किसी आदेश पर दस्तखत न करें जिसे लेकर वे सहज न हों.'' एक अन्य अफसर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की मिसाल देते हैं, जिन्होंने कई सीनियर अफसरों की अनदेखी

किसी आइएएस अधिकारी पर किसका अख्तियार होता है?

चयन और नियुक्ति

➲ संवैधानिक रूप से गठित निकाय, संघ लोक सेवा आयोग, कठिन परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से आइएएस अधिकारियों का चयन करता है

➲ परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यूपीएससी चयनित उम्मीदवारों के नाम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को भेजता है. राष्ट्रपति इन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जिसके बाद उन्हें राज्य काडर आवंटित किया जाता है

➲ राज्य सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) जिसमें मुख्य सचिव, वरिष्ठतम अतिरिक्त मुख्य सचिव और कार्मिक विभाग के सचिव शामिल हैं, अपने काडर के अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है. बीस राज्यों ने सीएसबी का गठन किया तो है, लेकिन उनमें से अधिकांश निष्क्रिय हैं. सिविल सेवकों की पोस्टिंग और स्थानांतरण पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है

पदोन्नति

➲ आइएएस अफसर की पदोन्नति डीओपीटी के बनाए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक नियंत्रित होती है

➲ राज्य सीएसबी, जहां भी यह सक्रिय है, राज्य काडर के अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश करता है. केंद्रीय सीएसबी में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, कार्मिक सचिव और कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) शामिल हैं. वे केंद्र सरकार के तहत काम कर रहे आइएएस अधिकारियों की पदोन्नति की सिफारिश करते हैं

केंद्र में प्रतिनियुक्ति

➲ राज्य में सात साल तक सेवा देने के बाद कोई अधिकारी केंद्र में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है. राज्य सरकार की इस पर सहमति होनी चाहिए

➲ 12 साल की सेवा पूरी करने के बाद अधिकारी निदेशक के पद पर केंद्र में काम कर सकता है. इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है

➲ केंद्र सरकार 16 साल की सेवा पूरी करने वाले काडर अधिकारियों का चयन करती है और उन्हें संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव के पदों के लिए सूचीबद्ध (पैनल में शामिल) करती है

➲ पैनल बनाने का काम केंद्रीय सीएसबी और एसीसी की सिफारिशों पर आधारित है. चयन प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों से बहु-स्रोत प्रतिक्रिया (मल्टी सोर्स फीडबैक या एमएसएफ) सहित संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है

➲ 2007 बैच से अधिकारी पैनल में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे अगर उन्होंने केंद्र सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर सेवा नहीं दी है

➲ किसी अधिकारी को पैनल में जगह मिल जाने का मतलब यह नहीं कि उसे केंद्र सरकार के तहत नियुक्ति का अनिवार्य रूप से अधिकार मिल गया है. केंद्र पैनल में शामिल अधिकारी की सेवा ले सकता है, बशर्ते वह इच्छुक हो और राज्य सरकार उसे छोड़ने के लिए सहमत हो. केंद्र में शामिल होने के इच्छुक अधिकारी पर विवाद के मामले में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होता है

➲ केंद्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि सात साल की हो सकती है जिसके बाद अधिकारी तीन साल के लिए राज्य काडर में लौटता है जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है

किसी आइएएस अधिकारी को कौन सजा दे सकता है?

बर्खास्तगी जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अंतिम अधिकार केंद्र का है. राज्य सरकारों के पास आइएएस अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति है, लेकिन उन्हें डीओपीटी को एक रिपोर्ट भेजनी होगी और निलंबन की स्थिति के बारे में हर 90 दिनों में सूचित करना होगा

शिकायत निवारण प्रणाली

नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति और पोस्टिंग पर किसी भी विवाद के निबटारे के लिए कोई आइएएस अधिकारी केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (सीएटी) के पास जा सकता है.

> **''नौकरशाहों की चाहत बेहतर पोस्टिंग या मालदार पद की होती है. नेता उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी रीढ़ कमजोर कर देते हैं. नया-नवेला नौकरशाह आने पर देखता है कि आखिर इनाम किसे मिल रहा है—नियम-कानून के हिसाब से चलने वाले बंदे को या फिर अपने सियासी आकाओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने वालों को?''**
>
> **अजय दुआ**
> पूर्व सचिव, केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय

करके मुख्य सचिव की नियुक्ति की थी. वे अफसरशाह कहते हैं, ''हरेक से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनका गुस्सा शांत किया.''

आइएएस अफसरों के एक धड़े का कहना है कि सिविल सेवकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का राज्य सरकारों का अधिकार और उसके साथ ही आइएएस अफसरों के साथ कुछ मुख्यमंत्रियों का अपरिपक्व सलूक भी केंद्र और राज्यों के बीच टकराव के लिए जिम्मेदार है. अखिल भारतीय सेवा (एआइएस) नियमों के मुताबिक, राज्य काडर में तैनात आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अफसरों के खिलाफ केंद्र अनुशासन की कार्रवाई नहीं कर सकता. वह सरकार ही आइएएस अफसर को निलंबित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है जिसके तहत वह अफसर काम कर रहा है.

कुछ मुख्यमंत्री इस अधिकार का इस्तेमाल अफसरशाहों से संदिग्ध वफादारी की मांग करने के लिए करते हैं, फिर चाहे नियम-कायदे ही क्यों न तोड़ने पड़ें. एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) काडर के एक आइएएस अफसर कहते हैं, ''अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सरीखे तुनकमिजाज सियासतदानों की अगुआई वाली सरकारों में यह ज्यादा हो रहा है.'' 2015 में दिल्ली की अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर शकुंतला गामलिन की नियुक्ति तब उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच सत्ता संघर्ष की बंधक बन गई थी. 2018 में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर पर दो विधायकों ने उन पर हमला किया. ममता बनर्जी किसी आइएएस अफसर को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाने देतीं.

केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ते राजनैतिक टकरावों का असर तबादलों और नियुक्तियों के अलावा मनोनयन और प्रतिनियुक्तियों पर भी पड़ रहा है. आइएएस (काडर) नियम 1954 की धारा 6(1) के मुताबिक, काडर अधिकारी को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार की सहमति से, और उस अफसर की रजामंदी से भी, केंद्र सरकार या दूसरी राज्य सरकार के तहत सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है. केंद्र को राज्य सरकार से मशविरा करना होता है और फिर राज्य सरकार उस अफसर को पदमुक्त करती है. असहमति की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होता है.

अंतिम फैसला हालांकि केंद्र सरकार का है, लेकिन अगर राज्य सरकार उस अफसर को पदमुक्त नहीं करती, तो नियम नहीं बताते कि फिर क्या हो. अगर कोई अफसर केंद्र में जाने का इच्छुक है पर राज्य उसे पदमुक्त नहीं कर रहा है, तो वह बेशक सीएटी या अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है. अलबत्ता नियम इस बारे में खामोश हैं कि अगर अफसर खुद अनिच्छुक है और राज्य भी उसे पदमुक्त नहीं कर रहा है—जैसा कि बंद्योपाध्याय के मामले में हुआ—तो क्या हो. पिछले दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के काफिले पर राज्य में हमला होने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिम बंगाल के तीन अफसरों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया था. ममता ने इन अफसरों को पदमुक्त नहीं किया.

''देखिए, नौकरशाह, खासकर आइएएस का प्रशिक्षण कुछ इतने बेहतर ढंग से होता है और वे खुद इतने अनुभवी भी होते हैं कि सियासी दखलअंदाजी और तनाव आदि से बेहतर ढंग से निबट लें''

ओमप्रकाश रावत
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

''किसी भी पहल की खामियों को लिखकर रेखांकित किया जाना चाहिए. वह सलाह भले कितनी ही सख्त हो. इससे कम से कम इतना तो होगा कि अफसर पर पूर्वाग्रही होने का ठप्पा नहीं लगेगा या फिर उसमें साहस और पेशेवर ईमानदारी न होने का आरोप नहीं लगेगा''

शैलजा चंद्रा
पूर्व सचिव, भारत सरकार,
और पूर्व मुख्य सचिव, दिल्ली

केंद्र की सेवा में बुलाए जाने वाले अफसरों की सूची में शामिल करने की नई चयन प्रक्रिया की भी आलोचना की जा रही है. कहा जा रहा है कि यह केंद्र सरकार की राजनैतिक विचारधारा के प्रति वफादार अफसरों को लाने के इरादे से बनाई गई है. मोदी सरकार अप्रैल 2015 में 360 डिग्री मूल्यांकन प्रक्रिया लेकर आई, जिसमें सीनियर, बराबरी के अफसर और जूनियर सहित तमाम हितधारकों सहित बहुत-से स्रोतों से फीडबैक (एमएसएफ) लेना भी शामिल था. इस प्रक्रिया में संबंधित अफसरों के कुल सेवा रिकॉर्ड, सतर्कता स्थिति, शुचिता, व्यवहार से जुड़ा सामर्थ्य, काम के हुनर, अधिकार क्षेत्र की विशेषज्ञता, काम को अंजाम देने की क्षमता और संभावना तथा उपयुक्तता पर भी विचार किया जाता है. ऊपर से देखने पर तो यह 360 डिग्री मूल्यांकन ज्यादा लोकतांत्रिक दिखाई देता है क्योंकि यह कामकाज की समीक्षा की प्रक्रिया को व्यापक बनाता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह प्रक्रिया ''विचारधारा के लिहाज से अनुकूल'' अफसरों को लाने की गरज से बनाई गई है, न कि स्वतंत्रचेता अफसरों को.

अगस्त 2017 में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता में कार्मिक, जन शिकायत, कानून और न्याय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी इस प्रक्रिया को अपारदर्शी, वस्तुपरक और तिकड़म की संभावना से ओतप्रोत बताया गया. राजस्थान काडर के एक आइएएस अफसर कहते हैं, ''फीडबैक चूंकि कहीं से भी आ सकता था, लिहाजा अफसर नजर में आने के लिए अपने सरकारी कामकाज में राजनैतिक और विचाराधारात्मक जुड़ाव दिखाने लगे. इससे मसला और उलझ गया.'' हालांकि पिछले साल दिल्ली हाइ कोर्ट ने 360 डिग्री समीक्षा प्रक्रिया को सही ठहराया, यह कहकर कि उसे एमएसएफ प्रक्रिया में 'कोई गड़बड़ी' दिखाई नहीं दी.

प्रक्रिया और राजनीति को लेकर ये बहसें तो खैर चलती रहेंगी. अलबत्ता इस पर कोई विवाद नहीं है कि इस राजनैतिक भंवर से निकलने का रास्ता मर्यादित और सही आचरण में है. राजनैतिक माहौल में बदलाव के साथ केंद्र और राज्यों के बीच टकराव बढ़ सकते हैं, लेकिन अफसरशाही के कामकाज पर इसका दूरगामी असर पड़ने के आसार नहीं हैं. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओमप्रकाश रावत कहते हैं, ''सिविल सेवकों और खासकर आइएएस अफसरों को राजनैतिक दखलअंदाजी और तनावों से निबटने का अच्छा प्रशिक्षण और अनुभव हासिल है.'' इन उलझन भरी स्थितियों से चतुराई से निबटने की कुंजी सरकारी कामकाज में औचित्य और मर्यादा का पालन करना है. इसे तिलांजलि देकर उठाया गया कोई भी कदम राजनैतिक दुष्परिणामों को न्यौता दे सकता है, जिसके लिए अधिकारी खुद अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे पाएंगे.

—साथ में, **रोमिता दत्ता** और **राहुल नरोन्हा**

साझा लड़ाई
श्रीनगर में 9 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक अब्दुल्ला (बीच में) और महबूबा मुफ्ती (बाएं) के साथ पीएजीडी के अन्य नेता

आबिद भट

उम्मीद की नई रोशनी?

मोअज्जम मोहम्मद, श्रीनगर में

पिछले एक हफ्ते से जम्मू-कश्मीर की फिजा में तरह-तरह की अफवाहें तैर रही हैं. इनमें जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने से लेकर नई दिल्ली के जम्मू-कश्मीर की मुख्यधारा की राजनैतिक पार्टियों के साथ वार्ता शुरू करने तक की बातें शामिल हैं. लेकिन अभी इनमें किसी की भी पुष्टि नहीं हो पाई है. कुछ जिलों में सुरक्षा बलों की नई टुकड़ियों के आने से इन अफवाहों को हवा मिली. हालांकि पुलिस का कहना है कि ये टुकड़ियां राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद लौट रही हैं. उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अफवाहों पर विराम लगा दिया है, लेकिन आशंकाएं बरकरार हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद तथा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हसनैन मसूदी कहते हैं, ''हमें यकीन नहीं है.''

लोग 5 अगस्त 2019 से ऐन पहले का हवाला दे रहे हैं जब तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को लेकर उपजे 'सार्वजनिक डर' को इसी तरह बेबुनियाद बताया था. मसूदी कहते हैं, ''हम आशा और प्रार्थना कर सकते हैं कि कोई नया प्रयोग न हो. मुझे उम्मीद है कि उप-राज्यपाल की अफवाहों को बेबुनियाद बताने की बात सच हो. वैसे, हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं.''

ताजा अफवाहों से फोकस पीपल्स एलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) की ओर मुड़ गया है. पीएजीडी पांच पार्टियों का मोर्चा है जो जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति और राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहा है. सज्जाद लोन की अगुआई वाला पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस गठबंधन को अलविदा कह दिया है और अब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), माकपा, जम्मू-कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं. पीएजीडी की 9 जून को पूर्व मुख्यमंत्री तथा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास फेयरव्यू पर छह महीने बाद बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, पीएजीडी प्रमुख, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला के केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख से कई लोग हैरान थे.

सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ हुसैन सहित कुछ नेताओं से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत का पिछला दरवाजा खोला है ताकि जम्मू-कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया बहाल की जा सके. बातचीत के विषय परिसीमन प्रक्रिया और नए विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाली है. सूत्रों के मुताबिक, क्षेत्रीय दलों को अगले कुछ हफ्तों में बातचीत का न्यौता मिल सकता है.

सूत्र यह भी बताते हैं कि 'मध्यस्थों' से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद पीएजीडी का रुख नरम हुआ है. हाल में उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य में कोविड संबंधी तैयारियों पर सुझाव के लिए अब्दुल्ला, सज्जाद लोन और स्थानीय कांग्रेस अध्यक्ष जी.ए. मीर को बुलाया था, जिसे एक संकेत माना जा रहा है. नौकरशाही में कुछ फेरबदल हुए हैं. बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम की जगह जम्मू-कश्मीर काडर के आइएएस अधिकारी अरुण कुमार मेहता को मुख्य सचिव बनाया

गया. अगस्त 2019 की घटनाएं सुब्रह्मण्यम की देखरेख में ही हुई थीं और वे मुख्यधारा के राजनैतिक दलों को कुशासन और भ्रष्टाचार का जिम्मेदार मानते रहे हैं.

मसूदी मानते हैं कि ये बदलाव सकारात्मक हैं, मगर जमीन पर अमन और प्रगति के संकेत नहीं हैं. राज्य में आतंकवाद बढ़ रहा है और जनवरी से अब तक 40 से अधिक युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हो चुके हैं. यह पुलिस की आतंकवादियों की सार्वजनिक अंत्येष्टि की अनुमति नहीं देने जैसी कठोर नीतियों के बावजूद हो रहा है. मसूदी कहते हैं, ''यह यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) जैसे कठोर कानूनों का डर दिखाकर कायम की गई खोखली शांति है. पिछले दो वर्षों में नई दिल्ली और कश्मीर के बीच की खाई चौड़ी हुई है. केंद्र सरकार के पास दस लाख वजहें हैं कि वह जम्मू-कश्मीर से जुड़े विशेष प्रावधानों को रद्द करने के अपने कदम की समीक्षा करे क्योंकि इससे अमन और प्रगति का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है.''

राज्य में जून 2018 में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने के बाद से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से केंद्र का शासन है. राजनैतिक शून्यता और अधिकारों के हनन पर अंतरराष्ट्रीय प्रेस में आई रिपोर्टों के साथ, यह माना जाता है कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने का भाजपा सरकार पर 'बाहरी दबाव' है. 9 जून को दक्षिण और मध्य एशिया के प्रभारी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री, डीन थॉम्पसन ने 'हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में लोकतंत्र' पर संसद में कहा कि जो बाइडन की सरकार ने भारत सरकार से जितना जल्दी हो सके कश्मीर में सामान्य स्थिति लौटाने का आग्रह किया है. थॉम्पसन ने कहा, ''इसके अलावा हम देखना चाहते हैं कि चुनावी कदम उठाए जाएं. हमने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है और आगे भी करते रहेंगे.''

साल के आखिर तक चुनाव की कवायद शुरू होने की उम्मीद है. एक सूत्र ने बताया, ''नवंबर-दिसंबर में चुनाव की संभावना है, लेकिन अगर तीसरी कोविड लहर का प्रकोप बढ़ता है, तो अगले साल वसंत तक के लिए टाल दिया जाएगा. लेकिन वे (केंद्र) अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते.''

चुनाव से पहले केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी क्षेत्रों के फिर से सीमांकन के लिए परिसीमन किया जाएगा. पिछले साल 6 मार्च को केंद्र ने परिसीमन आयोग का गठन किया था जिसमें जम्मू-कश्मीर के पांच निर्वाचित सांसद सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल थे. एनसी के तीन सदस्यों ने यह कहते हुए पैनल का बहिष्कार किया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है. परिसीमन में विधानसभा की सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 हो जाएंगी, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आरक्षित हैं.

नेशनल कॉन्फ्रेंस की केंद्रीय कार्यसमिति की बैठक 27 मई को हुई. नाम न छापने की शर्त पर एक नेता बताते हैं, ''बैठक में शामिल लगभग 98 प्रतिशत लोग इस प्रक्रिया (परिसीमन और चुनाव) का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे.'' उनका तर्क था कि राजनैतिक शून्यता लोगों के लिए कठिनाई पैदा कर रही है, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए, जहां अनुच्छेद 370 को बहाल करने के मामले की सुनवाई पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ कर रही है.

दिल्ली से अनौपचारिक बातचीत ने विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाली की संभावना जगाई, पर कश्मीर के नेता सशंकित

पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला को अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है. लेकिन पार्टी इसका निर्णय परिसीमन आयोग को लिखे गए अब्दुल्ला के पत्र पर प्रतिक्रिया आने के बाद ही करेगी. एनसी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ''अगर वे हमारी राय पर विचार करते हैं, तो हम इस पर गौर कर सकते हैं लेकिन अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है.'' आयोग जल्द ही जम्मू-कश्मीर का दौरा कर सकता है.

एनसी और पीडीपी के रुख में बदलाव के बारे में कई तरह की बातें कही जा रही हैं. एक वजह तो अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के मामले बताए जा रहे हैं. फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को ईडी कार्यालयों में तलब किया गया था और इसे राजनैतिक प्रतिशोध के रूप में ही देखा गया था. अब्दुल्ला पर जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में 43.69 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगे हैं. इसी तरह मुफ्ती परिवार के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं. महबूबा और उनकी मां के पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं.

अनुच्छेद 370 के बहाल होने तक बातचीत के मुखर विरोधियों में से एक, एनसी के वरिष्ठ नेता तथा बडगाम के पूर्व विधायक आगा रूहुल्लाह इस बात से सहमत हैं कि ईडी के मामले ही नेताओं के रुख में नरमी की वजह हो सकते हैं. वे कहते हैं, ''हमें सत्ता की राजनीति को भूल जाना चाहिए. गुप्कार एलायंस ने भी निराश किया है. जम्मू-कश्मीर के लोग आखिर कहां खड़े हैं? नई दिल्ली निर्देश दे रही है और एलायंस उन निर्देशों का पालन कर रहा है.''

लेकिन मुख्यधारा की पार्टियों में यह एहसास बढ़ रहा है कि चुनाव से दूर रहने से भाजपा को वाकओवर मिल रहा है. एनसी और पीडीपी ने अक्तूबर-नवंबर 2018 में स्थानीय निकाय चुनाव का बहिष्कार किया था, जिससे भाजपा और निर्दलीयों का स्थानीय निकायों पर कब्जा हो गया था. महबूबा मुफ्ती का तर्क है कि विधानसभा चुनाव में नहीं खड़े होने से विरोधियों को मौका मिल जाएगा. महबूबा कहती हैं, ''जब आप प्रशासन का हिस्सा होते हैं, तो कम से कम आप कुछ चीजों का विरोध तो कर सकते हैं. कोई विरोध ही न हो तो वे नाजायज चीजों को वैध बनाते जाएंगे.''

कश्मीरियों की गिरफ्तारी, राजनैतिक अधिकारों की कमी और जनता/राजनैतिक नेताओं के बढ़ते उत्पीड़न से भी पीएजीडी चिंतित है. पीएजीडी की उपाध्यक्ष महबूबा कहती हैं, ''दम घुटने लगा है. वे (भाजपा) जम्मू-कश्मीर के लोगों को दबाने के लिए देश की ताकत लगा रहे हैं. वे असहमति की आवाज को आपराधिक कृत्य बताकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं. लगता है, वे हमारे वजूद को मानने को तैयार नहीं हैं.''

हालांकि, जमीनी स्तर पर राजनैतिक दलों ने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है. दक्षिण कश्मीर के सोहेल अहमद कहते हैं, ''विशेष दर्जा नई दिल्ली और कश्मीर को एक करने का पुल था. लेकिन हम इतने दूर कभी नहीं रहे.'' ■

अंतहीन मुसीबत

रोहित परिहार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 जून को चिकित्सीय सलाह का हवाला देते हुए कोविड के बाद की समस्याओं से बचने के एहतियाती उपाय के तहत एक-दो महीने के लिए लोगों से आमने-सामने मिलने के अपने सभी कार्यक्रमों को रोक दिया. सियासी हलकों में उनके इस ऐलान को ऐसे बयान के रूप में पेश किया गया कि वे बागी नेता सचिन पायलट की सत्ता में साझेदारी की मांग के प्रति अपने सख्त रवैये को नरम करने के मूड में नहीं हैं. इस बीच 16 जून को पायलट दिल्ली से जयपुर लौट आए. उनके बारे में बताया गया था कि वे प्रियंका गांधी से मिलने गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई. उसी रोज शहर में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, जिनमें से एक में पिछले साल बगावत में पायलट के सहयोगी रहे भंवर लाल शर्मा ने गहलोत को अपना नेता घोषित कर दिया. दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बसपा के टिकट पर जीते और कांग्रेस में शामिल हो गए छह विधायकों ने किया. उन्होंने आलाकमान से कहा कि वह उन बागियों को दरकिनार कर दे जिन्होंने सरकार को लगभग गिरा दिया था और उसे बचाने वाले वफादारों को अहमियत दे.

खबर है कि दिग्गज नेता कमलनाथ को गहलोत-पायलट के बीच के झगड़ा को दूर करने को कहा गया है. वैसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर दिया. लेकिन आम तौर पर शांत रहने वाले अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह ने आलाकमान से मांग की है कि वह बीते साल अगस्त में पायलट से उनकी बगावत वापस लेने के एवज में किए वादे पूरा करे. दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री पद न मिलने पर जब पायलट ने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख का पद छोड़ने की धमकी दी थी तो जितेंद्र सिंह ने उन्हें शांत करने में अहम भूमिका निभाई थी. बगावत के दौरान भी उन्होंने मध्यस्थता की थी.

खत्म नहीं हो रहा गतिरोध

पिछले कुछ रोज से राजस्थान कांग्रेस में सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन पार्टी के भीतर गतिरोध लंबे समय तक चलेगा. पायलट ने सार्वजनिक तौर पर आलाकमान पर आरोप लगाया कि वह उनकी समस्याओं की ओर से बेखबर है, जबकि उसने पंजाब में बागियों की शिकायत पर दो बार फौरन प्रतिक्रिया दिखाई है. उन्होंने सुर्खियां बटोरने के लिए यह आरोप ऐसे समय लगाया जब उनके करीबी दोस्त जितिन प्रसाद 9 जून को कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए. उनका आशय था कि क्या उन्हें भी प्रसाद की तरह पार्टी छोड़ देनी चाहिए. तभी भाजपा नेता रीता बहुगुणा ने अप्रत्याशित बयान दिया कि उन्होंने पायलट से भाजपा में शामिल होने को कहा है. सियासत पर नजर रखने वालों का मानना है कि यह आलाकमान को पायलट पर ध्यान देने के लिए बाध्य करने का तरीका हो सकता है. उनके पिता की 11 जून को बरसी होती है, लेकिन राजस्थान में अब यह उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब सचिन ने बगावत की योजना बनाई थी. वे दौसा में बरसी के अवसर पर जमा होने वाले विधायकों को गुड़गांव ले गए थे लेकिन गहलोत ने 10 जून को ही सारे कांग्रेसी और निर्दलीय विधायकों को होटल में पहुंचाकर उनकी योजना की हवा निकाल दी थी. फिर पायलट ने अपनी योजना पर एक महीने बाद अमल किया.

पायलट की गतिविधियों से लगता है कि वे एक ओर तो भाजपा में न जाने का ऐलान करते हैं, वहीं वे अपनी ऐसी चाल से आलाकमान को स्तब्ध कर देना चाहते हैं. यह भी खबरें हैं कि वे जितिन प्रसाद की नई शुरुआत की खुशी में आयोजित पार्टी में शामिल हुए. उस पार्टी में कथित तौर भाजपा सांसद सैयद जफर इस्लाम शामिल थे, जिन्होंने पिछले साल पायलट के समर्थक विधायकों की गुड़गांव में एक महीने तक मेजबानी की थी. जफर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में भी ऐसी ही भूमिका निभाई थी. उस पार्टी में कथित तौर पर सिंधिया, आर.पी.एन. सिंह और मिलिंद देवड़ा भी शामिल थे. राजस्थान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, ''अगर वे परिपक्व नेता होते तो वे उस पार्टी में शामिल होकर इस धारणा को मजबूती नहीं देते कि वे भाजपा से पींगें बढ़ा रहे हैं.'' लेकिन पायलट ने बहुगुणा के बयान को खारिज करते हुए कहा: ''वे मुझे कॉल करने की जुर्रत नहीं कर सकतीं. उन्होंने सचिन तेंडुलकर को कॉल किया होगा.'' बहुगुणा के बयान को सही मानने वाले लोगों का कहना है कि पायलट की प्रतिक्रिया से वे काफी आहत हुई हैं. पायलट अतीत में अपने कई समर्थकों के साथ ऐसा व्यवहार कर चुके हैं.

आलाकमान से मायूस गहलोत

पायलट और उनके लोग जयपुर में अपने सार्वजनिक बयानों के जरिए गहलोत को निशाना बनाने के लिए भाजपा को हथियार मुहैया करा रहे हैं. इससे लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस सरकार की नैया डूब रही है. जाहिर है, यह गहलोत को गवारा नहीं है और अब बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने से नाराज होने की बारी मुख्यमंत्री की है. कुछ बागी आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति विरोधी है और वह कुछ बागी विधायकों के फोन टैप करा रही है. ऐसे आरोपों से गहलोत सरकार की छवि को बट्टा लगा है और भाजपा को भी सरकार और कांग्रेस को खराब बताने का मौका मिल

एएनआइ

तनातनी जारी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (बीच में) और सचिन पायलट (गहलोत के दाएं) के बीच की दूरियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहीं

गया है. गहलोत सरकार के एक मंत्री ने बताया, ''हमें भाजपा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे अपने बागी उसकी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं.'' एक और मंत्री का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान ने अनुशासनहीनता बर्दाश्त करके और उसे पुरस्कृत करने की छवि पेश करके खुद को और गहलोत सरकार को लोगों की नजर में कमजोर बना दिया है.

क्वारंटीन की घोषणा से पहले एक हफ्ते तक गहलोत ने कुछ बागी विधायकों से संपर्क किया जिनमें से कुछ ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री मान लिया और उनके समर्थक हो गए. पिछले साल अगस्त में आलाकमान ने उनके और पायलट के बीच समझौता करा दिया था. तब से उन्होंने शालीनता के साथ खामोशी बनाए रखी है. वैसे उनके कुछ समर्थकों ने बागियों और आलाकमान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है. बसपा से आए छह विधायक चाहते हैं कि आलाकमान कांग्रेस सरकार को बचाने और भाजपा के सहयोग से उसे गिराने का प्रयास करने वालों के बीच फर्क करे और बागियों को हतोत्साहित करे. तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री और गहलोत के विश्वासपात्र सुभाष गर्ग ने 13 जून को ट्वीट किया: ''यह ऐसा मौसम है जब चिड़िया अपने घोंसले बदलने के लिए बेताब होती हैं.'' इससे कांग्रेस सरकार बचाने वाले लोगों में यह एहसास बढ़ने का संकेत मिलता है कि बागी नेता कभी भी बेहतर संभावना की तलाश में कांग्रेस छोड़ सकते हैं. वे विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा कर सकते हैं, लिहाजा उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए. गहलोत ने एक बार *इंडिया टुडे* से कहा था कि अगर आलाकमान ने पायलट की बगावत के बारे में उनकी पूर्व सूचना पर यकीन किया होता, जिसके बारे में उन्होंने जून में ही बता दिया था और पायलट को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के पद से हटा दिया होता तो जुलाई में बगावत को रोका जा सकता था.

> **''मैं सचिन पायलट को भी नेता मानता हूं, पर अशोक गहलोत उनसे ऊपर हैं. मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे थे, पर इस बजट में सीएम ने मांगों को पूरा कर दिया''**
>
> **भंवर लाल शर्मा**
> विधायक, कांग्रेस

तो पायलट चाहते क्या हैं? जाहिर है, उन्हें अब भी यह लगता है कि नखरे दिखाने से उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है. लेकिन उनका मुख्य प्रयास यह है कि वे अपने वफादारों को मंत्री पद समेत प्रमुख ओहदे दिलाएं ताकि उनका प्रभाव बना रहे. वे जिला स्तर की सरकारी समितियों में करीब 20,000 नियुक्तियों में अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल करना चाहते हैं. गहलोत इन समितियों में नियुक्ति करने वाले हैं. लेकिन दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पिछड़ने के बाद से ही सचिन ने अपना जनाधार बढ़ाने की खास कोशिश नहीं की है. सरकार को स्थिर करने की उनकी मंशा और वक्त के साथ उनका जनाधार खिसकता गया.

अब यह साफ है कि आलाकमान ने समिति गठित करने के अलावा पायलट खेमे से कोई वादा नहीं किया था. तख्तापलट के प्रयास में पायलट के सहयोगी रहे भंवर लाल शर्मा का कहना है कि वह समिति बगावत को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बनाई गई थी. पायलट के एक अन्य सहयोगी दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 16 जून को कहा कि बागी कोई पद नहीं चाहते थे, वे सिर्फ सम्मान चाहते थे. गहलोत ने उनकी सम्मानजनक वापसी करा दी. उन्होंने पायलट को उससे बड़े सरकारी बंगले में रहने दिया, जिसके वे हकदार हैं. आला दर्जे की सुरक्षा देने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के पुनर्गठन में उनके सुझावों को भी मान लिया. पायलट खेमे के कई बागियों ने खुलकर कहा है कि गहलोत उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जमकर काम आवंटित कर रहे हैं. गहलोत उनमें से कुछ को बोर्ड और निगमों में भी शामिल करने वाले हैं.

गांधी परिवार के पायलट के साथ मुलाकात से इनकार के मद्देनजर इस बागी नेता के पास अब अपना जनाधार बढ़ाने की खातिर जमकर काम करने या कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने या अपनी पार्टी बनाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. गांधी परिवार के खेमे पर बेजा आरोपों की वजह से राज्य और देश में कांग्रेस सरकार की खिल्ली उड़ाई जा रही है. अब यह आलाकमान के ऊपर है कि वह बागियों को अनुशासनहीनता फैलाने की छूट देकर सरकार को कमजोर करे या एक झटके में समस्या से पार पा जाए. ■

त्रिकोणीय खींचतान

अमरनाथ के. मेनन

खेमे
ई.के. पलानीस्वामी (दाएं) और ओ. पन्नीरसेल्वम मार्च 2021 में अन्नाद्रमुक का घोषणापत्र जारी करने के दौरान और वी.के. शशिकला (नीचे दाएं)

अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में हार के बाद से अन्नाद्रमुक (अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के शीर्ष नेताओं के बीच टकराव बढ़ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने हाल में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे लगता है कि वे पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि अन्नाद्रमुक विधायक दल की कार्यकारिणी में संख्याबल और चुनावी रूप से महत्वपूर्ण तमिलनाडु के कई महत्वपूर्ण समुदायों का प्रतिनिधित्व हो. उन्होंने 14 जून को अपने एक वफादार और पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि की विधानसभा में पार्टी व्हिप के रूप में नियुक्ति की. ईपीएस के प्रतिद्वंद्वी ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) खेमे की इस पद पर नजर थी. ईपीएस, जो अन्नाद्रमुक के 66 सदस्यीय विधायक दल के नेता हैं, ओपीएस को विधायक दल के उप नेता के पद के साथ ही राजी करने में भी सफल रहे.

विश्लेषकों का कहना है कि इन नियुक्तियों के साथ, 67 वर्षीय ईपीएस को पार्टी पर बढ़त हासिल हो गई है और वे सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके हैं जबकि ओपीएस अब दूसरे नंबर पर रहने को विवश हैं. 70 वर्षीय ओपीएस विपक्ष के नेता नहीं बने और इससे वे नाराज बताए जाते हैं. ईपीएस जो फरवरी 2017 से चार साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री थे, के विपरीत ओपीएस केवल तब मुख्यमंत्री बने हैं जब किसी कारण से मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी. कामचलाऊ सीएम के रूप में उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा है. दिसंबर 2016 में जे. जयललिता की मृत्यु के बाद इस पद पर नियुक्त हुए थे. ओपीएस को लगता है कि उन्हें ईपीएस के लिए कुर्सी खाली करने के बजाए, सीएम बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए थी.

14 जून को विधायक दल के उपनेता के चुनाव से पहले तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ईपीएस विरोधी पोस्टर लगे थे और ओपीएस, जो अपना दबदबा दिखाने को आतुर थे, ने संकेत दिया कि वे ईपीएस के डिप्टी के रूप में काम करने के इच्छुक नहीं हैं. हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि फिलहाल वे खुद को एक मजबूत चुनौती के रूप में पेश करने से पीछे हट गए हैं.

शशिकला की छाया

वी.के. शशिकला, जो पार्टी में वापस अपनी जगह तलाश रही हैं, पहले से परेशानी में चल रही अन्नाद्रमुक की मुश्किलों को और बढ़ा रही हैं. शशिकला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए गया और फरवरी 2017 में उन्हें चार साल की जेल हो गई. इस कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ आते-आते रह गई. इस साल जनवरी में जेल से रिहा हुईं 66 वर्षीय राजनेता अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए छटपटा रही हैं. लंबे समय तक जयललिता की करीबी सहयोगी रहीं शशिकला ने अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं के साथ अपनी कथित बातचीत के 30 ऑडियो टेप जारी किए हैं, जिसमें वे कार्यकर्ताओं को आश्वासन दे रही हैं कि जल्द ही पार्टी में अपनी वापसी करके प्रमुख भूमिका निभाएंगी.

अन्नाद्रमुक में कई लोग, विशेष रूप से ईपीएस समर्थक, शशिकला के पार्टी के भीतर सत्ता के केंद्र के रूप में फिर से उभरने का कड़ा विरोध कर रहे हैं. शशिकला, ईपीएस-ओपीएस के बीच तनातनी का फायदा उठाकर पार्टी पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगी. इसकी आशंका ईपीएस और ओपीएस दोनों गुट में है. इसीलिए 14 जून को शशिकला सहानुभूति रखने वाले 17 नेताओं को अन्नाद्रमुक से निष्कासित कर दिया गया. उनमें पार्टी प्रवक्ता वी. पुगाझेंधी, पूर्व मंत्री एम. आनंदन और पूर्व सांसद वी.के. चिन्नासामी शामिल हैं.

इस साल जनवरी में जेल से रिहा हुई 66 वर्षीया शशिकला अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए छटपटा रही हैं. उन्होने अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं से अपनी बातचीत के 30 टेप जारी किए हैं

अन्नाद्रमुक ने जारी बयान में काफी सख्त लहजे में कहा, ''एक मजबूत ताकत होने के नाते पार्टी एक परिवार (शशिकला और उनके भतीजे टी.टी.वी. दिनाकरण) की आकांक्षाओं के आगे नहीं झुकने वाली.'' बयान में कहा गया है कि पार्टी में पनपे कुछ 'विषैले पौधे', पार्टी को हथियाने की कोशिश कर रहे थे. 14 जून की बैठक में शशिकला की ओर से पार्टी को 'अपनी गिरफ्त में लेने के प्रयासों' और इसी नीयत से कुछ सदस्यों से संपर्क साधने की कोशिशों की भी निंदा की गई.

अन्नाद्रमुक के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि ईपीएस विरोधी पोस्टरों के पीछे शशिकला का हाथ हो सकता है ताकि ईपीएस और ओपीएस के बीच दरार और बढ़ जाए. उन्हें आशंका है कि शशिकला के बहकावे में आकर पार्टी के असंतुष्ट एक साल के भीतर चुपचाप तरीके से कई गुना बढ़ सकते हैं, हालांकि उनके लिए पार्टी पर नियंत्रण करना आसान नहीं होगा. राजनीतिक टिप्पणीकार एन. सत्यमूर्ति कहते हैं, ''शशिकला के पास निकट भविष्य में अपनी पकड़ बनाने का बहुत कम या कोई मौका नहीं दिखता. ओपीएस ने दिखा दिया है कि उनके पास अब एक मजबूत लड़ाई की ताकत नहीं बची है, इसलिए शशिकला उनके साथ मिलकर अपने मंसूबों को आगे नहीं बढ़ाना चाहेंगी. उन्हें अन्नाद्रमुक नेतृत्व को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामले के फैसले का भी इंतजार करना होगा, जो अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएगा.''

अधर में भविष्य

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में सहयोगी दलों के साथ केवल 75 सीटें जीतने वाली अन्नाद्रमुक को मतदाताओं का विश्वास फिर से हासिल करने की आस लगाने से पहले, एक लंबा रास्ता तय करना होगा. विश्लेषकों का कहना है कि अंदरूनी कलह नगरपालिका चुनावों में पार्टी की संभावनाओं को बर्बाद कर सकती है. नगरपालिका चुनावों के मौजूदा महामारी की लहर के समाप्त होने के बाद कराए जाने की संभावना है. बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी राज्य के पश्चिमी हिस्से, जो कि ईपीएस का गढ़ है, में बेहतर प्रदर्शन करती है या फिर दक्षिणी क्षेत्रों में जहां ओपीएस का दबदबा है.

एक और गंभीर आशंका, भ्रष्टाचार के मामलों और संभावित मुकदमों और उनके कारण गिरफ्तारी को लेकर भी बनी है. 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव से तीन महीने पहले, द्रमुक ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को अन्नाद्रमुक सरकार और उसके कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक लंबी सूची सौंपी थी. ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री के रूप में एम.के. स्टालिन के इन मामलों को लेकर विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाए रखेंगे. सत्यमूर्ति कहते हैं, ''अगर एम.के. स्टालिन सत्ता में आने के बाद चुनाव से पहले लगाए गए अपने आरोपों को लेकर नरम रुख अपनाते हैं तो लोग उन्हें संदेह की नजर से देखेंगे. यह उनकी या द्रमुक की साख के लिहाज से अच्छा नहीं होगा.''

पूर्व मंत्रियों और अन्नाद्रमुक के अन्य मध्यम-स्तर के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से ईपीएस और ओपीएस के बीच जो छद्म एकता दिख रही है, उसकी कलई खुल सकती है. शशिकला इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगी. इस बीच, ईपीएस के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है. ईपीएस की तुलना युगांडा के पूर्व राष्ट्रपति ईदी अमीन से करते हुए, जो अपने शासनकाल में क्रूरता के लिए कुख्यात थे, पुगझेंडी कहते हैं, ''ईपीएस सबके साथ एक गुलाम की तरह बर्ताव कर रहे हैं. मैं आने वाले समय में और भी कई चीजों का खुलासा करूंगा.''

ईपीएस और ओपीएस धड़े एक दूसरे के आमने-सामने खड़े हैं और शशिकला फायदा उठाने की ताक में हैं. ऐसा लगता है जैसे अन्नाद्रमुक किसी बड़े उथल-पुथल भरे दौर की ओर बढ़ रही है. शशिकला लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता. साथ ही वे यह भी कहती हैं कि पार्टी काडर की खराब हालत के मद्देनजर वे मूक दर्शक नहीं बनी रह सकतीं. वे पार्टी कार्यकर्ताओं के फोन कॉल्स रिसीव करती हैं और उनके सवालों का जवाब भी देती हैं. उनका कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी. इससे पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के अंदर खलबली मचना स्वाभाविक है. पार्टी जब चुनाव हारती है तो उसके अंदर भी बहुत कुछ टूटता है.

मद्रास विश्वविद्यालय में राजनीति और लोक प्रशासन विभाग के प्रमुख रामू मणिवक्कन कहते हैं, ''ऐसा लगता है कि ईपीएस और ओपीएस दोनों में से कोई भी, 2026 के विधानसभा चुनाव में भी अन्नाद्रमुक को एकजुट रखने और उसका नेतृत्व करने में सक्षम नहीं होगा. पार्टी को एक नए नेता या एक नए मंत्र की जरूरत है.'' फिलहाल, इसके आसार नहीं दिखते. ■

‘चिराग’ से ही बंगले में आग?

रामविलास पासवान के निधन के कुछ महीनों बाद ही पासवान कुनबा बिखरा, चिराग फिलहाल अकेले पड़े मगर विरासत की जंग लंबी चलने के आसार

अमिताभ श्रीवास्तव

रंजन राही

दोफाड़ परिवार और पार्टी
पटना में लोजपा के पांच सांसदों और अन्य नेताओं के साथ पशुपति कुमार पारस (बीच में माला पहने); और (दाएं) चिराग पासवान

रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को सोमवार 14 जून को पहले तो अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के बंगले में दाखिल होने के लिए गेट के बाहर कार में 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा. विडंबना देखिए कि अपने पिता राम विलास पासवान की बनाई जिस लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के वे अध्यक्ष हैं, उसका चुनाव चिह्न भी बंगला है. फिर, गेट खुला तो बंगले के भीतरी दरवाजे चिराग की अगवानी के लिए खुले नहीं थे. उन्हें बंद दरवाजे पर कई बार दस्तक देनी पड़ी. जिस बंगले में वे बेरोकटोक आते थे, अब वहां वे अनचाहे अतिथि थे.

रविवार को पार्टी के पांच लोकसभा सदस्यों ने चिराग को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया तो वे चाचा के घर पहुंचे थे. पारस ने दावा किया कि वे पार्टी तोड़ नहीं रहे, बल्कि ''बचा रहे हैं.'' मंगलवार को पारस गुट ने बताया कि चिराग को लोजपा प्रमुख के पद से भी हटा दिया गया है. 13 जून को लोजपा के छह में से पांच सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात की और पारस को लोकसभा में पार्टी के नए नेता के रूप में मान्यता देने की मांग की. सोमवार दोपहर तक लोकसभा सचिवालय ने यह मान्यता प्रदान कर दी. इससे चिराग पासवान पार्टी में हाशिए पर पहुंच गए हैं, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व वे अक्तूबर 2020 में अपने पिता रामविलास पासवान के निधन से काफी पहले से ही संभाल रहे थे.

इस अचानक झटके के बावजूद चिराग ने 'बंगले' को संभालने की कोशिश की. वे लोजपा प्रमुख का पद छोड़ने और अपनी मां रीना पासवान को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव के साथ चाचा के घर गए थे. लेकिन उन्हें लगभग 90 मिनट तक इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि पारस घर पर नहीं थे.

लेकिन, एक दिन बाद चिराग ने तेवर सख्त कर लिए. 15 जून को लोजपा में उनके गुट ने पांच सांसदों की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता खत्म कर दी. चिराग ने 'आदरणीय चाचाजी' के संबोधन के साथ शुरू हुआ पारस को लिखा एक पुराना पत्र भी ट्वीट किया, जिसमें चाचा के साथ मतभेदों का विस्तृत ब्यौरा था. 29 मार्च को लिखी 4 पन्ने की चिट्ठी में चिराग ने पारस की विभिन्न शिकायतों के बारे में बात की जिसमें पासवान परिवार के एक अन्य सदस्य, प्रिंस राज को बिहार लोजपा प्रमुख बनाए जाने पर पारस की कथित नाखुशी का जिक्र भी है. प्रिंस राज फिलहाल पारस के साथ हैं. चिराग ने यह भी दावा किया कि उनके पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पारस के रवैये से दिवंगत रामविलास पासवान नाखुश थे और पारस की नीतीश कुमार की प्रशंसा ने बिहार चुनावों में लोजपा के प्रदर्शन को झटका दिया था.

इस बीच, पारस गुट ने चिराग को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटा दिया, तो बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग ने लंबी कानूनी लड़ाई का इशारा किया कि वे अभी भी पार्टी के प्रमुख हैं.

पारस का आरोप है कि चिराग पार्टी के संविधान के मुताबिक 'एक व्यक्ति-एक पद' की भावना के विपरीत तानाशाही शैली अपनाते हैं. पारस गुट के मुताबिक, चिराग तीन पदों पर काबिज हैं. 2013 से पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होने के अलावा, चिराग संसदीय दल के नेता भी थे और 2019 में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया. पारस गुट का कहना है कि इसी वजह से चिराग को संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया गया. पारस 17 जून को पटना में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए.

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का समर्थन करने वाले पांच सांसदों में पारस, उनके भतीजे प्रिंस पासवान (प्रिंस, पूर्व सांसद दिवंगत रामचंद्र पासवान के बेटे हैं), चंदन सिंह, वीणा देवी और महबूब अली कैसर हैं.

बगावत का समय भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि केंद्र में कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है. राजनैतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बगावत जद (यू) की शह पर हुई है और पारस गुट को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है. दरअसल, चिराग के नीतीश कुमार सरकार पर लगातार हमले से उनकी पार्टी के लोग भी बहुत खुश

एएनआइ

नहीं थे. इसी के साथ बिहार चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने और विधानसभा चुनाव में लोजपा के लगभग सफाए से भी पार्टी में कई लोग चिराग के फैसलों से नाखुश थे.

चाचा पारस और भतीजे चिराग के बीच बढ़ती तनातनी पार्टी में शायद ही किसी से छिपी थी. अंग्रेजी बोलने वाले बातों के उस्ताद चिराग अपने चाचा के साथ कभी भी सहज नहीं थे, जिन्होंने एक बार 2011 में बॉलीवुड में भी अपने लिए संभावनाएं टटोली थीं. पारस पुरानी शैली के नेता हैं, जिन्हें लोजपा में हमेशा दूसरे नंबर के नेता के रूप में देखा जाता था लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान के उभरने के बाद यह व्यवस्था बदल गई.

2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करने का चिराग का एकतरफा जुनून ही शायद उनके संकट का सबब बना है. लोजपा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले तक एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ चिराग ने नीतीश पर हमले शुरू कर दिए. लोजपा ने चुनाव में उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिन पर जद (यू) ने चुनाव लड़ा था और नीतीश की पार्टी के वोट काटे. जद (यू) नेताओं ने अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए निजी तौर पर चिराग को जिम्मेदार ठहराया. एनडीए गठबंधन में जद (यू) पहली बार दूसरे स्थान पर रही थी. 243 सदस्यीय सदन में जद (यू) 115 सीटों पर लड़कर केवल 43 ही जीत सकी. भाजपा 110 सीटों पर लड़कर 74 सीटें जीत गई. लोजपा ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ एक सीट जीत सकी.

चिराग ने पिता की मृत्यु के बाद भी नीतीश विरोधी अभियान जारी रखा, जबकि चाचा पारस नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े दिखते थे, लेकिन चुप करा दिए गए थे. लंबी चुप्पी के बाद पारस ने इस जून में पलटवार किया तो चिराग के पैरों तले जमीन खिसक गई.

2019 के लोकसभा चुनावों के बाद पासवान परिवार ऐसा परिवार था जिसके सबसे ज्यादा सदस्य संसद में नजर आते थे. रामविलास पासवान राज्यसभा में थे. उनके बेटे चिराग पासवान और दो भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान लोकसभा में थे. जुलाई 2019 में रामचंद्र पासवान के निधन के बाद हुए उप-चुनाव में पासवान परिवार ने उनके बेटे प्रिंस को लोकसभा पहुंचाया. आज उस पासवान परिवार में इतनी फूट पड़ चुकी है कि भतीजे के लिए चाचा के घर के दरवाजे नहीं खुलते और भतीजे को अपने पिता की विरासत पर अधिकार जताने के लिए कानूनी दांवपेच ही एकमात्र रास्ता नजर आता है. समय का चक्र निराला है.

2019 से पहले रामविलास पासवान और चिराग का पूरा ध्यान राष्ट्रीय राजनीति में था. पारस को तब इतनी तसल्ली थी कि पार्टी की बिहार इकाई में उन्हीं की चलती थी. जुलाई 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में लौटे, बड़े पासवान ने उनसे पारस को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की गुजारिश की. नीतीश ने पासवान की बात मानते हुए पारस को पहले जुलाई 2017 में मंत्री बनाया और एक महीने बाद विधान परिषद में मनोनीत कर दिया. दो साल बाद जब पासवान ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, उन्होंने हाजीपुर की अपनी लोकसभा सीट पारस को दे दी.

मगर यही वक्त था जब पारस पर बड़े भाई की मेहरबानियां बंद होते देखी गईं. सितंबर 2019 में रामविलास पासवान ने बेटे चिराग को बिहार का पार्टी प्रभारी बना दिया, जहां पार्टी ने आम चुनाव में छह सीटों पर चुनाव लड़ा और छहों जीती थीं. इसके साथ ही चिराग ने बिहार पार्टी प्रमुख के ओहदे से पशुपति पारस को बेदखल कर दिया. इसे पार्टी में पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर देखा गया.

उसके बाद पारस लगातार दरकिनार होते गए. सूत्रों के मुताबिक, पारस ने बिहार विधानसभा का चुनाव अलग होकर लड़ने के अपने भतीजे का फैसले को कभी मंजूर नहीं किया. उम्मीदवारों के चयन में भी उनकी अनदेखी हुई. चुनाव से पहले पारस ने नीतीश की तारीफ की, तो बताया जाता है कि चिराग ने उन्हें पार्टी से निकाल देने की धमकी दी थी. इस बीच अप्रैल में लोजपा के इकलौते विधायक नीतीश के साथ साथ हो लिए. अब 14 जून को जब पारस ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहकर उनके कसीदे पढ़े, तो इशारा साफ था. उसी दिन जब टीवी कैमरों ने चिराग पासवान को अपने चाचा के घर के बंद गेट के सामने हॉर्न बजाते देखा गया, तो यह साफ हो गया कि पासवान परिवार दोफाड़ हो चुका है. ■

आस्था का नया स्थान

केसीआर ने धार्मिक प्रतिद्वंद्विता में आकर तिरुपति मंदिर को पीछे छोड़ने के प्रयास में एक भव्य धर्मस्थल पर शुरू करवाया काम. इस पर खर्च होंगे पूरे 1,800 करोड़ रुपए

अमरनाथ के. मेनन

हैदराबाद से यही कोई 70 किलोमीटर दूर उत्तर-पूर्व में यदागिरिगट्टा की तीखी पहाड़ी ढलान को खोद और काटकर चौरस बना दिया गया है और इस पर स्थित गुफा मंदिर अब एक विशाल मंदिर परिसर में तब्दील हो गया है. इसकी साज-सज्जा का काम अब आखिरी चरण में है. तपतपाती गर्मी में पसीना बहाते हुए कामगार सोने के रंग से सुशोभित 330 फुट लंबा एक गलियारा तैयार कर रहे हैं जो श्रद्धालुओं की कतार को नरसिंह स्वामी के गर्भगृह तक ले जाएगा. नरसिंह स्वामी हिंदू देवता विष्णु के अर्धनर और अर्धसिंह अवतार हैं, जो बुराई का नाश, धार्मिक उत्पीड़न का खात्मा और धर्म को बहाल करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बातों पर यकीन करें तो वे "21वीं सदी का विश्वस्तरीय हिंदू आध्यात्मिक ठिकाना" स्थापित कर रहे हैं. यह सब सरकारी खर्च से किया जा रहा है. मार्च 2015 में उन्होंने 1,885 एकड़ में फैली 1,800 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया था. इस जगह का नाम भी उन्होंने यदागिरिगट्टा से छोटा करके यदाद्रि रख दिया था, इस उम्मीद में कि यह देश का प्रमुख मंदिर पर्यटन केंद्र बनेगा. मंदिर के अलावा आसपास के इलाके को अनूठे मंदिर शहर के तौर पर विकसित किया जा रहा है. बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसा कि पड़ोसी आंध्र प्रदेश में हिंदू धर्म का लोकप्रिय मंदिर तिरुमला है. 2015 तक श्रद्धालुओं को नरसिंह स्वामी के चरणों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ऊबड़खाबड़ सीढ़ियों और पहाड़ी रास्ते से चढ़कर गुफा तक जाना पड़ता था. 13वीं सदी के इस मंदिर का निर्माण होयसला साम्राज्य के सेनापति बोमन्ना दंडनायक ने राजा वीर सोमेश्वर के शासनकाल के दौरान 1246 में करवाया था.

केसीआर ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से यदागिरिगट्टा मंदिर विकास प्राधिकरण (वाइटीडीए) बनाया और परियोजना पर अमल के लिए उसे तमाम अवसंरचना, विकास और राजस्व प्राधिकारियों की सेवाएं जुटाने के अधिकार सौंपे. मंदिर के निर्माण में आने वाली इंजीनियरिंग और दूसरी चुनौतियों का मुकाबला करने की खातिर वाइटीडीए को सलाह देने के लिए आला अफसरों से लैस तकनीकी समिति का गठन किया गया. मंदिर के निर्माण में सुविधा

इस तरह उत्थान
(एकदम ऊपर बाएं से क्रमशः) मंदिर का आज के समय का विहंगम दृश्य; पूर्वी गोपुरम पर कृष्णशिला से तैयार गज प्रतिमाएं; यदागिरिगट्टा मंदिर वाली पहाड़ी का 52 वर्ष पुराना दृश्य; और अभी चल रही निर्माण प्रक्रिया

केसीआर इस तथ्य से बखूबी वाकिफ हैं कि राज्य में खासकर भाजपा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अगर उन्होंने जन समर्थन पाने की नई युक्तियां नहीं तलाशीं तो तीसरी बार उनका तेलंगाना की सत्ता में आ पाना मुश्किल होगा

के लिए मूर्ति को जरूरी अनुष्ठानों का पालन करते हुए खास तौर पर बनाए गए बालालयम में ले जाया गया. जल्द ही मूर्ति को कुछ हफ्तों के पूजा-पाठ के बाद मंदिर के नए भव्य गर्भगृह में पुन: अधिष्ठापित किया जाएगा. यह सब वैष्णव पंथ के प्रवचनों के लिए विख्यात 64 वर्षीय संत त्रिदंडी चिन्ना श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामी की देखरेख में किया जा रहा है. हैदराबाद के दक्षिणी छोर पर उनका आश्रम है. केसीआर उन्हें बहुत मानते हैं (और उनके नाम के आगे भी बड़े संतों की तरह श्री श्री लगाया जाता है).

केसीआर इस तथ्य से बखूबी वाकिफ हैं कि राज्य में खासकर भाजपा के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अगर उन्होंने जन समर्थन पाने की नई युक्तियां नहीं तलाशीं तो तीसरी बार उनका सत्ता में आ पाना मुश्किल होगा. शायद इसीलिए वे भव्य मंदिर बनवाकर पड़ोसी राज्य में स्थित सबसे समृद्ध हिंदू मंदिर तिरुमला को पीछे छोड़ने के इरादे से धार्मिक प्रतिद्वंद्विता में उतर रहे हैं. राजनैतिक टीकाकार सी.

नरसिंह राव कहते हैं, ''केसीआर धार्मिक व्यक्ति हैं पर ऐसा भी नहीं कि वे आस्था के स्टंट के जरिए लोगों का दिल जीतने का प्रयास भी न करें. पहले भी राजनैतिक अस्तित्व के लिए उन्होंने जाति का समूहों के बीच की प्रतिद्वंद्विता का इस्तेमाल किया ही है.'' वे यह भी कहते हैं कि केसीआर की मध्ययुगीन सोच उन्हें लाभ पहुंचा रही है.

वाइटीडीए निवेशकों के लिए परियोजना को भावी पर्यटन स्थल के तौर पर भी पेश कर रही है. अनोखी दानदाता योजना के तहत एक नजदीकी पहाड़ी पर चार बेडरूम के 252 घर डेढ़-डेढ़ करोड़ में बेचे गए हैं. इसमें संरक्षकों को हर साल 30 दिन ठहरने के साथ मंदिर तक विशेष पहुंच भी मिलेगी. इनकी देखभाल करने वाला वाइटीडीए बाकी साल भर इन्हें आने वाले श्रद्धालुओं को किराए पर देकर आमदनी जुटाएगा. एक प्रेसिडेंशियल सुइट और 13 वीवीआइपी विला का काम भी तेजी से चल रहा है ताकि इन्हें मंदिर के उद्घाटन तक तैयार किया जा सके. मंदिर की प्रसादम और जनाहार योजनाओं के बिक्री के विवाद में पड़ने के अंदेशे से वाइटीडीए ने यह काम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) को आउटसोर्स कर दिया है जिसे मास कैटरिंग में महारत हासिल है.

केसीआर ने यहां के अपने पिछले प्रवास में अफसरों को यह पक्का करने के लिए कहा था कि यदाद्रि को साफ-सफाई और निरोगता के मामले में रोल मॉडल बनाएं. उनका कहना था कि ''बिजली व्यवस्था और जगमगाहट सभी इस तरह की जाए जिससे भक्ति और आनंद की भावनाएं जागृत हों.'' यदाद्रि परियोजना लॉन्च करते वक्त केसीआर ने मंदिर में आने वालों की तादाद वक्त के साथ आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ने की बात कही थी. पर फिलहाल श्रद्धालुओं की आवक कम ही है. हां, अस्थायी बालालयम में आने वालों की तादाद में जरूर पहले के मुकाबले बढ़ोतरी बताई गई है.

मंदिर और नगर की योजना परंपराओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. मंदिर का इलाका 2,500 वर्ग गज तक सीमित था जिसे पहाड़ी के 4.5 एकड़ में फैलाया गया है. मंदिर के भवन को थामने के लिए तीन तरफ 100 फुट ऊंची पुश्ते की दीवार खड़ी की गई है. सीमेंट की यह 4.5 फुट किलेबंदी दक्षिण में 1,300 फुट, पश्चिम में 320 फुट और उत्तर में 1,000 फुट तक जाती है ताकि टूटकर गिरने वाले पत्थरों को थाम सके और मंदिर के स्थापत्य को ऐसी ऊंचाई दे सके जिससे वह दूर से दिखाई दे.

वाइटीडीए के सीईओ और वाइस-चेयरमैन जी. किशन राव कहते हैं, ''मंदिर के निर्माण में इंजीनियरिंग और वास्तुकला दोनों की चुनौतियां पेश आईं क्योंकि इसमें लहरदार ढलान को समतल में बदलना था और ऐसे डिजाइन करना था जिनमें

आंकड़ों के आईने में यदाद्रि

उतर रही भव्यता

ग्राफिकः नीलांजन दास

6,500
श्रद्धालु औसतन रोजाना आ रहे थे मंदिर में, काम शुरू होने से पहले

2,50,000
टन
वजन की **9,30,000** घन फुट कृष्णशिला का इस्तेमाल हुआ है मंदिर निर्माण में

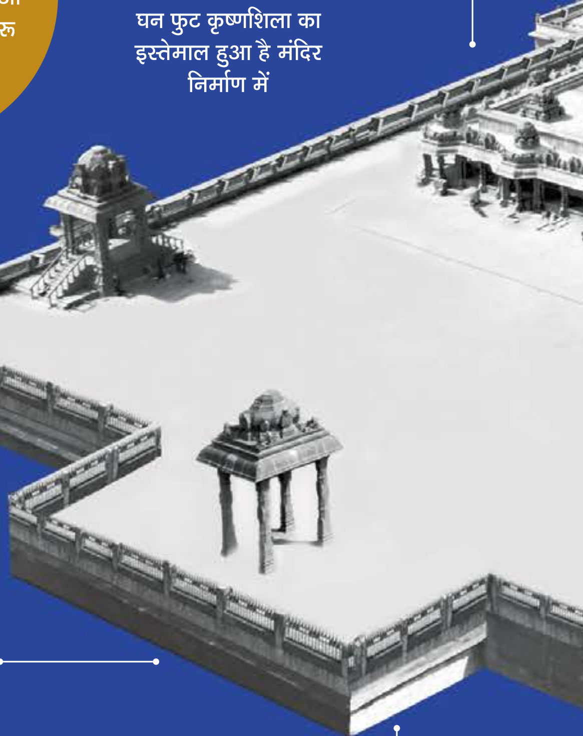

8,200
फुट
ऊंची रिटेनिंग दीवारें होंगी तीन तरफ, जिनकी मोटाई **4.5 फुट** होगी. उन्हें सीमेंट से मजबूती दी जाएगी

11,000
किलो
पीतल का प्रयोग हुआ दीवार के पैनलों और मंदिर के द्वारों को सजाने के लिए

मंदिर का समय चक्र

तेजी से बढ़ा घटनाक्रम

27 फरवरी, 2015
तेलंगाना सरकार ने यदागिरिगट्टा मंदिर विकास प्राधिकरण (वाइटीडीए) की स्थापना की. मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन बनाए गए

30 मई, 2015
मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मंदिर और मंदिर नगर परिसर की आधारशिला रखी. वाटीडीए ने मंदिर और संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं को मंजूरी दी

541
प्रस्तर प्रतिमाएं मंदिर के शीर्ष किनारों और परिसर की शोभा बढ़ा रहीं

700 किलो
सोने से नए मुख्य गोपुरम पर दो मिलीमीटर मोटी कलई चढ़ाई जाएगी. असल गुफा मंदिर इसी के नीचे है

1,885
एकड़
है यदाद्रि मंदिर नगर योजना का कुल इलाका

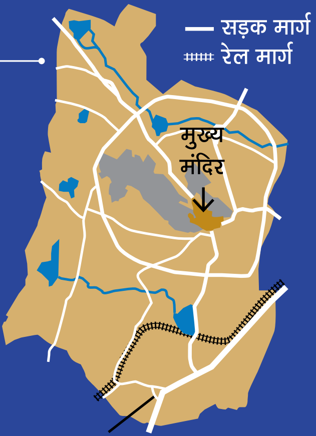

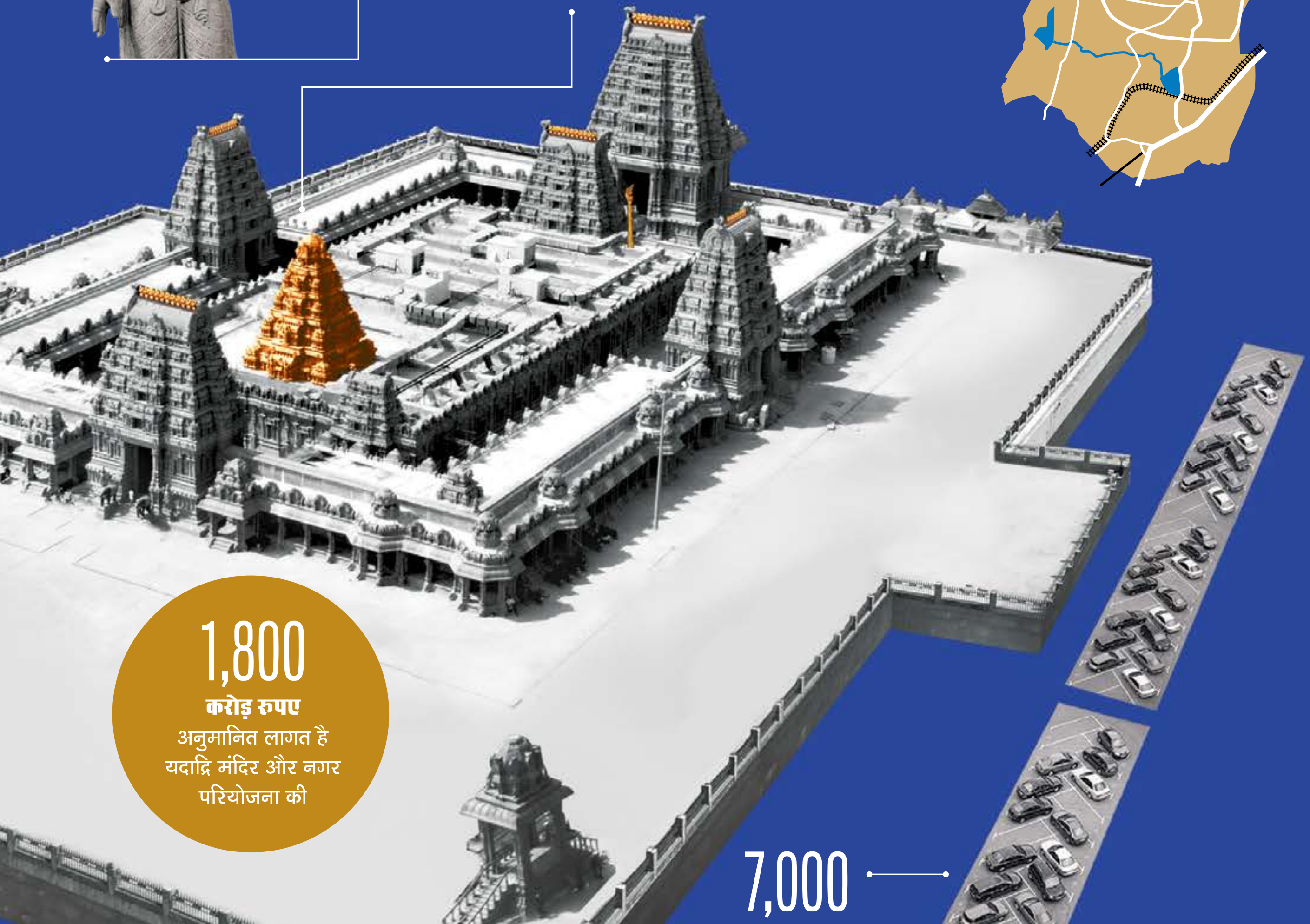

1,800
करोड़ रुपए
अनुमानित लागत है यदाद्रि मंदिर और नगर परियोजना की

7,000
पार्किंग की जगहों पर बस, कार और दूसरे वाहन खड़े किए जा सकेंगे

21,780
वर्ग गज
विस्तार है मंदिर का

7 दिसंबर, 2015
सरकार ने परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए सलाह, डिजाइन की मंजूरी और ठेकेदारों के चयन की खातिर पांच सदस्यीय अधिकारप्राप्त तकनीकी समिति बनाई

21 अप्रैल, 2016
गुफा मंदिर के जैसा ही अस्थायी मंदिर बालालयम बनकर खुलने के बाद उसमें पूजा-अर्चना शुरू हो जाने पर मूल गुफा मंदिर को बंद किया गया

11 अक्तूबर, 2016
पहले स्तंभ की आधारशिला रखी गई, नए मंदिर का काम शुरू

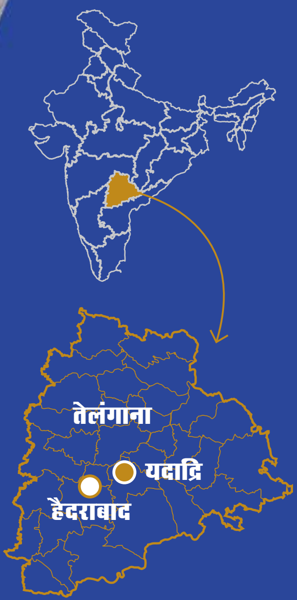

1,000 साल से ज्यादा टिकने वाली निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा सके. निर्माण इस लिहाज से अनूठा है कि हमने सीमेंट और कंक्रीट सरीखी आधुनिक सामग्री के बजाए केवल कृष्णशिला (काले ग्रेनाइट) का इस्तेमाल किया है, जो तेलंगाना के काकतिया साम्राज्य के समय मंदिरों के स्थापत्य में इस्तेमाल की जाती थी.'' ग्रेनाइट आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले की गुरिजेपल्ली खदानों से मंगवाया गया है और आइआइटी मद्रास तथा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री केंद्र ने इसकी मजबूती और टिकाऊपन की तस्दीक की है.

मंदिर के वास्तुकार और कला निर्देशक बी. आनंदसाई ने देश भर के 60 से ज्यादा मंदिरों का दौरा करके मंदिर स्थापत्य के समूचे काम को अंतिम रूप दिया. इनमें भीतरी और बाहरी प्रकारम (अहाते की दीवारें), नक्काशीदार पत्थरों के स्तंभ, संबद्ध मंदिर, देवी-देवताओं और आलवारों (वैष्णव पंथ के संतों) की मूर्तियां शामिल हैं. नरसिंह स्वामी के मूल गुफा मंदिर और हनुमान की नक्काशी वाली चट्टान के साथ जरा छेड़छाड़ नहीं की गई. बाकी सब नया है. सबसे ऊंचा गुंबद सप्ततला महाराजागोपुरम सात मंजिला और 100 फुट ऊंचा है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है. इसके अलावा छह और गुंबद मंदिर की भव्यता बढ़ा रहे हैं. गोपुरम आम तौर पर छत तक पत्थरों से ढाले जाते हैं और उसके ऊपर ईंट का इस्तेमाल किया जाता है. यदाद्रि में बिल्कुल शीर्ष तक गोपुरम के निर्माण में काले स्फटिक पत्थर या ग्रेनाइट का इस्तेमाल साफ दिखाई देता है. मंदिर की अहम खासियतें हैं सप्ततला महाराजागोपुरम, गुफा का 202 फुट लंबा और 103 फुट चौड़ा मुखमंडपम जिसकी 35 फुट ऊंची छत झाड़-फानूस से सुसज्जित है, कांच के कक्ष अष्टभुजी प्रकारम और इसके अलावा काले स्फटिक पत्थरों की मूर्तियां जिनमें पूर्वी और पश्चिमी गोपुरम पर पत्थर में उत्कीर्ण सात फुट दो इंच के सिंह और उत्तर तथा दक्षिण गोपुरम पर पांच फुट आठ इंच के सिंह शामिल हैं.

आनंदसाई कहते हैं, ''मूर्तिशिल्पों का यह संयोजन पत्थरों में तराशी गई कविता है. इस मंदिर को आध्यात्मिक और वास्तुशिल्प के लिहाज से भव्य बनाने के लिए हमने कई विशिष्ट शैलियों और परंपराओं को मिलाया है. इनमें मुख्य मंदिर में चालुक्य शैली, मुखमंडपम और 12 आलवारों में काकतिया शैली, बाहरी प्रकारम में पल्लव रूपरेखा की झलक, द्रविड़ शैली में गोपुरम और साथ ही कुछ में जैन शैली से प्रेरित प्रतिमाएं और पंक्तिरेखाएं गुंथी हैं.''

शिल्पकारों ने काले स्फटिक पत्थरों के अलावा पारंपरिक जोड़ सामग्री का इस्तेमाल किया है ताकि मंदिर का ढांचा सदियों तक टिका रहे. ग्रेनाइट के पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट के बजाए चूने के गारे, कारक्कया (भारतीय आलूबुखारा), गुड़, ऐलोवेरा (ग्वारपाठा) और जूट के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है. यह मिश्रण ''सभी मौसमों में टिकाऊ'' माना जाता है. आनंदसाई कहते हैं, ''मूर्तिशिल्पों में सदियों तक न दरार आएगी और न ही पिघलेंगी, क्योंकि यह मिश्रण गोंद है.'' तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के करीब 500 मूर्तिकारों और इतने ही सहायकों ने दो साल की कड़ी मेहनत से ग्रेनाइट पत्थरों को उपयुक्त आकृतियों में काटा-तराशा है. यह काम जोखिमों से बेपरवाह लगातार चलता रहा (कम से कम दो दर्जन कामगार गंभीर रूप से चोटिल हुए). प्रधान संगतराश आनंदचारी वेलु कहते हैं, ''हमने पक्का किया कि हम सभी चरणों में अगम शास्त्र के दिशानिर्देशों का पालन करें.''

केसीआर के कुछ विरोधियों ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि कुछ स्तंभों पर उकेरी गई मूर्तियां उनसे मिलती-जुलती हैं और उनके समर्थकों की शह पर इस तरह का उत्कीर्णन करवाया गया है

अगम शास्त्र में मंदिर निर्माण, मूर्ति स्थापना और पूजा-उपासना के रीति-रिवाजों के नियम और बारीकियां बताई गई हैं. वेलु और वाइटीडीए परियोजना में उनके पूर्ववर्ती एस. सुंदर राजन ने किसी विवाद में पड़ने से बचने के लिए इसका पूरी निष्ठा से पालन किया. तो भी एक मौका ऐसा आया जब केसीआर के विरोधियों ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि स्तंभों में कुछ आकृतियां उनसे मिलती-जुलती हैं और कथित तौर पर उनके समर्थकों के कहने पर उत्कीर्ण की गई हैं. आलोचना के और भी मुद्दे हैं. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दसोजू श्रवण कहते हैं, ''मंदिर तो अयोध्या में और दूसरी जगहों पर भी बन रहे हैं लेकिन चंदे से, सरकार के पैसे से नहीं. जनता के पैसे का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल वगैरह बनवाने में होना चाहिए. फिल्म के सेट जैसी इस रचना से लोग भले चमत्कृत हों लेकिन यह है केसीआर की आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए. उन्हें ऐतिहासिक सार्वजनिक स्थलों को विकृत करने का शौक है...'वास्तु' के अनुरूप नई इमारत की तामीर के लिए उन्होंने निजाम के दौर का राज्य सचिवालय ध्वस्त करवा डाला. केसीआर चाहते हैं कि उनके कल्वकुंतल परिवार को यदाद्रि के लिए उसी तरह याद रखा जाए जैसा कि तिरुमला के लिए चोल याद किए जाते हैं.''

गर्भगृह को जस का तस रखा गया है. इसमें अकेली सजावट 48 फुट का पांच-मंजिला विमान गोपुरम है जिस पर आने वाले सालों में सोने की परत चढ़ाई जाएगी. मंदिर के संरक्षित स्मारकों की सूची में न होने के तर्क के साथ अधिकारी इस बदलाव को तर्कसंगत बताते हैं. पर कई आलोचक इससे सहमत नहीं. तेलंगाना की इनटैक की सह-संयोजक अनुराधा रेड्डी के शब्दों में, ''यदाद्रि भले ही संरक्षित स्मारकों में न हो लेकिन पहाड़ी पर विस्फोट कर करके एक खूबसूरत गुफा मंदिर को विकृत कर दिया गया. और वहां जिसकी तामीर की गई वह काकतिया प्रदेश में होने के बावजूद उसका आंचलिक धरोहर से कोई तादात्म्य ही नहीं.''

अब तक खर्च 852 करोड़ रुपए में से 248 करोड़ रुपए मंदिर पर और बाकी जमीन के अधिग्रहण तथा बुनियादी ढांचे पर खर्च हुए हैं. इसमें मंदिर को घेरने वाली पहाड़ियों के बीच सुचारु आवाजाही के लिए चार लेन की सड़क, छह लेन की यदाद्रि की बाहरी रिंग रोड और आसपास का सुंदरीकरण शामिल है.

केसीआर चाहते हैं कि यदाद्रि पहले दिन से ही लोगों को अपने सौंदर्य से आकर्षित कर ले. मंदिर की पहाड़ी ढलान पर शहर आकार ग्रहण कर रहा है. हालांकि यह मंदिर के निर्माण सरीखी तेज रफ्तार से नहीं बन रहा है. एक कृत्रिम झील के साथ-साथ मैरिज हॉल, फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बस टर्मिनल बन रहे हैं. इसके अलावा 25 एकड़ के बगीचे में यहां मंदिर की पूजा में लगने वाले फूल उगाए जाएंगे. उत्सवों की शुरुआत के लिए वे मंदिर के उद्घाटन के मौके पर महा सुदर्शन यज्ञम (यज्ञों की जननी) की योजना बना रहे हैं. इस मौके पर वैष्णव पंथ से जुड़े देश भर के आध्यात्मिक नेताओं को बुलाया जाएगा. ■

किताबें

एक चेहरा जो पूरे आदमी का है

विनोद भारद्वाज

इस ग्रंथावली पर लिखते हुए मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मेरा सुदामा पांडेय धूमिल से अच्छा-खासा परिचय सिर्फ अट्ठारह साल की उम्र में हो गया था. वे मुझसे बारह साल बड़े थे पर उन दिनों वे सहारनपुर से अपना ट्रांसफर कराने के लिए बेचैन थे. वे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आइटीआइ) में सुपरवाइजर के रूप में काम करते थे. बनारस उनका घर था. ट्रांसफर कराने के लिए वे उन दिनों बहुत परेशान थे. यह 1967 की बात है. मैं अपने समय की चर्चित लघु पत्रिका *आरंभ* का एक संपादक था. नरेश सक्सेना और जयकृष्ण जैसे वरिष्ठ साहित्यकार और कलाकार पत्रिका के अन्य संपादक थे. यह कहना गलत न होगा कि धूमिल की अनेक सर्वश्रेष्ठ कविताओं के कारण भी *आरंभ* को इतनी चर्चा मिली. खास तौर पर *मोची राम* और *उस औरत की बग़ल में लेट कर* धूमिल की ट्रेंडसेटिंग कविताएं हैं. ये *आरंभ* में ही छपी थीं.

आरंभ का पहला अंक अकाल पर केंद्रित था. उसमें धूमिल की *अकाल दर्शन* और *गांव* ये दो कविताएं छपी थीं. ठाकुर प्रसाद सिंह से मुझे जानकारी मिली थी कि सहारनपुर में धूमिल नाम के एक कवि हैं जिन्होंने अकाल पर कुछ बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं. मैंने फौरन उनको खत लिखा. उनकी कविताएं उससे भी अधिक तेजी के साथ मुझे मिल गईं. संयोग से जिस दिन *आरंभ* का पहला अंक छप कर आया, उसके अगले दिन दोपहर लखनऊ के मेरे घर के गेट पर एक बड़ी-बड़ी शानदार मूंछों वाला व्यक्ति धोती-कुर्ते में अपने सामान के साथ खड़ा था. वे पूछ रहे थे, 'क्या विनोद जी घर पर हैं? मैं धूमिल हूं.' उन्होंने अपने आने की कोई खबर नहीं दी थी. मेरे घर की छत पर दो कमरे थे. मैंने वहीं धूमिल के रहने की व्यवस्था की. कुछ मैं घबराया हुआ भी था. नरेश जी ने *गांव* कविता की कुछ पंक्तियां काट दी थीं. उस कविता की अंतिम पंक्तियां बड़ी असरदार थीं. *घर-बाहर अवसाद है/ लगता है यह गांव नर्क का भोजपुरी अनुवाद है.*

मैंने कुछ डरते हुए धूमिल को *आरंभ* का वह अंक दिया. वे पन्ने पलटते रहे. मैंने कटी हुई पंक्तियों का भी धीरे से जिक्र किया. धूमिल उदारता से बोले, 'मैं तो इसे प्रिंटिंग मिस्टेक ही समझ रहा हूं.' मेरी घबराहट तब जा कर कम हुई. मालूम पड़ा, वे लखनऊ अपने ट्रांसफर के सिलसिले में आए हैं. बनारस यानी घर जाने के लिए वे परेशान थे.

मेरे घर की काम करने वाली लड़की शीला ने मेरी मां से कहा, 'ये साहेब विनोद के दोस्त कैसे हो सकते हैं? देखने में तो उसके चाचा लगते हैं.' धूमिल सब को खुश रखने की कला जानते थे. वे कई बार मेरे घर रहे. 1967-69 के समय में सहारनपुर और बनारस से उन्होंने मुझे करीब तीस चिट्ठियां लिखीं. ग्रंथावली के तीसरे खंड में धूमिल की 60 के आसपास चिट्ठियां शामिल हैं जिनमें से आधी मेरे नाम हैं. पर उन चिट्ठियों की एक छोटी-सी भूमिका जरूरी थी. 1975 में धूमिल का ब्रेन कैंसर से 39 साल की उम्र में असमय निधन हो गया था. नामवर सिंह *आलोचना* पत्रिका के संपादक थे और विष्णु खरे सह संपादक. खरे के कहने पर ही मैंने ये सारी चिट्ठियां एक छोटे-से नोट के साथ छपने के लिए दे दी थीं. उस दौर में हिंदी लेखक महानगरों की कॉफी कल्चर के धुएं में खोया था. धूमिल इस संस्कृति के खिलाफ थे. वे साइकिल चलाने वाली गांव की संस्कृति में रचे-बसे थे. *जब मैं साइकिल पर सवार होता हूं, मेरा दिमाग साइकिल की तीलियों की तरह चलता है.*

रत्नशंकर धूमिल के सुपुत्र हैं, उनके निधन के समय वे छोटे थे. ग्रंथावली कई साल पहले ही छपने वाली थी. इसका प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है. मैं डायरी, पत्र लेखन को काफी महत्व देता हूं. डायरी में एक जगह अशोक वाजपेयी और विष्णु खरे की आलोचक के रूप में तुलना भी की गयी है.

आरंभ के जनवरी-अप्रैल 1968 के अंक में *मोची राम* कविता का प्रकाशन एक बड़ी साहित्यिक घटना थी. उस कविता के साथ धूमिल की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी छपी थी: ''प्रयत्न यह रहा है कि भीड़ से अलग, आदमी के रोजमर्रा के कामों, और पेशे के आधार पर बनी हुई भाषा की मान्यता के खिलाफ कुछ लिखूं. मुझे अक्सर लगा है कि सही आदमी वे हैं, जो अस्तित्व में नहीं हैं. (एक चेहरा, जो कि पूरे आदमी का है, किंतु वह मेरा नहीं, मेरी कमी का है.)

आज लिखते समय बरसों पुरानी याद आ रही है जब धूमिल चौकड़ी मार कर बैठे *मोची राम* का पाठ करने से पहले बोले, 'त्रिलोचन को बनारस में यह कविता सुनाने के बाद तुम मेरे दूसरे श्रोता हो. एक खत में उन्होंने लिखा है, *आरंभ* से जुड़ कर मुझे लग रहा है कि पहली बार सही लोगों से जुड़ा हूं.'

मैं एक बार लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भी धूमिल से उनके अंतिम दिनों में मिला था. एक ताकतवर आवाज धीमी और कमजोर हो गई थी. हिंदी का यह बहुत बड़ा नुकसान था. ■

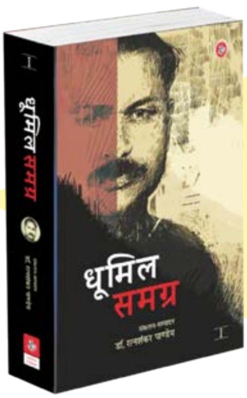

धूमिल ग्रंथावली
(तीन खंड)
संकलन-संपादनः
रत्नशंकर पांडेय
प्रकाशकः **राजकमल प्रकाशन, नईदिल्ली**
कीमतः 999 रुपए

आज लिखते समय बरसों पुरानी याद आ रही है जब धूमिल चौकड़ी मारकर बैठे मोची राम (कविता) का पाठ करने से पहले बोले, 'त्रिलोचन को बनारस में यह कविता सुनाने के बाद तुम मेरे दूसरे श्रोता हो.'

सोशल मीडिया पर कविता का समां

नवीन कुमार

बीते एक-डेढ़ साल में कोरोना की वजह से देश-दुनिया ने क्या-क्या नहीं देखा-भोगा. लॉकडाउन, लाखों मजदूरों का पलायन, बेरोजगारी, दूसरी लहर में ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ते लोग, नदियों में बहाए जाते और उनके किनारे रेत में दफनाए जाते कोरोना पीड़ितों के शव. साहित्य चूंकि समाज का दर्पण है इसलिए इन त्रासदियों को खासकर कवियों-गीतकारों ने अपने भाव और शब्दावली में पिरोकर आम लोगों तक पहुंचाए. पर उससे भी अहम बात यह थी कि सिनेमा और रंगमंच से जुड़े कुछ अहम नामों ने इन्हें स्वर देकर सोशल मीडिया के जरिए इनकी पहुंच को कई गुना बढ़ा दिया.

फेसबुक हो या यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हर प्लेटफॉर्म पर इनका दायरा तेजी से बढ़ रहा है. छंदों के बंधनों से आजाद, आज के मौके की कविताओं को आवाज देने वाले कलाकार न तो कवि हैं और न ही गायक. इनके पाठ का रसास्वादन करने वाले आज के युवाओं में बड़ा वर्ग ऐसा है, जिसका साहित्य से कोई खास वास्ता नहीं. पाठकर्ता कलाकार भी इस तरह की हौसलाअफजाई की वजह से रोज नए कवियों की नई मौजूं कविताएं खोज-खोजकर ला रहे हैं, जिनमें मौजूदा दौर के सामाजिक और राजनीतिक हालात को उकेरने वाली तल्ख इमेजरी होती है.

सिनेमा की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले मनीष गुप्ता ने कुछेक साल पहले यूट्यूब पर *हिंदी कविता* नाम से एक चैनल शुरू किया था. इसमें मनोज वाजपेयी, सौरभ शुक्ल, राजेंद्र गुप्ता, पीयूष मिश्र, सुरेखा सीकरी, स्वरा भास्कर और मोहम्मद जीशान अयूब जैसे कलाकारों ने रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार जैसे हिंदी के शीर्ष कवियों की कविताओं का पाठ किया. इसमें कविता भाव के अनुरूप दृश्यों और संगीत के साथ पश की जाती रही है. प्रयोग खासा चर्चित हुआ. फिर उर्दू स्टुडियो आया जिसमें नसीरुद्दीन शाह सरीखे ऐक्टर जुड़े और मिर्जा गालिब, कैफी आजमी, मीर तकी मीर, साहिर लुधियानवी जैसे शायरों को अपनी आवाज में पेश किया.

हिंदी कविता चैनल का हिस्सा रह चुके ऐक्टर राजेंद्र गुप्ता अब अपने यूट्यूब चैनल *राजेंद्र गुप्ता रिसाइट्स* पर बिना तामझाम के रोज एक कविता सुना रहे हैं. उन्हीं के शब्दों में, ''आज की कविता छंद वाली नहीं, कंटेंट वाली है. यही कारण है कि इसकी ऑडिएंस बढ़ती जा रही है. एक नया वर्ग तैयार हो रहा है जिसका लिखने-पढ़ने से खास ताल्लुक नहीं लेकिन साहित्य से वह जुड़ रहा है.'' स्वांत:सुखाय है और अव्यावसायिक तौर पर कविता पाठ कर रहे गुप्ता इससे पहले फेसबुक और एक साहित्यिक संस्था चौपाल पर कहानी के साथ कविता पाठ करते थे. बीते दो साल में वे करीब 400 कविताओं का पाठ कर चुके हैं.

लेकिन इन प्रयोगों को ज्यादा ताकत दी है महामारी के विविध पहलुओं को लेकर लिखी जा रही कविताओं के पाठ ने. गुप्ता कहते भी हैं, ''पिछले लॉकडाउन में किस तरह से लाखों मजदूर शहर छोड़कर अपने गांवों के लिए निकल पड़े थे. फिर अब ऑक्सीजन के अभाव में अनगिनत मौतें. इससे पहले शाहीनबाग, एनआरसी जैसे मुद्दे. पिछले डेढ़-दो साल से जिस तरह के राजनीतिक-सामाजिक उथल-पुथल वाले हालात रहे हैं, वे कवियों को कैसे उद्वेलित न करेंगे.'' पाठ के लिए कविताएं चुनने में भी उन्होंने कद से ज्यादा कविता के असर को देखा. एक ओर उन्होंने साहिर, मजरूह, दिनकर, गुलजार, नरेश सक्सेना और कुंवर नारायण को पढ़ा तो दूसरी ओर संजय कुंदन, अनिल करमेले, प्रेम रंजन अनिमेष, हूबनाथ पांडेय, विजय कुमार, देवेंद्र आर्य, मणि मोहन, अमिताभ मिश्र, फरीद खान जैसे 40-50 समकालीन और नए कवियों की रचनाएं भी पढ़ीं. बरेली के चिकित्सक-नाटककार डॉ. ब्रजेश्वर सिंह की *वरवर राव* और *किसान* कविता पसंद आई तो उसे भी स्वर दिया, जिनको अब तक 10,000 से ज्यादा श्रोता

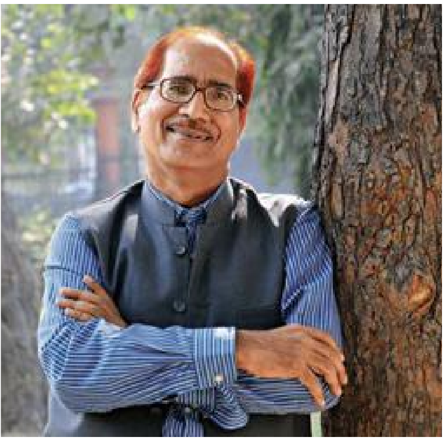

सोशल मीडिया

(बाएं से क्रमशः) सौरभ शुक्ल, राजेंद्र गुप्ता, ओम निश्चल और जीशान अयूब आदि ने मौजूदा दौर में कविता को सोशल मीडिया के जरिए गैरपारंपरिक श्रोताओं के एक बड़े तबके तक पहुंचाया

सुन चुके हैं. वे साफ कहते हैं, ''जो कविता मुझे झंझोड़ती है, आज के हालात को सशक्त ढंग से बयां करती है और जिसके बारे में मुझे लगता है कि वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसे मैं बतौर अभिनेता पहुंचा रहा हूं.''

थिएटर और सिनेमा से नाता रखने वाले सौरभ शुक्ल ने भी *हिंदी कविता* के लिए भवानी प्रसाद मिश्र की 'सन्नाटा' कविता पढ़ी थी. फिर अभिनय में व्यस्तताओं के चलते पाठ का संयोग न बन सका. लेकिन उस प्रयोग के बारे में शुक्ल कहते हैं, ''उसमें मजेदार बात यह थी कि आप उसमें कविता पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि यह भी बताते थे कि वह कविता आखिर आपको क्यों पसंद है, उसकी खासियत क्या है? कविता में भाषा और विचार के अलावा भी काफी कुछ होता है जो आपको आकर्षित कर सकता है.'' उनका मानना है कि कविता या कोई भी कला अपने आपमें कोई एक अलग चीज न होकर अपने समय का आईना होती है. आज की बहुत-सी कविताओं में आपको वे सवाल मिल जाएंगे जो आपके भीतर उठ रहे हैं. लोग उन्हें पढ़ेंगे-सुनेंगे तो स्वाभाविक तौर पर अपने को उनसे जोड़ेंगे.''

गुप्ता और शुक्ल की तरह युवा अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब भी कविता लिखते नहीं बल्कि पढ़ते हैं. *हिंदी कविता* चैनल पर उन्होंने नजीर अकबराबादी की दो कविताएं *बंजारानामा* और *दीवाली* पढ़ी थी. वे इस पर मिले ऑनलाइन रिस्पांस से चकित थे. उन्हें लगा कि एक बड़ा तबका है जो कविताएं सुनना चाहता है ''पर हम ही शायद उन तक नहीं पहुंच पा रहे.'' जीशान नए कवियों के मुरीद हैं. सीएए विरोधी आंदोलन के समय सुमित सपरा और आमिर अजीज जैसे युवा कवियों का उन्होंने खूब हौसला बढ़ाया था. रमाशंकर यादव विद्रोही की एक कविता उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली है: *इतिहास में वो पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया था?* ऐसे कवियों को वे हिंदी साहित्य के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी मानते हैं. जीशान के शब्दों में, ''मेरे पढ़ने का कोई पैटर्न नहीं है. कोई कविता सामने आती है, समाज के हालात को लेकर उसमें व्यक्त भाव अच्छे लगते हैं तो उसे पढ़ देता हूं. अब तो कविताओं के लिए बाकायदा दृश्य शूट कर सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है. मैं भी इंस्टाग्राम पर डालता हूं. कोई नाम नहीं रखा है. असली मजा शब्दों का है, मैं किस तरह पढ़ रहा हूं, हाथ में किताब लेके.''

सोशल मीडिया पर कविता की तरह गीत भी लोकप्रिय हो रहे हैं. गीत को इस मीडिया से जोड़ने का काम करने वालों में कवि-गीतकार, आलोचक ओम निश्चल भी हैं. उनका आकलन है कि कविता और शायरी अब गांवों तक भी पहुंच रही है. ''सोशल मीडिया के प्लेटफार्म ने सब कुछ आसान कर दिया है. फेसबुक हो या यूट्यूब, उस पर आप अपने लिखे हुए को छापकर उसे दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा सकते हैं. इसी के तहत नई कविताएं और गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोता इससे लोग जुड़ रहे हैं.'' निश्चल का मानना है कि सोशल मीडिया वर्तमान समय की तस्वीर पेश करता है. सच को दिखाने वाले नए कवि और गीतकार उभरकर आ रहे हैं. वे *शववाहिनी गंगा* कविता की मिसाल देते हैं, ''यह कविता इस तरह से वायरल हुई कि कई भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है. इसका कथ्य प्रबल है. गंगा में अस्थि विसर्जन होता है. लेकिन शव विसर्जन के बाद इसे कोई शव वाहिनी गंगा कहेगा तो यह सभ्यता पर सवाल है.'' उन्होंने *साहित्य तक* चैनल के लिए *लाश नदियों में बहाते जाइये, उड़न खटोला बैठ फकीरी भूल गया बड़बोला, इस शहर में है अब दाना पानी नहीं, देश बचा लो जान बचा लो* तथा *अमर उजाला* के काव्य चैनल के लिए अनेक पॉपुलर गीत लिखे और गाए हैं.

उन्होंने खुद एक गीत लिखा और गाया है: *प्रवासी नहीं हैं प्रवासी नहीं हैं.* उनका अपना यूट्यूब चैनल है *ओम निश्चल* नाम से जिस पर उन्होंने नामचीन कवियों और गीतकारों की रचनाओं को अपनी आवाज में डाला है. वे नए कवियों और गीतकारों को भी तलाशते रहते हैं और उनकी कविताओं और गीतों को अपने चैनल पर पेश करते हैं. सूर्यभानु गुप्त, प्रभात पांडेय, यश मालवीय, विनोद श्रीवास्तव, अर्चना उर्वशी, प्राची सिंह, डॉ. यासमीन मूमल, रणवीर दिनेश आदि के अलावा नागेंद्र अनुज, राहुल शिवाय, पंकज शर्मा, प्रदीप शुक्ल सरीखे नई पीढ़ी के कवियों की रचनाओं का भी उन्होंने पाठ किया है. ■

सवाल+जवाब

शेष आकांक्षा गुरुकुल की

विख्यात शास्त्रीय-उपशास्त्रीय गायक पद्मविभूषण **पं. छन्नूलाल मिश्र** कोरोना की दूसरी लहर में पत्नी और बेटी की मृत्यु, बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के सवाल और बनारस में गुरुकुल की योजना पर

समीर नंदन गुप्ता

● कोरोना की दूसरी लहर में आपको पत्नी और बेटी की मृत्यु के त्रासद अनुभव से गुजरना पड़ा. हमने एक विख्यात गायक और परिजनों को न्याय की गुहार लगाते देखा.
चार दिनों के भीतर ही पत्नी और बेटी की मौत हो गई. उनकी याद बहुत आती है लेकिन क्या कर सकते हैं? प्रभु की इच्छा समझकर बर्दाश्त करते हैं. शरीर तो अब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन मन अभी भी बहुत दुखी है.

● आप वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री के प्रस्तावक भी रहे हैं, दूसरी बेटी ने चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल भी उठाए थे.
जी सबसे कहा है. जांच भी हो रही है. जांच करने वाले घर भी आए थे.

● *खेलैं मसाने में होरी दिगंबर...* गाने वाले को भी श्मशान की तस्वीरों ने काफी विचलित किया होगा?
निश्चित रूप से विचलित किया. बहुत सारे लोग इस दौरान हमसे बिछड़ गए. कितने ही कलाकारों का निधन हो गया. क्या कहें, ''होइहि सोइ जो राम रचि राखा...''

● संगीत समारोहों के बंद होने से कलाकारों के सामने आर्थिक संकट भी है. क्या कहेंगे आप इस पर?
डेढ़ साल से कार्यक्रम बंद हैं. कहीं कुछ नहीं हो रहा. हम तो किसी को सिखा भी नहीं पा रहे क्योंकि हम ऑनलाइन बात कर नहीं पाते. लेकिन जीविकोपार्जन, परवरिश के लिए कुछ-न-कुछ तो होना चाहिए. बड़ी चिंता होती है कि जीविका के लिए क्या करें? जीवन की तमाम जरूरतें तो रहती ही हैं लेकिन किसी से कुछ मांग भी तो नहीं सकते—*प्रेम घटे कछु मांगत तें, मान घटे पर गेह के जाए...*बहुत सारे कलाकारों का यही हाल है. इस उम्र में भी हमारे साथ कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है.

● 85 की उम्र है, कोई इच्छा जो अभी पूरी होनी बाकी हो?
सम्मान, पुरस्कार तो सब मिल चुके हैं, बहुत सारी जगहों पर कार्यक्रम भी किए लेकिन एक इच्छा मन में है. मेरा छोटा-सा घर है. यहां ज्यादा लोगों को बुलाकर सिखाया नहीं जा सकता. तो चाहता हूं कि एक गुरुकुल बना सकूं. ऐसा लगता है कि चार-पांच साल जब तक हूं, जो भी विद्या मेरे पास है, अधिक से अधिक बच्चों को सिखा सकूं, उन्हें दान कर सकूं. नहीं तो मेरी कला मेरे साथ ही चली जाएगी. इस कला का प्रचार-प्रसार जरूरी है. गुरुकुल के लिए सरकार की मदद की दरकार होगी, कह रहा हूं सबसे.

—आलोक पराड़कर

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

इंडिया टुडे
कितनी सुरक्षित?
कितनी कारगर?
इंडिया टुडे
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 25% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	3 वर्ष	156	~~6240~~	4680	25%
☐	2 वर्ष	104	~~4160~~	3330	20%
☐	1 वर्ष	52	~~2080~~	1770	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.......................है और इसे दिनांक................. को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में .... (बैंक का नाम)........................रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम.. पता...

.... शहर..................... राज्य..................... पिन......................

मोबाइल.. ईमेल...

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
www.indiatoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

IndiaContent

SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE